हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 नवम्बर, 1973

खंड 2, अंक 4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बृहस्पतिवार, 15 नवम्बर, 1973

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4) 1
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4) 17
अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 513 पर संव्यवस्था (रूलिंग)	(4) 21
कृषि मंत्री द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (संख्या) पर वक्तव्य	(4) 22
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण (चौधरी प्रताप सिंह दौलता द्वारा)	(4) 27
हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 31.12.1972 तक लिए गए ऋण दर्शाने वाला विवरण, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का वार्षिक वित विवरण (बजट अनुमान, 1972–73) (संशोधित अनुमान 1971–72), हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के लेखों का चतुर्थ वार्षिक विवरण 1970–71, तथा हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन पर खर्चा।	(4) 29
हरियाणा वित–निगम के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाे पर चर्चा	(4) 62
परिशिष्ट	i-viii

हरियाणा विधान सभा

वृहसपतिवार, 15 नवम्बर, 1973

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़, में. प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री बनारसी दास गुप्त) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Plying of Buses of Haryana Roadways

*** 439. Sh. K.N. Gulati:** Will the Minister of Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for plying uses from Sonepat to Faridabad and Bhadurgarh to Faridabad?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): बल्लभगढ़–फरीदाबाद–सोनीपत तथा बल्लभगढ़–फरीदाबाद–बहादुरगढ़ मार्गो पर बस सेवाएं क्रमशः 10 अक्तुबर, 1973 तथा 3 अक्तुबर, 1973 से आरम्भ कर दी गई हैं।

श्री के. एन. गुलाटी: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी बसे चलायी गयी हैं?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: अभी तो एक–एक ही बस चलायी गयी है। एक सुबह बल्लभगढ से सोनीपत के लिए चलती है वही

शाम को वापिस आती है। इसी तरह से बहादुरगढ से फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के लिए भी चलाई गयी है।

श्री के. एन. गुलाटीः क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगें कि फरीदाबाद से दिल्ली तक जो डी.टी.यू. की बहुत बसे चलती है उनसे दिल्ली सरकार को बड़ी इन्कम होती है, क्या हरियाण्ण सरकार भी वहां की इन्कम को ध्यान मे रखते हुए हरियाणा रोड़वेज की बसे चलाएगी?

परिवहन मंत्री (कर्नल महा सिंह): दिल्ली से फरीदाबाद रूट के लिए हमारा दिल्ली परिवहन से बहुत पुराना एग्रीमैंट हुआ हैं उसके मुताबिक हमें दिल्ली को कुछ किलोमीटर देने पड़ते हैं। कोशिश की जा रही है कि उनसे बातचीत करें। हम भी चाहते है कि वह रूट भी शामिल होना चाहिए और उस पर हरियाणा रोड़वेज की बसे चलनी चाहिए। आपके कहने पर ही हमने सोनीपत से फरीदाबाद और फरीदाबाद से बहादूरगढ़ के लिए बसे चली दी है ताकि आने वाले को दिक्कत न हों।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताएगें कि जिस तरह से रात को चण्डीगढ़ से डायरैक्ट बसें दिल्ली के लिए चलती है, क्या इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट से भी रात की सर्विस जारी करने का विचार है?

कर्नल महा सिंहः हमने आलरेडी जारी कर रखी है। नारनौल से रात को बस चलती है, भिवानी से भी शुरू कर दी है।

भिवानी वाली रोहतक की सवारियां लेकर आती है। इसी तरह से गुड़गांव से दो–तीन बसे गुजरती है। एक फिरोजपुर झिरका से आती है और दूसरी रेवाड़ी से आती है। बाकी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर रास्ते मे ही पड़ते है। जो नजदीक डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए जरूरत नही समझी गयी।

Expenditure incurred of Minister

***450 Chaudhri Mehar Chand:** Will the Chief Minister be pleased to State-

(a) the average monthly expenditure incurred by the State Government during the period From 1st April, 1973 to 30th June, 1973 on the pay and allowances of each Minister including T.A. And D.A. free transport, free house, free electricity and other amenities; and

(b) the amount of monthly house rent, if any, given to a Minister in lieu of free residence during the period referred to in part (a) above?

Chief Minister (Chudhri Bansi Lal): (a) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House (Annexure 'A')

(b) Nil.

STATEMENT

ANNECURE 'A'

Sr.	Name & Dign. of the Minister	Pay	T.A./ D.A.	Medical Charges	Free Transport	Free House	Free Electricity	Other Amenities		
								Water Charges	Chowkidar/ Mali	T. Phone Charges
1	Sh. Bansi Lal, C.M.	2,000.00	676.67	22.91	1,142.66	Nil*	452.56	126.17	Nil	3,825.20
2	Sh. K.L. Poswal, H.M.	1,500.00	760.00	9.77	1,601.07	Nil*	314.26	53.56	Nil	1,975.76
3	Sh. Bhajan Lal, A.M.	1,500.00	536.67	57.02	1,638.20	Nil*	60.83	59.17	Nil	2,652.55
4	Sh. Shyam Chand, D.M,	1,500.00	770.00	-	1,410.41	900.00	58.96	30.53	291.00	2,417.18
5	Sh. R.S.C. Mittal, F.M.	1,500.00	420.00	-	2,033.90	Nil*	86.36	80.23	Nil	898.27
6	Sh. Maru Singh, E.M.	1,500.00	583.34	19.66	910.13	1,100.00	254.99	12.67	291.00	678.75

7	Sh. Harpal Singh, I.M.	1,500.00	676.67	-	1,033.93	975.00	243.85	23.80	291.00	2,302.25
8	Sh. Chiranji Lal, R.M.	1,500.00	1226.25	-	994.18	1,200.00	133.23	97.67	291.00	1,425.73
9	Sh. Maha Singh. T. M.	1,500.00	793.33	69.68	891.57	1,200.00	14.33	33.20	291.00	1,499.40
10	Smt. Sharda Rani, M.H.H.	1,500.00	443.33	42.03	843.52	900.00	148.81	12.67	291.00	1,448.67
11	Smt. Chandrawati, M.R.P.	1,500.00	513.33	19.58	963.42	Nil*	142.97	49.79	Nil	1,229.80
12	Smt. Parsanni Devi, M.E.T.	1,500.00	735.00	-	1,136.70	Nil*	198.39	18.33	Nil	1,866.70
13	Sh. Goverdhan Dass, M.C.L.	1,500.00	793.33	-	898.04	Nil*	74.19	12.77	Nil	1,773.50
14	Sh. Harmohinder Singh Chatha, M.I.P.	1,500.00	771.25	55.61	969.30	Nil*	99.97	21.02	Nil	1,073.75

J.B.T. and B.A., B.Ed. Teachers

***462. Chaudhri Dal Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that some J.B.T. and B.A. B.Ed. teachers have been appointed in the schools on adhoc basis in Jind Sub-Division;

(b) if so, the number of such J.B.T. and B.A., B.Ed. Teachers who are serving in the said schools at present, separately; and

(c) the time by which permanent teachers will be appointed in the schools referred to in part (a) above in place of adhoc appointees.

शिक्षा मंत्री एंव परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): (ए): जी हां।

(बी) जे.बी.टी. की संख्या 176 है तथा बी.ए.–बी.एड. की संख्या 91 है।

(सी) ज्यों ही एस.एस.एस. बोर्ड से उम्मीदवारों की सिफारिश की गई।

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे की क्या कारण है कि अभी तक एडहोक बेसिंज पर टीचर्ज लगा रखे है? जैसा कि आपने पार्ट (सी) के जवाब मे बताया है कि जब भी सबौरडिनेट सर्विसिज सिलैक्शन से कैन्डीडेट्स मिल

जायेगें तो लगा दिये जाऐगें लेकिन स्पीकर साहब, बोर्ड ने तो बी. ए.–बी.एड. कैन्डीडेट्स रिमैन्ड करके भेजे हुए है, उनको क्यो नही लगाया जाता है, उनका क्या कारण है?

शिक्षा मंत्री (श्री मांडू सिंह मलिक): स्पीकर साहब, यह गल्त बात है। जितने भी एस.एस.एस. बोर्ड ने सिलैक्ट करके भेजे थे वे हमने सब लगा दिए हैं। जब और भेज देगा तो लगा दिये जायेगें।

De-Luxe Buses

*** 486. Sh. Girish Chander Joshi:** Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) the total number of De-Luxe buses of Haryana Roadways plying in the state together with the routes thereof; and

(b) the total number of De-Luxe buses during the year 1973-73?

शिक्षा मंत्री परिवहन मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क)	(i) हरियाणा राज्य डिल्कस बसों की संख्या	18	
	(ii) जिस क्षेत्र मे डिलक्स बसों की सेवा उपल्बध है।	1. अम्बाला छावनी – शिमला	1

		2. देहली – शिमला	1
		3. देहली – चण्डीगढ़	1
		4. देहली – जगाधरी	1
		5. देहली – जयपुर	1
		6. सिरसा – देहली	1
(ख)	साल 1973–73 मे बढाई गई डिलक्स बसों की संख्या	शून्य	

High Yield Variety Programme

***495. Sh. Gauri Shankar:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether the Government proposes to bring more area under the High Yield variety Programme; If so, the area proposed to be covered under this programme together with the cost to be incurred theron?

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल): (हां)

(ख)	क्षेत्र (हैक्टेयर)	वर्ष	
		1973–73	1973–74
	(1) धान	92,000	1,18,000

	(2) बाजरा	2,19,000	2,26,000
	(3) गेंहू	10,00,000	12,00,000
(ग)	व्यय	38,50,000 रूपये	

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, जैसा मंत्री महोदय ने अपने उतर मे फरमाया है कि इतनी अच्छी अच्छी वेरायटी से बढोतरी हुई है, काफी लम्बी–चौड़ी इबारत पढी। मै जानना चाहता हूं कि पिछले साल जिन एरियाज मे हाई वैरायटी का बीज बोया गया था उससे वहां कितनी पैदावार हरियाणा में बढी हैं?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैने कहा है कि पिछले साल हाई ईल्ड वैरायटी का गेंहू 25 लाख एकड़ मे बोया था। जहां तक ज्यादा पैदावार का ताल्लूक है, मै मानता हूं कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल बाकई की गेंहू की पैदावार कुछ कम हुई है। उसका कारण कुछ और ही है। वैरायअी या बीज का कसूर नही था दरअसल फसल पकाऊ आने के टाईम पर गर्म हवा चली जिससे ईल्ड मे काफी फर्क पड़ा। इस वजह से पैदावर कम हुई। हायी ईल्ड वैरायटी बीज मे नुक्स की वजह से पैदावार कम नही हुई

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बतायेगे कि हायी ब्रिड बाजरे का बीज 1 लाख 47 हजार रूपये का आज भी गोडाउन मे पड़ा है? क्या यह हकीकत है?

चौधरी भजन लालः यह बिल्कूल गलत बात है। हमे बाजरे का सीड जितना चाहिए था उतना हमारे पास आया भी नही। बाजरे का सारा ही सीड हमारे पास 1600 क्विंटल आया है जबकि हमारी जरूरत 6 हजार क्विंटल की थी।

श्री गौरी शंकरः स्पीकर साहब, पिछले साल से इस साल जो बाजरे का बीज दिया गया वह निकम्मा था और उससे पैदावार का नुक्सान हुआ है। क्या इस बारे मे किसी के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया गया हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, बाजरे का सीड कोई प्रान्तीय सरकार नही बनाती है। हम सारे का सारा सीड नैशनल सीड कार्पोरेशन के द्वारा लेते है उसके बाद हम आगे डिस्ट्रिब्यूट करते है। इस बार हमने किसानों को कहा कि बाजरे का सीड एक नम्बर, दो नम्बर और चार नम्बर न बोये। बाजरे का बीज तीन का ही बोये क्योकि हमने तीन नम्बर को ही रिकमैन्ड किया था। तीन नम्बर सीड के बारे मे किसी किस्म की कोई शिकायत नही आयी और तीन नम्बर का बीज अच्छा भी रहा। एक नम्बर, दो नम्बर और चार नम्बर का बीज अच्छा भी रहा। एक नम्बर, दो नम्बर और चार नम्बर बाजरे के सीड मे पिछले साल

काफी शिकायत रही थी इसलिये हमने किसानों को सिर्फ बाजरा ही बोने के लिए कहा। जिस के बारे मे किसी प्रकार की कोई शिकायत नही आयी।

मलिक सतराम दास बतराः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि 105 रूपये क्विंटल के भाव से जो गेंहू प्रेाग्रेसिव फार्मर से लिया उसको आगे किसानों को किस भाव पर बेच रहे है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि हमने गेहूं के सीड का भाव 160 रूपये रखा गया हे। इसमे ऐसा है जब हम सीड बनाते है तो गेंहू के मुकाबले की प्रोडक्शन कम होती है, फिर हम उसकी ग्रेडिंग करते है उसके हिसाब से वह मंहगा पड़ता है। हमने किसानों को 160 रूपये के भाव से बेचा है।

श्री ओम प्रकाश गर्गः क्या मंत्री महोदय यह बातने की कृपा करेगें कि पिछले साल सीड के बारे मे उनके पास कोई शिकायत आयी है या नही?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय गेहू के सीड की प्रान्त मे कोई कमी महसूस नही हुई। गैंहू का सीड किसान खुद भी बनाते है ओर सरकार ने भी काफी मात्रा मे दिया है। प्रान्त मे गेंहू के सीड की कोई कमी नही थी।

श्री ओम प्रकाश गर्गः स्पीकर साहब, मैने यह सवाल नही पूछा था कि कमी थी। मेरा मतलब यह था कि क्या मंत्री जी

के पास सीड के खराब होने के बारे मे कोई शिकायत आई है जिससे फसल अच्छी न हुई हों?

चौधरी भजन लालः ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नही आई।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएगें कि जो बीज 160 रूपये क्विंटल से फरोख्त करते है वह बीज अब तक कितना स्पलाई किया जा चुका है?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, हमने जो सीड बेचा है उसके बारे मे तो आगे सवाल आ रहा है उसमे बताऊंगा लेकिन फिर भी मै जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमने कोई छः हजार क्विंटल बेचा है। दूसरे गेंहू के सीड की प्रान्त मे कही भी कमी महसूस नही की जा रही हें।

चौधरी शिव राम वर्माः क्या मंत्री महोदय यह बताएगें कि लोगों को हाई ईल्डिग वैराइटीज की तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार कोई विशेष सुविधाए देने पर विचार कर रही है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हाई इल्डिग वैरायटी अगर देश मे न होती तो आजकल जिस हिसाब से देश की आबादी बढ़ रही है, उससे देश मे बहुत बुरा हाल होता। जब हरियाणा बना तो हाई ईल्डिग वेरायटी के नीचे सिर्फ 16,000 हैक्टयेर जमीन थी और अब इसके नीचे हमने 17 लाख हैक्टेयर तक पहुंचा दी है।

चौधरी पीर चन्दः क्या मंत्री महोदयस यह बतलाने की कृपा करेगें, जैसे कि उन्होने यह बतलाया है कि एक नम्बर और दो नम्बर सीड अच्छे नही थे, और तीन नम्बर सीड अच्छा था, उन्होने एक और दो नम्बर सीड क्यों खरीदा, तीन नम्बर खरीदनवे मे उन्हे क्या दिक्कत थी?

चौधरी भजन लालः हमने एक क्विंटल भी, एक नम्बर, दो नम्बर और चार नम्बर सीड नही खरीदा। एक नम्बर, दो नम्बर और चार नम्बर सीड तो नैशनल सीड कार्पोरेशन ने बेचा है। हमने सिर्फ तीन नम्बर बीज बेचा है। हमने अपने किसानों को यह हिदायत दी थी कि वे सिर्फ तीन नम्बर बीज जी बोएं।

तारांकित प्रश्न संख्या 505

यह प्रश्न पूछा नही गया क्योकि सम्बन्धित माननीय सदस्य इस समय सदन मे उपस्थित नही थें।

Loans and Grants by the Development department

***446. Chaudhri Mehar Chand:** Will the Minister for development be pleased to state the various types fo loans and grants being given by the Development Department to the Public together with the terms and conditions thereof, separately?

Department Minister (Sh. Shyam Chand): A Statement is laid on the table of the House.

Statement

Loans

(i) The development Department gives loans to public through the agency of Block Development and Panchayat Officers under the provision of land Improvement Act 1883 for Minor Irrigation purposes at the rate of Rs.21 thousand per block per year to be utilized for aforesaid purposes in accordance with the terms and conditions given in Annexure-I.

(ii) The Development Department also gives loans for the construction of houses in the new abadies of model villages. These loans are payable to the loanees according to the size of their land holdings or landless residents as the case may be. The terms and condition for the grant of this type of loans given in Annexure-II.

Grants

(i) The Development Department also gives grants to the Panchyat Samitis for various Development works. These grants are given according to the provision under Section 42 and 43 of the Punjab Panchayat Samiti's Act 1961.

(ii) Discretionary grants sanctioned by the Ministers for works and schemes, the benefit of which accrues to the general public, are also disbursed through the Development Department in accordance with the policy instructions as gives in Annexure-III.

ANNEXURE I

Terms and conditions for grant of loan by the4 Development Department under the N.E.S. Minor Irrigation Loans Scheme.

(i) Admissibility

Purposes for which N.E.S. Loans are admissible and the extent up to which loans can be granted are as under:-

(a) name of the items	Limit of the loan to be advanced
1. Minor Irrigation	
(i) Sinking of percolation wells	Rs. 2,000
(ii) Repair of old wells	Rs. 1,000
(iii) Installation of Pumping sets	Rs. 2,500
(iv) Installation of Tube-wells	Rs. 6,000
	(Rs. 8,000 in the Non-Irrigated area of Gurgaon and Hissar)
(v) Koohls	Rs. 10,000
(vi) Tanks or Diggis	Rs. 12,000
(vii) Jhallars	Rs. 1,000
2. Reclamation	According to the area of the land to be reclaimed.

3. Other Puposes	According to the local need subject to the condition that the amount of loan does not exceed the cost of work.
(i) Field channels	
(ii) Distributaries	
(iii) Drainage	
(iv) Fencing	
(v) Soil conservation including Wahhadi	

(ii) Sanctioning Authority

Powers to sanction the loan are exercised by the following authorities up to the extent shown against each;-

(1) Block Dev. & Panchayat Officer	Upto Rs. 3,000 in individual cases.
(2) Deputy Commissioner	Upto Rs. 5,000 in individual cases (upto Rs. 6,000 in the case of tube-wells.)
(3)Commissioners	Upto Rs. 10,000
(4) Development Commissioner	Exceeding Rs. 10,000 upto Rs. 50,000.

(iii) Security

Collateral security of land sufficient to cover of loan (i.e. the value of 1½ times of amount of loan to be advanced). The land be hypothecated in favour of the Government.

(iv) Rate of Interest.

As fixed by the Government from time to time.

(v) Repayment.

Recovery is effecte4d in yearly equated installments of Principal and interest during the periods as detailed below:-

(i) Loans for percolation well	10 Years
(ii) Loans for repair of old wells	Twenty Half Yearly installment.
(iii) Loans for pumping sets.	15 Yearly instilments
(iv) Loans for tube wells	10 years
(v) Loans for Kuhls	10 years
(vi) Loan for Tanks or Diggis	10 years
(vii) Loan for jhallars	10 years
(viii) Reclamation	10 years
(ix) Field Channels Distributaries, Drainage, Fencing or soil conservation	10 years

Utilization of loan & period of grace.

The loan shall be utilized solely for the purpose for which it is sanctioned.

A period of one year is allowed for the completion of work and the completed works shall be got inspected by the sanctioning authority within this period. The first installment of recovery shall become payable on the expiry of that period.

In case of non-utilization of mis-utilization of the loan money, the whole amount advanced shall become payable in lump-sum along with the interest chargeable.

Execution of Bond.

The loanee shall be required to execute an agreement bond in the prescribed from for the fulfillment of the conditions attaching to the loan and its repayment alongwith the interest thereon.

ANNEXURE II

The main terms and conditions for the grant of loan under the Model Village scheme are as under:-

(1) The loan is advanced @ 75% of the estimated cost of a house. The costs of construction have been estimated category-wise as under:-

	Rs.
Category A	30 Thousand
Category B	20 Thousand
Category C	15 Thousand

Category D	10 Thousand

(2) The loan is disbursable in three installment; first installment 20% in the beginning, second installment 50% when the house comes up to plinth level and the third installment 30% of loan when the house is completed upto roof level.

(3) The loan is recoverable is recoverable in 40 half yearly equal installment of principal and interest-first installment being due 3 years after the draw2al of 1st installment of loan.

(4) The loan for category of house is subjected to an interest of 3% per-annum while loan for other category is subjected to interest of 5% per annum.

(5) If a loanee completes his house within one year of the drawl of Ist installment of loan of, 1/3 of the loan is remitted by way of subsidy.

(6) those who construct their houses without taking loan form the Government, will be entitled to subsidy of 40% of the amount of loan to which they would have otherwise been eligible.

ANNEXURE-III

Policy instructions governing the Discretionary Grants by Ministers.

1. These grants are sanctioned subject to the following consideration:-

(i) The Chief Minister/Ministers/Minister of State/Deputy Minister/Chief Parliamentary Secretary/Parliamentary Secretaries will generally keep in mind for guidance, the following categories of works/schemes for assistance provided the benefit accrues to the general public:-

(a) Drinking water supply scheme.

(b) Permanent works for improvement of Agriculture.

(c) Permanent works for improvement of rural sanitation.

(d) Village Roads, including small bridges and culverts.

(e) Improvement to schools or dispensary buildings where such institutions already exist and are in adequately housed.

(f) Library Books.

(g) Construction of godowns for storage of goods

(h) Allocation to panchyats for works connected with Panchyats.

(i) Uniforms to be supplied to poor school children.

These categories are, however, illustrative and not exhaustive. The Chief Minister/Ministers/Minister of State/Deputy Minister/Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary Secretaries can sanction grant-in-aid for any

work or scheme which is likely to improve conditions in the country side or benefit the community as a whole.

(ii) The condition for matching contributions form the beneficiaries need not be insisted upon, The Chief Minister/Ministers/Minister of State/Deputy Minister/Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary Secretaries while sanctioning the grants will keep in mind the possibility of making beneficiaries contribute.

(iii) Grant-in-aid will not be admissible to Government Institution.

(iv) Grant-in-aid will not ordinarily be admissible to denominational institutions. They may, however, be given to any such institutions where the particular items of works for which the grant is made, represents a district expansion of existing facilities and the institutions is open to all communities living in the area.

(v) Grants-will be admissible throughout the State.

(vi) Grant-in-aid should ordinarily no be given for the same work or scheme by more then one Minister. As soon as it is noticed that more than one Minister has sanctioned grants for the same works or scheme in the same area, the Development Department shall bring the matter to the notice of The Chief Minister/Ministers/Minister of State/Deputy Minister/Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary Secretaries and obtain his orders for utilization of the grant elsewhere.

(vii) No discretionary grant shall be sanctioned by any Minister including the Chief Minister during the period of three months preceding the date of General Elections to the State Legislature or Parliament. Further in the case of a bye-election or bye-elections, no discretionary grant shall be sanctioned in the constituency or constituencies concerned during the period of three moths preceding the bye-election(s) or from the fixing of the date of the bye-election(s) whichever period was shorter.

2. As the grant is to be spent at the discretion of The Chief Minister, Ministers, Minister of State, Deputy Minister, Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary Secretaries the works or scheme which they would like to be executed out of the amount at their disposal, should be intimated by them to the Development Department, alongwith the amount of grant-in-aid which they would like to be rapid for each work. The Development Department will take necessary action regarding the allotment of these funds to the Deputy Commissioner concerned immediately for being utilized/spent during the financial year thorough the Zila Parishad/Panchayat Samitis or the panchayats concerned, the Public Works Department (Buildings, Roads and irrigation Branches) or any other Government agency or Municipal Committee, as may be indicated by The Chief Minister, Ministers, Minister of State, Deputy Minister, Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary Secretaries for the purpose for which it is given. Moreover, in cases, where the major portion of the expenditure on a particular project is to be borne by the manageme3nt of the institutions themselves, then the grant money should be disbursed to the management

of the institution for the execution of the said work/scheme subject to the condition that the Deputy Commissioner will ensure that proper accounts are audited by the Audit Department. The Deputy Commissioner should personally ensure that the grant money made by the ministers etc. to a panchayat or other local body for non- governmental expenditure, which are allocated to him, is utilized and the relevant works/scheme are executed properly. As soon as the work/scheme has been completed, a certificate to this effect will be sent by the Deputy commissioner to the Audit Department. The Deputy commissioner, Shall also ensure the proper account of all moneys spent on such schemes by the Zila Parishads/ Panchayat Samitis or Panchayats, as teh case may be are properly maintained and kept of the propose of audit. The Deputy Commissioner will also ensure that detailed accounts of all such expenditure are otherwise maintained in accordance with the procedure applicable to Local Development Works. These instructions will also be applicable to any additional amounts made available of the purpose during the current financial year.

तारांकित प्रश्न संख्या 463

श्री अध्यक्षः ताराकित प्रश्न संख्या 463 के बारे मे सरकार ने एक्टैन्शन मांगी है जिसकी स्वीकृति दे दी गई है। इस सम्बन्ध मे निम्न पत्र प्राप्त हुआ हैः

“Maru Singh Malik D.O. No. 39-Edu-II-2E/73/32979

मंत्री

शिक्षा विभाग हरियाणा

चण्डीगढ़

Dated the, 14th Nov., 1973

Subject: Starred assembly Question No. 463 regarding Primary Schools.

My dear Gupta Sahib,

I write to inform you that Starred Assembly Question No. 463 to be asked by Shri Dal Singh, M.L.A. was received in the Education Secretariat on the 19th October, 1973. I understand that this question has been fixed for answer on the 15th November, 1973. As some information asked for from the District Offices has not been received, i feel that it will not be possible to answer it on the 15th November, 1973. I shall, therefore, feel grantful if this question is fixed for answer on any date after the 30th November, 1973.

Yours Sincerely,

Sd/-

(Maru Singh Malik)

Sh Banarshi Dass Gupta,

Speaker

Haryana Vidhan Sabha,

Chadigarh."

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, यह बात तो ठीक नही है। इससे पहले भी मेरे एक सवाल के बारे मे सरकार एक्टैंशेन मांग चुकी है। सरकार के पास ये फिगर्ज तो होती है। कि कितने प्राईमरी स्कूल नए खोले गए और कितने प्राईमरी स्कूल से मिडल स्कूल बनाए गए। यह कोई ऐसी बात नही है जो कि छिपाई ता सके।

श्री अध्यक्षः उन्होने फरमाया है कि यह इन्फर्मेशन हमने डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से मांगी है, वह हमें अब तक मिली नही है।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, जो कुछ हम पूछते है उसके लिए यह कहते है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से इन्फर्मेशन मिली नही है।

Growing of food.

***487. Sh. Grish Chander Joshi:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the steps taken to grown more food in the State during the year 1973-73.

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल): वर्ष 1972–73 मे अधिक अन्न उत्पादन के लिए विभाग द्वारा निम्निलिखित पग उठाए गए है:–

सिंचाई सुविधाओ का विस्तार

सिंचाई सुविधाओं मे विस्तार करने के लिए विभिन्न माध्यमों के द्वारा कृषिकों को 724.980 लाख रूपए ऋण के रूप मे दिए गए है, जिसके परिणामस्वरूप 29,640 नए नलकूप तथा पम्पस लगाए गए है, जिससे कि लघु सिंचाई के अन्तर्गत वर्ष 1971–72 की अपेक्षा 1,33,000 हैक्टेयर की वृद्वि हुई है।

अधिक उपज देने वाली जातियों के अन्तर्गत क्षेत्रः

वर्ष 1972–73 मे अधिक उपज देने वाली जातियों के अन्तर्गत क्षेत्र मे वृद्वि हुई जेा कि धान के अन्तर्गत 92,000 हैक्टेयर, मक्की के अन्तर्गत 13,000 हैक्टेयर, शंकर बाजरा 2,19,000 हैक्टेयर तथा गेंहू के अन्तर्गत 10,00,000 हैक्टेयर्ज है।

उन्नत बीजों का प्रयोगः

अधिक उत्पादन मे उन्नत बीजों के महत्व को देखते हुए 1972–73 मे विभ्न्नि फसलेां के अन्तर्गत निम्न मात्रा मे बीजों का प्रबन्ध किया गया हैं।

गेहूं	15,320 क्विंटल
चना	630 क्विंटल
शंकर बाजरा	1,885 क्विंटल
मक्की	117 क्विंटल

धान	1,777 क्विंटल

रसायनिक खादः

रसायनिक खाद के प्रयोग से उत्पादन मे तेजी से वृद्वि होती है। वर्ष 1972–73 में रसायनिक खादों का निम्नलिखित मात्रा मे वितनण किया गयाः–

	मात्रा (टनों में)
खाद	वर्ष 1972–73
एमोनियम सलफेट	4,15,530
(एन)	83,106
सुपर फासफेट	50,930
(पी)	(8,175)
म्यूरीएट आफ पोटास	4,360
(के)	(2,611)
जोड़	4,70,820
न्यू ट्रीएंटसः	**(39,892)**

गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत मे बढोतरी 18.6 प्रतिशत ।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेगें कि प्रान्त मे जितनी खाद की आवश्यकता थी, क्या उतनी खाद किसानों को मिली है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, खाद के बारे मे स्थिती यह है कि सारे देश मे ही खाद की कमी रही है। खाद बाहर से आती है। हमें बाहर से ही खाद कम मिली। जितनी हमें खाद की जरूरत थी, उतनी खाद आई नही। लेकिन इसके बावजूद भी हमने पूरी कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा खाद दें। भारत सरकार ने भी हमारे साथ बहुत ही सहानुभूति वर्ताव किया और वे जितनी हमारी ज्यादा से ज्यादा सहायता कर सकते थे, की। लेकिन जितनी हमारी जरूरत थी, उससे थोडी़ बहुत कम अवश्य रही है।

मलिक सतराम दास बतराः स्पीकर साहब, हिसार यूनिवर्सिटी के कुद लैक्चरार, कुछ डाक्टर, कुछ प्रोफैसर आजकल रबी कम्पेन के तहत गांव गाव मे जा रहे हे। यदि हम यह भी मान ले कि वह ठीक काम कर रहे है तो मै मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होने कोई एक किल्ला जमीन भी अपने हाथ से जमींदार को बो कर दी है? इसके इलावा मै यही भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसान को पानी की सरटेंटी का आश्वासन देती है?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, एग्रीकलचर यूनिवर्सिटी से अढाई सौ से करीब एक्सपर्टस हमने बुलाए है। हमने अढाई सौ टीमे बुलाई है। उनकी एक–एक पार्टी के अधीन हमने 10–10 गांव रखे है। वे लोग तकरीबन अढाई हजार गांवों मे इसकी डिमान्स्ट्रेशन लगाकर किसानों को बताएगें कि आपको इस तरह से खाद डालनी है, इस तरह से बोना है, सारी बातें वे अच्छी तरह से समझाएगें। इस चीज का हमने प्रबन्ध का सवाल है, अधिक पानी दैने के लिए भी हमने इस बार वैस्टर्न जमुना कैनाल मे 6–7 सौ क्यूसिक पानी भाखड़ा से लेकर चलाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सोईंग हो सके। पिछले साल के मुकाबले मे इस साल भाखड़ा की नहरों मे भी ज्यादा पानी चला है।

चौधरी मनफूल सिंहः क्या मंत्री महोदय यह फरमाने की कृपा करेगे कि गेंहू की कीमत कम होने के कारण किसान को जो रूझाान अब जौ, सरसों और चने काश्त करने की तरफ है, उसके लिए कोई पग उठाए जा रहे है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, बात ऐसे है जब गेंहूं का भाव तय करने का जिक्र आया, उस समय हमने गवर्नमैंट आफ इंडिया से पूरी लड़ाई लड़ी कि किसान के लिए गेंहू का भाव कुछ बढाना चाहिये लेकिन भारत सरकार की भी उसमे कुछ मजबूंरियां होती है। उन्हे भी इस बात का फेसला करते समय बहुत सी बाते ध्यान मे रखनी पड़ती है। जैसे लेबरर है, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, कर्मचारी है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता

है लेकिन इस सब के बावजूद भारत सरकार ने गेंहू का भाब बढाया है। पिछले साल गेंहू का भाव 76 रूपये था जब कि इस बार उन्होने इसकी स्पोर्ट प्राईस 85 रूपए नियत की है। जैसे पिछले साल पैडी की स्पोर्ट प्राईस 63 रूपये मुकरर्र की थी और फिर अब उन्होने उसकी प्रोक्योरमैंट प्राईस 70 रूपये मुकरर्र की है, इसी तरह से उन्होने जो गेहूं की 85 रूाये स्पोर्ट प्राईस मुकरर्र की है, उसमे यह आशा ळ कि इसकी प्रोक्योरमैंट प्राईस जरूय कुछ न कुछ बढेगी। जहां तक एरिया कम होने का सवाल है चने ओर जौ मंहगें भाव से बिक रहे है इससे कुछ न कुछ तो जरूर फर्क पड़ेगा।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने यह माना है कि खाद की कमी हैं। खाद की कमी की वजह से, खाद ब्लैक मे बिकता है। अगर यह बात उनकी नौलेज मे है तो मै यह जानना चाहूंगा कि इसको रोकने के लिए क्या कोई प्रबन्ध करने का विचार है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सारी की सारी खाद, जितनी भी आती है वह को–आप्रेटिव सोसाइटीज के थरू बिकती है। हमारे प्रान्त मे 70 प्रतिशत खाद किसानों को को–आप्रेटिव सोसाइटीज के द्वारा तकसीम की जाती है और 30 प्रतिशत खाद प्राईवेट डीलर्ज के द्वारा दी जाती है। उसके लिए भी हमने पिछले सैशन मे एक बिल पास किया है जिसके द्वारा उन पर भी हमारा पूरा कन्ट्रोल है। डिप्टी कमिश्नर को उसको कन्ट्रोल

करने का हमने पूरा अधिकार दिया है। अगर कही भी कोई ब्लैक जैसी बात हो और उस के नोटिस मे आए तो वह ऐक्शन ले सकता है। अगर कोई ऐसी बात आपके नोटिस मे हो तो आप सरकार के नोटिस मे लाएं, उनके खिलाफ ऐक्शन लेगें।

चौधरी फूल सिह कटारियाः स्पीकर साहब, जिस इलाके के अन्दर गेंहू नही होता, उस इलाके के अन्दर खाद की बहुत जरूरत है जैसे कि साल्हावास और नाहड़ का इलाका है। वहां पर इतनी ज्यादा गेंहू तो नही होती लेकिन अग पहले से कुछ अधिक है। हमारे यहां झज्जर तहसील ऐसी है कि वह प्रोक्योरमैंट के अन्दर सबसे ऊपर रही है। उसने अपने टारगेट से भी ज्यादा गेहू प्रोक्योर किया है। क्या मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि हमारे इन इलाको को भी खाद दी जाएगी?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हम खाद सारी स्टेट के कोने कोने मे देते है। सरकार यह सर्वे कराती है कि कौन–कौन से इलाके मे कितनी – कितनी खाद चाहिए। सर्वे की रेशो के हिसाब से हम खाद तकसीम करते है।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगें कि किसान जो अन्दाता है, वह पहले के मुकाबले मे और गरीब क्यो होता जा रहा है?

(कोई उत्तर नही दिया गया)

चौधरी पीर चन्दः जैसे कि मंत्री महोदय ने यह फरमायार है कि पिछले साल खाद की कमी रही , मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस साल खाद की कमी को पूरा करने के लिए कोई प्रबन्ध किये हुए है या नही?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैने पहले भी यह कहा है कि इस बारे मे हम पूरी–पूरी कोशिश कर रहे है कि किसान को खाद हर हालत मे मिले लेकिन जैसे कि मैने पहले भी कहा है, भारत सरकार की भी कुछ मजबूरियां है, क्योकि खाद बाहर से आती है और खाद बाहर से ही कम आने की वजह से इसकी कमी है।

राव बन्सी सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताएगें कि डिस्ट्रिक्ट वाईज कितनी–कितनी खाद अलाट की गई है और डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ मे खाद की बहुत कमी रही है क्या यह बात भी उनके नोटिस मे है? इस कमी को पूरा करने के लिए कोई प्रबन्ध किए जा रहे है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, डिस्टिक्ट वाईज कितनी खाद अलाट की गई इसकी तो फिगर्ज मेरे पास नही है, अगर पूछना चाहते है तो अलग से नोटिस दे दे उसका भी जवाब दे देगें लेकिन जहां तक खाद की कमी का ताल्लूक है, जैसे कि मैने अभी बताया है, खाद की सिर्फ हमारे प्रान्त मे ही नही, सारे देश मे कमी है। जहां तक महेन्द्रगढ़ जिले का ताल्लूक है जहां

पर खाद ज्यादा लगती है वहां पर ज्यादा दी जाती है और जहां पर उसकी जरूरत थोड़ी होती है, वहां पर थोड़ी दी जाती है।

चौधरी शिव राम वर्माः मंत्री महोदय ने अभी यह आंकड़े दिए है कि हमने किसानेा को यह यह चीजे दी। मै यह जानना चाहता हूं कि सारी सुविधाए देने के कारण कितनी पैदावार बढ़ी है? एक तरफ सुविधा देने की बात कही गई है और दूसरी और किसानों को जो बिजली दी जाती है उसमे कटौती की जा रही हैं क्या यह भी ग्रो मोर फूड का एक हिस्सा है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, पिछले साल के मुकाबले मे जहां तक उत्पादन का ताल्लूक है वह तो आगे आएगा लेकिन जहां बिजली का ताल्लूक है, हमने सोईंग के वक्त ट्यूबवैल को पूरी बिजली देने की केाशिश की है। हो सकता है कि कभी किसी मशीनरी मे नुक्स आने की वजह से कुछ कमी आ गई हो लेकिन उसके बावजूद हमारी पूरी कोशिश है कि किसान को हर ट्यूबवैल के लिए पूरी बिजली मिलें।

चौधरी दल सिंहः मिनिस्टर साहब, ने अभी फरमाया कि किसानों को हमने सुविधाए दी और वे किसानो के बड़े हमदर्द है। जमींदारो को देने के लिए भारत सरकार ने बोनस मिला है वह किसानों को आज तक क्यों नही दिया गया है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चौधरी दल सिंह ने ऐसी बात कही जैसे सारा कुछ इनको पता है। अभी तक सरकार

ने बोनस नही दिया है। ज्यों ही बोनस हमारे पास आएगा हम फौरन किसान को दे देंगें।

Consumption of Fertilizer

***496. Sh. Gauri Shakar:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether it is a fact that fertilizer consumption has gone up in the State; if so, the percentage of increase in 1973-73 and 1973-74.

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल): वर्ष 1972–73 मे वर्ष 1971–72 की अपेक्षा खाद की खपत मे 18.6 प्रतिशत की वृद्वि हुई परन्तु वर्ष 1973–74 (फरवरी से सितम्बर तक) खाद की खपत 1972–73 (फरवरी से सितम्बर तक) की तुलना मे बराबर हो रही।

चौधरी राम लाल वधवा: जो कमी है उसको पूरा करने के क्या साधन तैयार किए जा रह हैं?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब यह दे चूके हैं?

तारांकित प्रश्न संख्या 506

यह प्रश्न पूछा नही गया क्योकि सम्बधिन्त माननीय सदस्य उस समय सदन मे उपस्थित नही थें।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Revenue Patwaris

242. Chaudhri Dal Singh: Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) Whether any persons were selected by the S.S.S Board, Haryana for appointment to the post of Revenue Patwaris in the years 1973;

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative whether the S.S.S. Board Haryana, recommended the names of the selected persons as referred to in part (a) above to the Deputy commissioners in the State for appointment against the vacant posts of Revenue Patwaris; if so, the District-wise number and names of such persons;

(c) whether the selected persons as referred to in part (b) above have been appointed by the concerned Deputy Commissioners; and

(d) the Total number of District-wise vacant posts of Revenue Patwaris in the State as on 30th September, 1973.

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma):

(a) Yes.

(b) Yes, District-wise number and names of such persons are embodied in Annexure 'A'.

(c) Out of the selected persons as referred to in part (b) above, 16 have been appointed by the concerned Deputy Commissioners.

(d) 96 as per given in Annexure 'B'.

ANNEXURE 'A'

Hissar District.

Sarvshri:-

1	Kashmiri Lal
2	Om Parkash
3	Ramji Lal
4	Jagdish chander S/o Attar Chand
5	Sohan Singh
6	Jagdish chander S/o Ganpat Ram
7	Ram Chander
8	Kapur Singh
9	Balkar Singh
10	Bhool singh
11	Main Paul
12	Ranjeet Singh
13	Balwan Singh
14	Gurmel Singh
15	Om Parkash
16	Babu Singh
17	Ram Narain

18	Gugan Ram
19	Satish Kumar
20	Pawan Kumar
21	Hari Singh
22	Dhup Singh
23	Ram Partap
24	Harphul Singh
25	Hans Raj
26	Shamsher Singh
27	Mahabir Singh

Bhiwani District.

1	Sajjan Singh
2	Ram Parkash
3	Parkash Chander
4	Manohar lal
5	Hans Raj

Sonipat District

1	Rajinder Singh

Karnal District

1	Jiwan Dass Batra
2	Babu Ram
3	Bakshi Narain

Kurukshetra District

1	Shiv Kumar
2	Meg Raj
3	Mange Ram

Ambala District.

1	Sham Singh
2	Prem Chand
3	Om Parkash
4	Ajmer Singh
5	Raj Kumar
6	Ramesh Chand

7	Jag Paul
8	Shiv Dayal
9	Mam Chand
10	Sudaugar Ram
11	Rajinder Parshad
12	Gian Chand
13	Nar Singh
14	Gurdial Singh
15	Brij Bhushan

Jind District

1	Punjab Singh
2	Babu Ram
3	Om Parkash
4	Mukat Bhihari Lal
5	Dalip Chand
6	Raj Kumar
7	Jogi Ram
8	Bhup Singh

9	Telu Ram
10	Des Raj
11	Jai narain
12	Man Singh
13	lal Chand
14	Sham Lal

Narnaul District

1	Duli Chand
2	Budh Ram
3	Sardara Singh
4	Hari Singh
5	Brij Mohan
6	Ranbir Singh

ANNEXURE 'B'

Sr. No.	District	Number
1	Hissar	33

2	Bhiwani	16
3	Rahtak	-
4	Sonepat	4
5	Gurgaon	-
6	Karnal	5
7	Kurukshetra	3
8	Ambala	3
9	Jind	14
10	Narnaul	18
Total		96

अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न स. 513 पर संव्यवस्था (रूलिंग) 4(21)

श्री अध्यक्षः 12 नवम्बर, 1973 को जब प्रश्न का उतर दिया जाना था, श्री हरद्वारी लाल, एम.एल.ए. ने सचिव, विधान सभा को यह लिखकर भेजा कि यह मामला न्यायाधीश (सब–जुडिस) हो गया है क्योंकि उन्होने इस मामले के बारे मे जो कि उनसे सम्बन्धित है कुरूक्षेत्र विश्वविधालय के वर्तमान उप–कुलपति के विरूद्व भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अधीन एक परिवार (कम्पलेंट) दायर किया हुआ हैं। उन्होने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चण्डीगढ़ के न्यायालय मे अपने द्वारा दायर

किए गए परिवाद कीएक प्रति साथ लगाई थी और उन्होने यह इच्छा प्रकट की थी कि यह तथ्य मेरे ध्यान मे लाया जाए ''क्योकि सदन के नियमों तथा रूढ़ि के अनुसार ऐसे मामले का वर्णन नही किया जा सकता या उस पर चर्चा नही की जा सकती जो न्यायाधीन (सब–जुडिस) हों।''

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 46 के खण्ड (10) मे यह दिया गया है कि ''इस (प्रश्न) मे किसी ऐसे विषय पर जानकारी नही मांगी जाएगी जो भारत के किसी भाग मे क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी विधी–न्यायालय (कोर्ट आफ ला) के न्याय–निर्णयन के अधी हो।'' यह प्रश्न इस विषय के न्यायाधीन (सब–जुडिस) बनने से पहले ही स्वीकार किया जा चुका था और मै समझता हूं कि यह नियम इस विशेंष मामले मे किसी प्रकार लागू नही होता। तथापि इस मामले की परिस्थिती को ध्यान मे रखते हुए मै इस प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्यगण से आग्रह करूंगा कि वे इस प्रश्न के उतर के लिए जोर ने दें।

Chaudhri Hardwari Lal: Sir, I have a submission to make. . .

श्री अध्यक्षः आप तशरीफ रखिए। मेरी रूलिंग आ चुकी है।

Chaudhri Hardwari Lal: The ruling is that subjudice matter can be referred to .. . .

श्री अध्यक्षः आप तशरीफ रखिए। मैने रूलिंग के अन्दर सब कुछ कह दिया हैं।

Chaudhri Hardwari Lal: I Want to understand if Sub-Judice matter can be referred to in the House.

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाइए। मैने अपनी रूलिग दे दी है उसके अन्दर सब कुद कह दिया है।

Chaudhri Hardwari Lal: I just want to know if the ruling is that it could be referred to

श्री अध्यक्षः अगर कुछ और बात करनी है तो आप मेरे चैम्बर मे आए जाए।

Chaudhri Hardwari Lal: I am sorry I could not follow the last part of it.

श्री अध्यक्षः मैने जिक्र किया कि समय यह क्वैश्चन एडमिҕ हुआ यह उस वक्त सब–जुडिस नही था।

Chaudhri Hardwari Lal: As a Matter of fact, the question should not have been admittede because it related to a matter . . . .

श्री अध्यक्षः मै इस सवाल का पर बहस नही करना चाहता।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मेरी एक मोशन यू.पी. बोर्डर के सम्बन्ध में थी उसके बारे में स्वीकृति मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः उसकी इतलाह आपको मिल जाएगी।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, यह बड़ा गम्भीर मामला है गवर्नमैंट की तरफ से जनता को और सदन को विश्वास मे लेना चाहिए।

श्री अध्यक्षः इसकी सूचना आपके पास पहुंच जाएगी।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, आपने कह दिया कि रूलिंग आ चुकी है और आपने कहा है कि मैम्बर न दे लेकिन फिर भी अगर मैम्बर जोर दें . .. .

श्री अध्यक्षः मै इसके बारे मे कोई डिस्कशन नही चाहता।

चौधरी चांद रामः डेट आफ रूलिंग बाद की है. . . .. . .

श्री अध्यक्षः मेरी रूलिंगे आ चुकी है अब इस बहस की आवश्यकता नही हैं। अब कृषि मंत्री चौधरी अमर सिंह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य देंगें।

कृषि मंत्री द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (संख्या 1 पर वक्तव्य)

10.00 बजे

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल): आदरणीय सदस्य ने सदन का ध्यान आवश्यक वस्तुओं की कमी तथा बढती हुई कीमतों के बारे मे आकर्षित किया है, जिनकी स्थिती इस प्रकार है:–

साफट कोयला

भारत सरकार ने हमारे राज्य के लिये 750 वैगन प्रति मास का कोटा नियत किया हुआं है परन्तु वैगन उपलब्ध न होने के कारण हमारे राज्य मे यह कोयला बहुत कम प्राप्त हुआ है। इस के लिए हम समय–समय पर रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलते रहे है और राज्य को अधिक वैगन दिलाने की पूरी कोशिश करते है। परन्तु हमारे प्रयत्नों के बावजूद भी राज्य को आवश्यकतानुसार साफ्ट कोयला नही मिल रहा है। इसी प्रकार slack coal की भी कमी हमारे राज्य मे काफी चलती आ रही है क्योकि 20 रेक प्रति मास के विरूद्व केवल एक या दो रेक प्रति मास मिल रहे है। अधिक रेक प्राप्त करने के लिए कोशिश जारी है और भविष्य मे भी प्रयत्न जारी रहेंगे। इन वस्तुओं की कमी सारे देश भर मे है और कई कठिनाईयों के होते हुए भी भारत सरकार हमारी मांग को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं।

2. साथ ही राज्य मे कोयला आता है उसके ईक वितरण की पूरी व्यवस्था की गई है। Haryana Distribution of Domestic Fuel Order, 1971, के अधीन जिलाधीशों को साफ्ट कोयले का मूल्य नियत करने की शक्तियां भी दी हुई हैं तथा कोयले के डिपो होल्डर्ज जिला अधिकारियों द्वारा नियत की गई कीमत पर ही कोयला बेच सकते हैं। जिला अधिकारियों से पूछताछ करने पर पता चला है कि साफ्ट कोयले की कीमत इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले मे ज्यादा नही बढी है। कुछ एक जिलों में जिलाधीशों ने एक से डेढ रूपये की प्रति किवंटल तक दर बढाए है। साफ्ट कोयले के वितरण के लिये जिलों मे जिलाधीशों की अनुमति से कोयले के डिपो खोले जा सकते है तथा जहां भी जिलाधीश आवश्यक समझते है कोयले के और डिपो भी लोगो की सुविधा के लिए खोजे जा सकते है।

वनस्पति घी

3. हमारे राज्य के लिए भारत सरकार ने 1,613 अन प्रति मास वनस्पति घी का कोटा नियत किया है। इस कोटे का अधिकतर हिस्सा राज्य से बाहर की वनस्पति घी की मिलों से दिया हुआ हें। परन्तु वनस्पति घी के कम उत्पादन के कारण बाहर की मिलों की ओर से कुछ महीनेां से हमें कम सप्लाई प्राप्त हुई हें जिस के कारण हमे राज्य की मिलों पर ज्यादा निर्भर होना पड़ा है।। राज्य मे केवल चार मिलें प्रतिमास 600 टन वनस्पति घी बनाती हैै और बाहर की मिलों से केवल 70–80 टन घी मिल रहा

है। इस प्रकार हमे 1,613 टन के विरूद्व केवल 700 टन घी ही प्राप्त हो रहा है। इसलिये घी के वितरण पर भी पूरा नियन्त्रण किया गया हैं। जिला अधिकारियों को आदेश दिए गए है कि घी का वितरण राशन कार्डो पर ही किया जाए। इस समय घी के वितरण के लिए राज्य मे 484 Whole Dealers तथा 720 Retail Dealers हैं।

वनस्पति घी के कम उत्पादन को मुख्य कारण खाने वाले तेलो की कमी है। पिछले वष्र देश के कई प्रमुख राज्यों मे सूखा पड़ा और बाहर के देशों से भी कम मात्रा मे यह तेल प्राप्त हु आ। परन्तु इस खरीफ मे गुजरात आदि राज्यों में मुंगफली की फसल बहुत अच्छी हुई है और आशा है कि शीघ्र ही वनस्पति घी के वितरण पर नियन्त्रण हटा दिया जाएगा। भारत सरकार की ओर से भी कीमत मे कमी होने की आशा है।

सीमेंट

4. हमारे राज्य को 20 लाख टन की इस वर्ष की मांग के विरूद्व भारत सरकार ने केवल 3.88 लाख अन सीमेट अलाट किया है। भारत सरकार ने हमारे आग्रह करने पर हमे बताया है कि देश मे सीमेन्ट का उत्पादन इतना नही है जिस से हमारी मांग पूरी की जा सके । कम उत्पादन होने के कारण, बिजली की कमी, मजदूरों की हड़ताल आदि है। जो भी सीमेन्ट राज्या को प्राप्त होता है उस के वितरण पर पूरा नियन्त्रण है और अधिकतर

सीमेन्ट सरकारी कामों के लिए तथा जनता को नलकूपों आदि के लिए प्राथमिकता से दिया जाता है। जो free-sale कोटा है उस के वितरण के लिए S.D.Ms. की अध्यक्षता मे कमेंटियां बनाई हुई है और इन कमेथ्यों की देख रेख मे सीमेंन्ट का ठीक ढंग से वितरण किया जाता है।

हमारी मांग पर भारत सरकार ने राज्य मे स्थित दोनेा सीमेन्ट फैक्ट्रियों का अधिकतर उत्पादन हमारे राजय को अलाट किया है जिस के फलस्वरूप दूसरे राज्यों के मुकाबले मे हमे काफी सीमेन्ट प्राप्त होता है।

सीमेन्ट की कीमत भी भारत सरकार ही नियत करती है ओर उन्होने 15 सितम्बर, 1973 से सीमेन्ट की कीमत 10 रूपये प्रति टन बढाई हैं।

मिट्टी का तेल

5. मिट्टी का तेल का कोटा भी भारत सरकार द्वारा ही हर मास दिया जाता हैं। पिछले मास का कोटा लगभग 73 लाख लीटर था। मिट्टी का तेल पर भी राजया का पेरा नियन्त्रण है और Punjab Kerosne Oil Dealers Licencing Order, 1966 के अधीन जिला अधिकारियों ने हमारे राज्य में 147 होलसेलर्ज तथा 724 रिटेल डीलर्ज नियत किए है। जिला अधिकारियों को आदेश दे रखें है कि जब भी मिट्टी के तेल की कमी महसूस हो तो इस का वितरण राशन कार्डो द्वारा ही किया जाए जिस की मात्रा 5

सदस्यों वाले कुटूम्ब के लिये 10 लीटर प्रति मास तथा पांच से अधिक सदस्यो वाले कुटुम्ब के लिए एक टीन प्रतिमास रखा है। भारत सरकार को भी प्रार्थना की गई है कि हमारे राज्य का कोटा 73 लाख से बढा कर 90 लाख लिटर किया जाए।

मिट्टी के तेल की कीमत भी भारत सरकार ने नियत की हुई है। इस मास भारत सरकार ने मिट्टी के तेल की कीमत मे 28 पैसे लिटर की वृद्वि की थी जो हाल ही मे 10 पैसे प्रति लिटर कम कर दी गई है।

चावल तथा गेंहू

6. अगस्त तथा दिसम्बर के मासों मे गेहूं के आटे की मांग की काफी थी लेकिन भारत सरकार की ओर से हमें 30,000 टन की मांग के विरूद्व केवल 10,000 टन प्रति मास मिला राज्य सरकार ने इस थोडी़ मात्रा को ठीक ढंग से वितरण करने के लिए यह निर्णय लिया कि गेहूं की बजाए केवल आटा ही उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दूकानों द्वारा दिया जाए ताकि केवल गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति ही इसे लें। Prevention of Harding Order के अधी यह आदेश जारी किए हुए है कि राशन कार्ड पर केवल उन्हे आटा दिया जाए जिनके पास गेंहू का भण्डार नही है। यह आदेश Defence of India Rules के अधीन जारी किए गए है और उनके अधीन गलत ढंग से राशन लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सकती हैं।

इस कार्यवाही का काफी अच्छा असर पड़ा तथा अब खरीफ की अच्छी फसल होने के कारण बाजरा आदि भी लोगो को ठीक भाव पर मिल रहा है और अब आटे की अधिक मांग नही रही है।। अब पूरी मोंग के अनुसार आटा भेजा जाता है। इसी प्रकार चावल के बारे मे भी हमारे राज्य मे स्थिती ठीक रही है। अक्तूबर के महीने मे पिछले महीने के मुकाबले उचित मूल्यों की दूकानो द्वारा बहुत ही कम चावल उठा जब कि हर लि मे अधिक स्टाक थें।

राज्य सरकार ने गेंहू तथा चावल की कीमत मे कोई विशेंष वृद्वि नही की है। भारत सरकार की ओर से जिस भाव पर गेंहूं मिलता है उसमे केवल आवश्यक खर्चा लगा कर भाव नियत किए जाते है। हाल ही मे भारत सरकार ने 8 नवम्बर, 1973 से गेंहू के भाव मे 12 रूपये प्रति क्विंटल तथा चावल के भाव मे 25 रूपये से 28 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्वि की है जिसकू अनुसार गेहूं तथा चावल के भाव मे कुछ वृद्वि हुई है।

गेहूं और आटे और चावल के वितरण के लिए राज्य मे इस समय 860 शहरी डिपो तथा 2,817 ग्रामीण डिपो चल रहे है। जिला अधिकारियों को आदेश दिए हुए है कि हर गांव मे जहां कही भी और डिपों खोलने की मांग हो वहां जनता की सूविधा के लिए डिपो फौरन खोल दिए जाए। इस वर्ष देहात के लोगों को राशन कोर्ड भी खाद्य विभाग ने तैयार कर दिए है तथा झूठे कार्डो की शिकायत दूर करने की पूरी पूरी कोशिश की गई है।

जहां तक कृषि उत्पादन को बढाने के सिलसिलें मे गेंहू तथा चने के बीज, खाद तथा ट्रैक्टरो की कमी तथा बढती हूई किमतो की बात है इस के बारे मे स्थिती इस प्रकार है:—

बीज

7. कृषि विभाग ने बीज की कमी की सम्भावना को ध्यान मे रखते हूए इनको प्राप्त करने के लिए काफी कदम उठाए है जब कि पिछले वर्ष केवल 630 क्विंटल चने का बीज राज्य की ओर से वितरित किया गया था, इस वर्ष राज्य मे 13,000 क्विंटल चने के बीज का वितरण किया गया जिसमें से लगभग 10,000 क्विंटल बीज राजस्थान से बहुत प्रयत्नों के बाद प्राप्त किया। चने का बीज 185 रूपये प्रति क्विंटल के भाव पर बेचा गया जब कि बाजार मे चने के बीज की कीमत 200 रूपए से अधिक रही। इसी तरह चालू रबी की फसल मे 15,000 क्विंअल गेंहू के बीज का भण्डार किया गया है और यह बीज 160 रूपये प्रति क्विंटल की कीमत पर बेचा जा रहा है जब कि नैशनल सीड कार्पोरेशन के बीज का भाव 210 से 220 रूपये प्रति क्विंटल है। राज्य मे कही से भी बीज की कमी की सूचना नही प्राप्त हुई है।

खाद

8. रासायनिक खाद की कमी न केवल हमारे देश मे है बल्कि सभी देशों मे है। भारत सरकार के पूरे प्रयत्नों के बावजूद देश के सभी राज्यों मे रासायनिक खाद की भारी कमी है। भारत

सरकार ने हमारे राज्य की कृषि उत्पादन की क्षमता और केन्द्रीय पूल मे योगदान का ध्यान मे रखते हूए खाद की अलाटमैंट मे हमारे राज्य को विशेष प्राथमिकता दी हे। इसके बावजूद हमारे राज्य मे किसानों की जागरूकता के कारण हमे खाद की कमी महसूस हो रही हैै। 1967–68 मे राज्य मे खाद की 1 लाख 62 हजार टन की खपत हुई थी जब कि पिछले साल खाद की कमी के बावजूद भी इसकी खपत 40 लाख 70 हजार अन हुई है यानि 5 वर्षो मे तीन गुना वृद्वि हुई है। यदि आवश्यकता के अनूसार खाद प्राप्त होती तो खपत मे और भी वृद्वि होती। इस वर्ष की खरीद के लिए हमने 3 लाख टन खाद की मांग की थी जब कि विश्व भर मे खाद की कमी के कारण भारत सरकार ने हमे केवल 2 लाख 64 हजार टन अलाट किया। जिस मे से 2 लाख टन खाद प्राप्त हुई। इसी प्रकार चालू रबी के लिए हमने 6,80,000 टन की मंगा की थी जिसके मुकाबले मे हमें 4,40,000 टन अलाअ किया। रबी के लिए खाद प्राप्त करने मे बन्दरगाहों पर जहाजो मे से खाद उतारने की कठिनाई के कारण कुछ देरी अवश्य हुई है लेकिन अब यह दिक्क्त दूर हो गई है और राज्य मे Phophatic खाद पूरी मात्राा मे प्राप्त हुई है और नाईट्रोजनयस खाद भी शीघ्र ही पूरी मात्रा मे प्राप्त होगी।

खाद की कीमत भी भारत सरकार ने निर्धारित की हुई है और हाल ही मे अन्य मुल्कों मे खाद की कीमत में वृद्वि के कारण भारत सरकार ने खाद की कीमत थोड़ी सी बढाई है।

खाद वितरण पर पूरा नियन्त्रण है और 70 प्रतिशत से अधिक खाद सहकारी समितियों द्वारा वितरित की जाती है। प्राईवेट डीलर्ज की ओर से जो खाद बेची जाती है उस पर भी Fertilizer Control Order के अधीन जिलाधीशों को पूरे अधिकार है।

ट्रैक्टर

9. देश मे अच्छे ट्रैक्टरों की कमी जरूर है लेकिन इस का कारण विदेश से आए हुए ट्रैक्टरों की मांग हैं। देश मे बने हुए ट्रैक्टरों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने दूसरे मुल्कों से ट्रैक्टरों के आयात पर कुछ हद तक पाबन्दी लगा रखी हैं।

राज्य मे किसानों की जरूरत को पूरा करनेक लिए एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन की ओर से 17 एग्रो सर्विस सैन्टर चलाए जा रहे हैं। इन की ओर से 116 ट्रैक्टर जरूरतमंद किसानों को किराए पर दिए जाते है। इस के अलावा बेराजगार इंजीनियरों द्वारा भी कृषि सेवा केन्द्र चलाए जा रहे है। ऐसे 2–3 केन्द्र स्थापित किए जा चुके है और 9 अन्य केन्द्र शीघ्र की स्थापित किए जा रहे है। 17 अन्य केन्द्र भी खोलने के लिए बेरोजगार इंजीनियरो को ट्रेनिंग दी जा रही है। चालू वर्ष मे कुल 70 केन्द्र खोलने का लक्ष्य है। अगले वर्ष 70 और ऐसे केन्द्र खोले जाएगें।

इससे तकरीबन हर ब्लाक मे दो दो सर्विस सैन्टर हो जाएगें जिससे छोटे किसानो को काफी सूविधा मिलेगी।

उपरोक्त वर्णन से जाहिर है कि हालांकि पिछले साल देश के अधिकतर भागों मे सूखा पड़ा और कई आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन मे कमी हुई है परन्तु हमारी राज्य सरकार इन वस्तुओं को अपने राज्य के लोगो के लिए अधिक से अधिक मात्रा मे प्राप्त करने के लिए अनथक प्रयत्न करती रही है और आगे भी करती रहेगी और इन वस्तुओ की कीमत तथा वितरण पर राज्य सरकार ने पूरा नियन्त्रण किया हुआ है। ठीक ढंग से वितरण करने की व्यवस्था भी की गई है खास कर Defence of India Rules के अधीन Prevention of Harding order जारी किया गया है जिस के अधीन 24 आवश्यक वस्तुओं कि वितरण पर नियंत्रण किया गया हें।

10. मै सदन को सरकार की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण मामलें मे सरकार पूरी तरह जागरूक है और जन साधारण की जरूरी आवरूकताओं को पूरा करने मे सरकार कोई कसर बाकी नही छोड़ेगी।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण (चौधरी प्रताप सिंह दौलता द्वारा)

चौधरी प्रता सिंह दौलताः स्पीकर साहब, मै पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः यह आपको क्वैश्चन आवर के बाद कहना चाहिए था।

चौधरी प्रता सिंह दौलताः स्पीकर साहब, मै आपकी इज्जत करता हूं। मै उस वक्त खड़ा हुआ था।

श्री अध्यक्षः नही नही उस वक्त तो मिनिस्टर साहब ने शुरू कर दिया था।

चौधरी प्रता सिंह दौलताः स्पीकर साहब, मेरी चेयर को डिफाई करने की आदत नही है।

श्री अध्यक्षः अच्छा मै आपको एक मिनट के लिए समय देता हूं लेकिन कोई काउन्टर एलीगेशन न हों।

चौधरी प्रता सिंह दौलताः स्पीकर साहब, टाईम तो मूझे तीन–चार मिनट चाहिए। हां अगर काउन्टर एलीगेशन हो तो आप मुझे फौरन बैठा दे क्योकि पर्सनल एक्सप्लेनेशन मे किसी दूसरे पर हमली करने की कोई प्रोवीजन नही है।

श्री अध्यक्षः ठीक है आप एक मिन्ट के लिए बोल लें।

चौधरी प्रता सिंह दौलताः स्पीकर साहब, मुझ पर जो भी क्रिटिसिजम आनरेबल सी.एम. ने किया है (विघ्न) मै सिवाए अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी के उनके अच्छे क्रिटिसिजम को एक्सैप्ट करता हूं कि मै अपने हल्के मे नही जाता। जो आदमी डेमोक्रेसी मे हैल्दी क्रिटिसिजम को एक्सपैट न करे वह अच्छी बात नही है।

लेकिन मेरे वहां न जाने के वजह यह हैं कि मुझे पता नही है कि मै कांग्रेसी हूं या गैर–कांग्रेसी (शोर) मै तो बीच मे लटक रहा हूं। जब इसका फैसला होगा तक कांस्टीच्यूऐंसी मे जाऊंगा। (हंसी) स्पीकर साहब, जहां त क इंटेग्रिटी का ताल्लूक है मेरे पास तीन सर्टिफिकेटस है। that I am a man of integrity. No. 1, I hold that very certificate form my electorates which in the last session I commissioned in the rescue of my Chief Minister.

I was elected by over-whelming majority when the Hon. C.M. and when the Hon. Ex-C.M. both worked against me. I am here in spite of Bhagwat Dayal, in spite of Bansi Lal and in spite of Hardwari Lal. That is a clear certificate of integrity of political man from his constituency.

The second certificate with me is from a world renowned diplomat, His Excellency Chakravarty. I was a minister for eight months. Sir, in my time, I Challenge- that department is with Mr. Shyam Chand-that I was only Minister in India against whom not a single writ of Mala-Fide went to High Court in eight months. His Excellency is here. He complimented me “Whenever you wrote judgment, you were not a politician; you were a judge and you are an honest man”. When our term was over, Governor’s Rule came, file is there in the High Court; file is there with the Governor; my name was recommended by governor to be the first at the top. At that time, I was not dropped by the High Court because of any allegation against me. The exact words were, “He was a Minister yesterday. It is not proper that he should be a judge tomorrow. Let him settle in the profession”. And the latest recommendation which has gone to the Chief justice of India, I

have seen myself the advanced copy and I say with full responsibility that my name has been mentioned in paragraph No.1 as Senior Advocate. Under Section 16 of the Advocate's Act, one can be a Senior Advocate only if he is a man of integrity, ability and standing.

So I hold a certificate from my judges for being a man of integrity. I hold a certificate from my Governor. I hold a certificate from there and last of all, Sir, I make a challenge nobody has made it; I Make it, you are the custodian of our privileges, and I take you as my arbitrator. Le the hon. C.M., if he has got any instances of personal integrity against me refer them to you. I will give my explanation to you. You don't write any judgment. Tell me that something and my resignation is there. I am not very much proud of . . ..

श्री अध्यक्षः बस ठीक है। आप तशरीफ रखिए।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, यह क्या सवाल हुआ कि इन्होने कहा कि मेरे खिलाफ कोई चार्ज नही हैं।

श्री अध्यक्षः आप तशरीफ रखिए यह कोई डिस्कशन नही हैं।(शोर)

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, इन्होने कहा (शोर) कौन सी बात ठीक है आप इसका फैसला करें।

हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 31.12.1972 तक लिए ऋण दर्शाने वाला विवरण, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का वार्षिक वित विवरण (बजट अनुमान), 1972–73 तथा (संशोधित अनुमान),

1971–72, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के लेखों का चतुर्थ वार्षिक विवरण, 1970–71 तथा हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन पर चर्चा।

श्री अध्यक्ष: आप तशरीफ रखिये यह फैसले की बात नही है। इस बात का यहां कोई निर्णय थोडा ही होना है।

हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 31.12.1972 तक लिए ऋण दर्शाने वाला विवरण, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का वार्षिक वित विवरण (बजट अनुमान), 1972–73 तथा (संशोधित अनुमान), 1971–72, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के लेखों का चतुर्थ वार्षिक विवरण, 1970–71 तथा हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन पर चर्चा।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि रूल 79 यह कहता है कि जो आदमी नोटिस देता है, वह मूसर होता है। यह जो मैने नोटिस दिया है वह जिस समय मिनिस्टर साहिब ने बिजली बोर्ड की सालाना रिपोर्ट हाउसक की टेबल पर रखी ही थी कि मैने उसी वक्त कागज सैक्रेटरी साहब के पास भेजे। मेरा पहला मोशन था और उन्होने उसके सर्कुलेट भी किया हैं। जिसका लैटर नम्बर 25325–25404 है ओर इस पर सैक्रेटरी साहब के दस्तखत भी है तथा मेरा नाम दूसरे दिन तीन सदस्यों के साथ शामिल है। * ** * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * ** * * * * आज जो ऐजण्डा जारी हुआ हें

उसके अन्दर मेरा नाम ही नही है हालाकिं सर्कुलर के अनदर मेरा नाम है। आप कागज देख लें सब से पहले मैने मूव किया।

श्री अध्यक्षः ठीक है, मै देखता हूं। आप बैठियें।

चौधरी राम लाल वधवाः इसका मतलब है कि मूझे मूव करने के लिये और बोलने के लिये टाईम ही नही मिलेगा।

श्री अध्यक्षः जिन्होने मूव नही किया है उनको भी बोलने का टाइम मिलेगा ऐसी बात क्या है कि जो मूव करे वही बोले।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, रूल्ज की खिलाफवर्जी हो रही है।(शोर)

श्री अध्यक्षः मै देखता हूं कि यह क्या बात है। चौधरी राम लाल जी, आप यह चाहते थे कि इसके ऊपर डिसक्शन हों।

चौधरी राम लाल वधवाः जी हां।

श्री अध्यक्षः वह होगी।

चौधरी राम लाल वधवाः वह तो होगी लेकिन सवाल यह है कि जो आदमी मोशन का नोटिस देता है वह मूव करता है और उसकी फर्स्ट प्रायरिटी होती है।

श्री अध्यक्षः ठीक है, आप बैठियें, मै देखता हूं।

Chaudhri Phool Chand (Mullana-S.C.): Sir, I beg to move—

That the statement showing the loans raised by the Haryana Sate Electricity Board up to 31st December, 1972, Annual Financial Statement (Budget Estimate) for 1972-73 and (Revised Estimates) for 1971-72 of the Haryana State Electricity Board and the 4th Annual Statement of Accounts of the Haryana State Electricity Board for the year 1970-71, laid on the Table of the Vidhan Sabha on 6th March, 1973, be discussed.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 31 दिसम्बर 1972 तक लिए ऋण दर्शाने वाला विवरण, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का वार्षिक वित विवरण (बजट अनुमान), 1972—73 तथा (संशोधित अनुमान), 1971—72, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के लेखों का चतुर्थ वार्षिक विवरण, 1970—71 जो कि 6 मार्च, 1973 को विधान सभा की मेज पर रखे गए थें, पर चर्चा की जाए।

मेरे पास इसी प्रकार का एक और प्रस्ताव श्री सतराम दास बतरा, श्री जगजीत सिंह तथा श्री ओम प्रकाश गर्ग एम.एल. एज. द्वारा हुआ आया हे। यह प्रस्ताव भी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से ही संबन्धित है। अगर आप सहमत हो तो दोनो पर एक साथ ही विचार कर लिया जाए?

आवाजें: ठीक है जी।

मलिक सत राम दास बतराः मै प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन पर, जो 12 नवम्बर, 1973 को सदन की मेज पर रखा गया था, चर्चा की जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन पर, जो 12 नवम्बर, 1973 को सदन की मेज पर रखा गया था, चर्चा की जाए।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना–एस.सी.): स्पीकर साहब, सदन के सामने जो मोशन है यह बिजली बोर्ड द्वारा लिए गए कर्जों के बारे मे है। हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो 1970–71 का पीरियड है वह हरियाणा के इतिहास मे सुनहरी शब्दों मे लिखा जाने वाला है। हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इस वर्ष मे प्रत्येक गांव मे बिजली पहुंचाई और स्पीकर साहब, आपको ध्यान होगा कि इस साल के शुरू मे हमारे इस बोर्ड ने 3,367 गांवों केा बिजली दी थी लेकिन उसके बाद जितनी तेजी से काम हुआ यह सब को मालूम है। 6–7 महीनेां के अन्दर 30 करोड़ रूपये की लागत खर्च करके प्रत्येक गांव मे बिजली पहुंया दी और हमे इस बात के लिए फख्र हासिल हुआ है कि जो आखिरी गांव बिजली देने के लिये रहा था उसमे हमारी प्रधान मंत्री जी ने 29 नवम्बर, 1970 को स्विच आन किया और हरियाणा भर के अन्दर

प्रत्येक गांव और शहर मे बिजली टिमटिमाने लगी। वह समय एक ऐतिहासिक समय था। रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ स्पीकर साहब, 1970–71 के साल मे 18,229 ट्यूबवैल को बिजली दी गई और उस के बाद बिजली बोर्ड ने हरियाणा मे बिजली की सप्लाई को बढाने के लिए थर्मल प्लांटस और कुछ दूसरे प्लांटस लगाए। हमे यह बात कहते हूए कोई अतिशयेाक्ति नही होनी चाहिए कि बिजली बोर्ड ने नुमाया तरक्की की है, इन्होने जितनी तेजी सेक काम किया, जितनी काबलियत से काम किया उस का मान न केवल हरियाणा मे ही है बल्कि सारा हिन्दूस्तान उस को मानता है। साल 1971–72 मे बिजली बोर्ड ने जनरेशन के लिए थर्मल प्लांटस लगाए और जिन ट्यूबवैल्ज को पहले बिजली दी जा चुकी थी उन के अलावा 14,778 और टयूबवैल को बिजली दी और 2,636 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्ज और जोड़ दिए गए ताकि बिजली ठीक तरह सप्लाई की जा सके। इस के अलावा सन् 1973–73 के अन्दर बिजली बोर्ड ने और बहुत से ऐसे काम किए जो कि समय के मुताबिक जरूरी समझे गए। हमारे बिजली बोर्ड ने 1972 तक 3,819.487 लाख कर्जा लिया और उस के बाद 1972–73 मे भी कर्जा लिया लेकिन कर्जा लेने के बाद काम बहुत तेजी से हुआ इस मे कोई शक नही। स्पीकर साहब, इस के साथ साथ हमे एक बात कहनी होगी कि बिजली बोर्ड ने जो काम किए वह बहुत सराहनीय किए, उन्होने रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन करके, ट्यूबवैल को बिजली देकर सूबे का नाम ऊंचा किया। मै अर्ज करूंगा कि भाखड़ा मैनेजमैंट के चार स्टेशन है जिन से हमे पानी से तैयार

की हुई बिजली मिलती है, वह है भाखड़ा लैफ्ट बैंक पावर हाउस, भाखड़ा राईट बैंक पावर हाउस गंगूवाल पावर हाऊस और कोटला पावर हाउस। लेकिन मै समझता हूं कि इन मे से हमे उतनी बिजली नही मिलती जितनी मिलनी चाहिए। इसलिए मै अपने बिजली बोर्ड से कहुंगा कि इन पावर हाउसिज से जितनी जयादा से ज्यादा बिजली ले सकें उनको लेने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हरियापणा मे बिजली की शार्टेज पूरी हो सके। इस के अलावा स्अीम सिस्टम से चचलने वाले हमारे तीन थर्मल पावर हाउस हे, एक तो सूरजपूर थर्मल पावर हाउस है, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा यमुनानगर है। लेकिन मै समझता हूं कि यह काफी नही है। इन से जो हमें पावर मिलती है वह नाकाफी है। इसलिए मै बोर्ड को यह सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसा एक एक थर्मल पावर हाउस हर जिला मे बना दिया जाए, उस से बिजली की मांग काफी पूरी हो जाएगी और बहुत लाभ होगां, और जो ब्रेकडाऊन वगेरा होते है वह भी नही होगे। इस के अलावा स्पीकर साहब, डीजल से भी हमारे कुछ पावर हाउस बिजली जनरेट करते है। यह पावर हाउस दो तो अम्बाला जिला में है एक फरीदाबारद मे है, एक पानीपत और एक सोनीपत मे हैं। इन मे से दो डीजल से चलने वाली पावर हाउस बंद है। मै सूझाव दूंगा कि इन पावर हाऊसिंज को जल्दी से जल्दी चलाने की कोशिश की जाए। उन के चालू करने कसे हमे पावर सप्लाई मे बहुत मदद मिलेगी। स्पीकर साहब, हमारे प्रान्त मे पिछले दिनेा हमारी सराकर ने बहुत से ट्यूबवैल लगाए और उनको बिजली भी दी, इस मे कोई शक

की बात नही है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता हे कि समय पर उनको जितनी बिजली मिलनी चाहिए उतनी बिजली नही मिलती। जब हम देहातों मे जाते है तो हमे जगह जगह यह शिकायत मिलती है कि हमे टाईम पर बिजली नही मिलती और बिजली मिलने का कोई समय निश्चित नही होता। इसलिए मै सुझाव देता हूं कि हमें इतने रिसोर्सिज पैदा करने चाहिए जिस से कि लोगो का ज्यादा से ज्यादा और पूरी जरूरत के मुताबिक बिजली मिल सके। अगर हमारे ट्यूबवैल को बिजली पूरी मिलेगी तो अनाज ज्यादा पैदा होगा और हमारी जो अनाज की रिक्वायमैंटस है वह भी पूरी होगी। हमारे सूबे मे कोई एक लाख 16 हजार 82 ट्यूबवेल्ज है। मै बिजली बोर्ड को सूझाव दूंगा कि उनको पूरी बिजली देने का प्रबंध किया जाए। इस के अलावा देहातों मे जो बिजली के ब्रेकउाउन होते है उनको भी रोकना चाहिए चाहे वह इन्डस्ट्रियल परपज के लिए है चाहे एग्रीकल्चर परपज के लिये हों। इन ब्रेक डाउन्ज को बोर्ड को पूरी तरह से चैक करना चाहिए। यह ब्रेक डाउन्ज जो है यह तभी चैक हो सकेंगे जब हमारे थर्मल प्लांटस सुचारू रूप से काम करेगे। इस के अलावा जो बिजली की चोरी के केसिज होते है उनका पूरी तरह से चैक किया जाना चाहिए और जो चोरी करता पकड़ा जाए उसक को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि और कोई बिजली की चोरी करने की जरूरत न करे लेकिन ऐसी भी नही होना चाहिए कि बोर्ड का स्टाफ किसी की गलत रिपोर्ट करके उसक को हैरान करे। पावर एकसीडैंटस और बिजली की जो

लीकेज होती है उसको रोकने के लिए जितने अच्छे ढंग निकाले जा सकते हो निकाले जाए, ताकि बिजली जो बेकार चली जाती है वह बचाई जा सके और प्रोडक्टिव काम के लिए इस्तेमाल की जा सके। हमारा जो स्टाफ है, जो हमारे इंजीनीयर हे उन को इतने अच्छे ढंग से हमे यूटिलाई करना चाहिए जिस से वह हिम्मत से काम करे और उनके होसले बुलंद हो। ऐसा न हो जैसे कुछ साथी बताते है हमे कि दूसरी स्टेट मे तो बिजली इंजीनीयर रखा जाता है लेकिन हरियाणा मे बतौर जूनियर ट्रैनी रखा जाता है। मै सूझाव दूंगा कि ऐसा नही होना चाहिए। आप को ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे हमारे जो इंजीनियर है वे बाहर दूसरी स्अेटों मे न जाए और उनकी काबलियत का फायदा हमारी अपनी स्टेट को ही पहुंचे। इस के साथ साथ जितनी फेसिलिटीज हमारी सरकार ने बोर्ड को दी है उस के लिए मै अपनी सरकार को मुबारिकबाद देता हूं। सरकार ने बोर्ड को बहुत सा लोन दिया है और दीगर बहुत सी फेसीलिटीज दी है। मै बोर्ड को यह सूझाव दूंगा कि वे उस लोन को इतने अच्छे ढंग से खर्च करे जिससे कि हम कर्जे पर ही निर्भर न रहे बल्कि अपने रिसोर्सिज ऐसे बनाए जिससे हम अपने आयंदा के लिए कर्जे पर निर्भर न रहना पड़े क्योकि कर्जे पर निर्भर रहना ठीक नही होतो। हम अपने रिसोर्सिज को पूरी तरह एक्सप्लायट करके अपने पांव पर खडे हो और बिजली के बाम को इस ढंग से चलाये कि किसानो ओर इन्डस्ट्रीयलिस्टस को प्रोडक्विअ कामों के लिये सस्ते रेट पर बिजली मिलती रहे और हम इस कर्जे से भी जल्दी फारिंग हो

सके क्योकि कर्जे पर सूद काफी देना पड़ता है। मे समझता हूं कि शुरू शुरू मे कर्ज लेना जरूरी होता है लेकिन यह कर्जा जल्दी वापस कर देना चाहिये ताकि सूद का खाहमखाह बोझ न पड़े। स्पीकर साहब, अंत मे मैं एक बात कहना चाहता हूं और फख्र के साथ कहता हूं कि हमारा बिजली बोर्ड सारे देश मे एक नम्बर पर है ओर इस ने जो काम किये है और कर रहा है उसकी प्रंशसा न सिर्फ इस स्टेट मे होती है बल्कि सारे हिन्दूस्तान मे इस की तारीफ हो रही हैं। सरकार को यह बोर्ड पूरा सहयोग देता है और हमारी सरकार ने सारी दूनिया को साबित कर दिया है कि हमारे बोर्ड ने रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन मे मामले मे पहला नम्बर हासिल किया है। इन शब्दों के साथ मै कहना चाहता हूं कि हमारा बोर्ड हमारे राज्य की तरक्कीव के लिये दिन–ब–दिन ज्यादा से ज्यादा काम करे और जो कुछ कमियां है उनको दूर करके हमारे प्रान्त को और आगे ले जाये।

मलिक सत राम दास बतरा (कलानौर): स्पीकर साहब, हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है जिस ने एक छोटे से बजट से जो केवल 310 करोड़ का था गांव–गांव मे बिजली पहुंचा दी हे ओर गांव गांव को रोड्स से लिंक कर दयिा हैं। ऐसी तरक्की की मिसाल और किसी प्रांत मे नही मिलती है। स्पीकर साहब, पिछले दिनो भारत सरकार ने एक टीम हरियाणा के निरीक्षण के लिये आई थी और वह दूसरी स्टेट्स मे भी गई होगी। मैने भी उस टीम से मुलाकात की थी। उनका निरिक्षण करने का विषय यह ाि

कि क्या गांव मे छोअे किसानों जमींदारेा को बिजली के कनैक्शन सूवियाा से मिलते है या नही। मै भी उस टीम के साथ गांव गांव मे गया था और सारा सर्वे किया गया। कही ऐसी मिसाल नही मिली कि कनैक्शंज के लिये किसी अफसर ने डिल्ले की हो और कोई अड़चन पैदा की हो। यह ठीक हक कि हमारे प्रांत मे बदकिस्मती से सिवाये खादर बार के एरिया के बहुत सारे बैल्टस ऐसे है जहां परा पानी कड़वा है और पानी कड़वा होने की वजह से बिजली की वहां युटिलाईजेशन नही होती लेकिन कनैक्शनंज की कोई कमी नही है कि न मिल सके। खादर बार की जो बैल्ट है वह जमना के किनार–किनारे चलती है और इस मे खास तौर से करनाल का जिला आता है, कुछ एरिया जींद मे आता है, जिला अम्बाला और पलवल के इलाके भी आते है। इस सारी बेल्ट मे मीठा पानी मिलता है। लेकिन जिला महेंन्द्रगढ़ और रोहतक के कुछ इलाको मे पानी कड़वा होने की बजह से जमींदार ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने मे असमर्थ है। इसके अलावा अगर हरियाणा के मान चित्र को देखा जाए तो आप पाएगें कि महेन्द्रगढ झज्जर और फतेहाबाद बगैरा इलाकों की तरफ रेतीले टीले है। लेकिन अगर इजरायल जैसा देश अपने रेत के टिबबो पर कहां कहां से पानी ला कर खेती उपजा सकात हे तो हमार भी यह प्रतिज्ञा है कि हम भी इन रेतीले टिब्बो पर ुसल पेदा करेगे और जमींदार जो ऊंटो पर पीने के लिये पानी लाद कर दूर–दूर से लेाते है उनको खेती के लिये पानी मुहैया करेगे। अगर बोर्ड की इस रिपोर्ट की तफसील के साथ देखा जाये तो पता लगेगा कि

इस बोर्ड ने कितना सराहनीय काम किया है और देश मे एक नम्बर हासिल किया है। यहां पर 1971–72 मे 72,554 कनैक्शंज थे। इन मे डौमेस्टिक, कमर्शियल और इण्डस्ट्रीलिस्टस के कनैक्शंज शामिल है। 31 मार्च, 1973 को इन कनैक्शंज की तादाद 6,08,649 तक पहुंच गई। आप अंदाजा लगा सकते है कितनी ज्यादा बिजली की खपत हुई और कितने ज्यादा कनेक्शंज इतने थोड़े अर्सा मे दिये गये। (इस समय सभापतियों की सूची मे से एक सदस्य चौधरी ईश्वर सिंह पदासीन हुए)

फिर चेयरमैन साहब, आप देखे कि लाइनो कितना सुधार किया गया है। 1970–71 मे पर–कपिटा बिजली 52 युनिट थी, 1971–72 मे यह 108 यूनिट हो गई और अब 1973–73 मे पावर कट इतनी ज्यादा होने के बावजूद क्योकि बिजली का क्राइसिज आ गया था, भाखड़ा मे पानी की कमी की वजह से पर–कैपिटा 119 यूनिट तक पहूंच गई। आप देख सकते है कि कितना सराहनीय काम हुआ है। लाईन लौसिज मे जो सुधार लाया गया है। वह भी सराहनीय कदम है और जितनी एफीशैंसी इस बोर्ड ने दिखाई है वह काबिले तारीफ है। 1971–72 मे लाईन लौसिज 27 परसैन्ट थे लेकिन 1972–73 मे यह लौसिंज नीचे 23 परसैन्ट तक आ गये। खेती के कामो के लिये जितनी बिजली इस प्रांत मे उपलब्ध है उनती आज तक किसी प्रांत मे नही मिली है। 1971–72 मे खेंती के कामों के लिए 14 परसैन्ट बिजली दी जाती थी, 1972–73 मे यह बिजली 40 परसैन्ट दी गई और अब यह 45

परसैन्ट कर दी गई है। सारे हिन्दूस्तान मे कही ऐसी मिसाल नही मिलती जहां पर इतनी ज्यादा बिजली खेती के लिये दी गई हों यह ठीक है कि मैटीरियल की कमी है लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बोर्ड ने 30 सितम्बर, 1973 तक 3,348 टयूबवैल्ज के लिये और कनैक्शंज दिये है। यह बहुत ही सराहनीय बात है और मे इस काम की प्रशंसा किये बगैर नही रह सकता। इस बिजली को बढाने के लिये और उपाय भी सोचे जा रहे है ताकि इस की कमी न रहे चाहे क्राइसिज भी आ जाये। अभी अभी कृषि मंत्री जी फूडग्रेनह की बात कर रहे थक कि एकदम गर्म हवा चलने क वजह से फसलों को नुकसान हुआ। जब हरियाणा बना उस वक्त जा उपज होती थी और आज जो उपज हो रही है उसे देखें तो मै फख्र के साथ कह सकता हूं लामिसाल तरक्की हुई है ओर पैदावार कहा से कहां पहुच गई है। आप देखें 1966–67 मे हरियाणा मे अनाज की पैदावार 25.92 लाख टन थी, 1970–71 मे यह 47.71 लाख टन हो गई और और 1971–72 मे हमारी उपजल 45.46 लाख टन तक पहुंच गई। इस साल बारिशे न होने की वजह से और पावर कट लगने की वजह से 39.43 लाख टन उपज हुई है। यहां जमींदारो का, किसान भाईयों का अभी अभी फूड प्रोक्योरमैंट के मामले को लेकर काफी आन्दोलन चल रहा था और कुछ भाई उनको गुमराह करके उसे चलवाने की कोशिश कर रहे थें। मै जमींदार भाईयों से अनुरोध करूंगा कि वे बजाये इसके कि इन भाईयों के चक्कर मे पड़ें इस बात की मांग करे कि उनको अच्छे बीज, खाद मिले पानी मिले और बिजली की कटौती न करके

उनको पानी की सुविधाये दी जाये। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लैक्चरार हमे जो जो सूझाव दे, ट्रेनिंग दे, उन पर अमल करके हमे खेती को प्रोगेसिंव बनाना चाहिए और प्रोग्रेसिव तोर पर खेती करे। इस प्रकार अमल करने से मुष्े आशा है और जमींदारो से मै उम्मीद करता हूं कि वे प्रोडक्शन मे 30 मन फी हाई ईल्डिंग वैरायअी के बीज मुहैया हो, टाईम पर पानी मिले तो 30 मन फी किल्ले की वृद्वि होती है। अगर किसान को 30 रूपये फी मन के हिसाब से गंदम का भाव मिलता है तो 900 रूपये आय होती है। अगर इससे पिछले सालों की वृद्वि को देखा जाए तो इतनी बड़ी आमदन जमींदार को नही होती थी। मे जमींदार भाईयों से आग्रह करूंगा कि खेती की बढोतरी के लिए नये ढंगो को अपनाये और इस हिसाब से प्रोग्रैस करें तो मै उनको बधाई दंगा।

जब किसी चीज की कमी होती हे तो उसकी जुस्तजू मे, उसकी तलाश मे कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यह आप सब जानते है। भाखड़ा बिजली का एक बहुत बड़ा सैन्टर है जहां से हमें अधिकतर बिजली मिलती है। लेकिन किसी वजह से वहां से बिजली कम आने की वजहि से और फील्ड मे कंजम्पशन ज्यादा होने की वजही से हमे थोड़ी सी दिक्कत पेश आई है और इस को दूर करने के लिए बोर्ड जो नये उपाय कर रहा है, नये प्रोजैक्ट लगा रहा हैं, थर्मल प्लांटस लगा रहा हैं उसका ब्यौरा मै पेश कर रहा हूं।

भाखड़ा कम्पलैक्स से हमे बिजली और मिल गई है। 1967–68 मे हमारी पर–कैपिटा कंजम्पशन 57 यूनिट थी और 1972–73 मे यह बढ़ कर 119 युनिट तक पहुंच गई है और यदि हमे और बिजली मिल गई तो पर–कैपिटा कंजम्पशन और बढेगी। पावर बढाने के लिए बोर्ड ने कई उपाय सोचे है और आगे कदम बढा रहे है। भाखड़ा नंगल प्रोजैक्ट मे जो हमारा हिस्सा है, उसके अलावा फरीदाबाद मे थर्मल प्लांट लग रहा है। पिछले सैशन मे मेरे मोहतरिम दोस्त चौधरी चान्द राम जी इस बात पर एतराज कर रह थें कि बिजली के विस्तार करने से पहले सरकार ने इस बात को क्यो नही सोचा कि बिजली कम है। जब पानीपत का थर्मल प्लांट लगा दिया जाता तक कनैक्शन देते। इस पर मै अपने मोहतरिम दोस्त से कहुंगा कि जहां सरकार को रेलवे डिपार्टमैंट के साथ एग्रीमैंट करना होता है, भारत सरकार से इतनी मैगावाट बिजली पैदा करने के लिए मंन्जूरी लेनी होती है। कोल और माईन मिनिस्टर के साथ कोयले के लिए एग्रीमैंट करना पड़ता है वहां देरी होना जरूरी है। फरीदाबाद के दो यूनिट बहुत जलदी कमिशन हो रहे है और मेरा अन्दाजा है कि उन मे अन्दाजन 30 वैगन कोयला रोजाना लगना है। यदि फरीदाबाद और पानीपत मे जहां रोजाना इतना कोयला जलता है वहां हरियाणा सरकार को इस बात पर सोचना था कि भारत सरकार से कोयले की इजाजत मिले बगैर कैसे ये प्रोजैक्ट शुरू करे। यही वजह थी जिस के लिए यह काम देरी से शुरू हुआ। अब यह काम हो गया है और फरीदाबाद के ये दोनो यूनिट 60–60 मैगावाट के जल्दी ही

कमीशन हो रहे है और इन के बाद दो यूनिट और आ रहे हैं। पानीपत मे भी थर्मल प्लांट तैयार हो रहा है और मेझे उम्मीद है कि 1976–77 से पहले ही बोर्ड इसको तैयार कर दैगा। इन थर्मल प्लांटस मे 110 मैगावाट की फी–यूनिट बिजली पैदा होगी। इस तरह और यूनिटसा भी लगाये जा रहे है औ हम समझते है कि जब इन से बिजली उप्लब्ध हो जाएगी तो किसी जमींदार को यह शिकायत करने का मौका नही मिलेगा कि मुझे बिजली नही मिली है। वैस्टर्न जमुना कैनाल हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट, जो 45 मैगावाअ का है तैयार हो जाएगा जोकि गवर्नमैंट आफ इन्डिया के विचाराधीन है। ब्यास प्रोजैक्ट और पौंग डैम से 212 प्लस 40 मैगावाट बिजली पैदा होने की आशा की जा सकती है। बदरपुर थर्मल प्लांट चालू हो चुका है शायद इससे 1975 मे बिजली मिल जाए। इनके अलावा और कई प्रोजैक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। राणा प्रताप एटौमिक प्रोजैक्ट भी तैयार हो रहा हे। चेयरमैन साहब, नार्थ रीजन मे जिनती स्टेटे है उन मे बिजली का हमारा हिस्सा है। जम्मू–काश्मीर प्रोजैक्ट बन रहा है। उस से 50 मैगावाट बिजली हरियाणा को मिलेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना भारी बिजली का जो विस्तार हो रहा है। इसकी हमे जरूरत थी और बोर्ड ने हमारे लिए तलाश की है। इन प्रोजैक्ट्स से बिजली मिलने के बाद मै समझता हूं कि आयंदा बिजली पर कोई कट नही लगेगी और बिजली इतनी सप्लाई हो जाएगी कि चप्पा–चप्पा जमीन मे पानी लगने और ट्यूबवैल चलेगें। बोर्ड ने जो तरक्की की है, इतनी ज्यादा बिजली की जो उपलब्धि की है

इस पर मै बोर्ड को बधाई देता हूं। इसके साथ ही साथ जहां बिजली मे इतनी भारी तरक्की की है वहा मै बोर्ड के चेयरमैन साहब, से खास तौर पर इल्तजा करूंगा कि जो छोटी 11 के.वी. की लाईन है उससे जमींदारों को और ज्यादा कनैक्शन दे। इसके अलावा मै यह भी इल्तजा करूंगा कि जो अल्यूमिनियम की लाईने है वे गर्मी के दिनो मे आंधी आने से एक दूसरे के साथ टकराती हैं। ये लाईने ढीली होती है और ऐल्यूमिनियम की बनी हुई होने की वजह से पूरी तरह नही खीच पाती। खासकर गर्मियों के दिनों में जब आंधी चलती है और तारे एक दूसरे के साथ टकराती हैं तेा जमींदारो की मोटरे जलती है, मीटर जल जाते है। इस लिए मेरी इल्तजा यह है कि जहां से एंटरी शुरू होती हैं। वहां एक ग्रिड लगा दिया जाए ताकि बिजली रगुलेट होती रहे ताकि जब आंधी आये तो मीटर और मोटरे न जले। यह मेरा सूझाव है। मै बिजली बोर्ड की प्रशंसा करता हूं कि उसने थोड़े समय मे बिजली उपलब्ध करने के प्लांट लगाये है और सराहनीय प्रगति की है।

11.00 बजें

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): चेयरमैन साहब, बिजली बोर्ड की एनवल फाइनैंशल स्टेटमैंट (बजट एस्टीमैंट) 1972–73, (रिवाईज्ड एस्टीमैंट) 1971–72 और फोर्थ एनबल स्टेटमैंट आफ अकाउंटस हमारे सामने विचारधीन है। जहां तक बिजली का प्रश्न है, मेरे ख्याल मे विधान सभा मे इस पर बहुत डिस्कशन हो चुकी है, क्वैश्चन हो चुके है, शायद दो चार बातो

के और कोई बात रह नही जाती जो डिसकशन करने वाली हों। मै, अपोजीशन का एक सदस्य होने के नाते इस बात मे कंजूसी नही बरतूंगा कि अगर सरकार ने कोई अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा न करूं। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, इसने यह साहसपूर्ण कदम उठाया है जिनके परिणामस्वरूप सारे हरियाणा के अन्दर बिजली का फेलाव हुआ है, इस मे कोई शक की बात नही। लेकिन इस के साथ ही साथ बिजली के फेलाव के साथ साथ इसमे कई त्रुटियां रहा गई है। हमारे सामने एक ही सवाल आकर खड़ा होता है कि अगर किसी चीज को बनाने का ध्येय, लक्ष्य अच्छा हो लेकिन उसकी वर्किंग अच्छी न हो तो उस ध्येय का, लक्ष्य का कोई लाभ नही , वह फेल हो जाता है। आज बिजली की तारों का फेलाव हो रहा है लेकिन उन तारों मे बिजली नही है। मैने सवालो के समय मे, इस बात पर जब जब बात होती रही तो ये इस बात से इन्कार नही कर सके कि इन तारेां मे पूरे तौर पर बिजली नही दौड़ती और हम अपने प्रान्त मे जो हरित–क्रांति लाना चाहते थे वह नही ला सके, जितने जोरो के साथ हम इण्डस्ट्रीज का विस्तार करना चाहते थे वह नही कर सके और इसका कारण बिजली बोर्ड की वर्किंग की चीर फाड़ करने की आवश्यकता है। यह योजना जो हमारे सामने आई कि गांव गावं मे बिजली फेलनी चाहिए उससे पहले यह योजना बननी चाहिए थी कि बिजली का कर रहे है, जितनी तारें और खम्बे आज हम एक–एक गांव तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या उनके लिए हरियाणा के अन्दर उतनी पर्याप्त बिजली का उत्पादन है और क्या इतनी

बिजली के उत्पादन के लिए हमारे पास साधन है। ये दो बातें है जिनके ऊपर मै सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बात तो यह होनी चाहिए थी कि बिजली की तारों और खम्बो पर रूपया खर्च करने से पहले यह देखना चाहिए था कि आज जब हम बिजली के लिए भाखड़ा डेम और दिल्ली के ऊपर निर्भरप कर रहे है तो क्या हम सारे प्रान्त के अन्दर खेती के लिए और इण्डस्ट्रीज के लिए बिजली दे पायंगे। यह बात दिमाग के अन्दर रख कर चलना चाहिए था कि क्या इतनी बिजली का उत्पादन भाखड़ा कर रहा है, क्या वहा से और दिल्ली से हमे इतनी बिजली मिल रही है, रूपया कर्जा लेकर हरियाणा के अन्दर जो हम बिजली का फेलाव कर रहे है क्या उसका सही इस्तेमाल हो सकेगां, जितना बोझ आज हरियाणा सरकार ने और बिजली बोर्ड ने अपने ऊपर लाद लिया है क्या उसको हम चुका भी सकेगे?

चेयरमैन साहब, यह भी कोई शक की बात नही है कि अपने इस छोटे से प्रान्त के अन्दर दो बाते विशेषतः है नम्बर एक तो खेती है जिसके लिए सरकार ने यह बिजली का फेलाव किया और जिसके लिए आज इरीगेशन लिफ्ट स्कीम्ज और दूसरी नहरे वगैरा पानी देने के लिए चल रही है। जब मै रिपोर्ट की ओर देखता हूं तो ठीक है कि बड़ी खुशनुमा रिपोर्ट लिखी गई है। सरकारी दफतर के अन्दर बैठे हुए हजारों रूपये तनखाह लेने वाले मुलाजिम एक बड़ी खुशनुमा तस्वीर बनाकर हमारे सामने रखते है। होना भी चाहिए क्योंकि उनको तनखाह ही इसी बात की

मिलती है लेकिन देखना हमे यह है कि स्थिती इतनी गम्भीर हो चुकी है बिजली बोर्ड की वर्किंग हमे सोचने पर मजबूर करती है। इसको ठीक करने के लिए सरकार कैसे कदम उठाएगी। पिछले साल के आकड़े यही बताते है, सवालों के जवाब मे भी यह बताया गया है , चीफ मिनिस्टर साहब, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब और इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर साहब, इन तीनों से यह बात हाउस के अन्दर स्वीकार की कि खेती के लिए ट्यूबवैल चलाने के लिए और इण्डस्ट्रीज के लिए उतनी बिजली हम सप्लाई नही कर सके जितनी की आवश्यकता थी। पिछले दो साल के अन्दर इण्डस्ट्रीज की हालत तो बहुत ही खराब रही है। इसी सैशन के अन्दर जवाब देते हूए हमे यह बताया गया कि इतने लाख घंअे लेबर के जाया हुए है और इतना उत्पादन इंडस्ट्रीज के अन्उर कम हुआ है। इसका कारण केवल एक था। सरकार ने यह पग उठाते हुए लोगो को हद से ज्यादा प्रोत्साहित किया था। इन्होने कहा कि आपको बिजली इतनी मात्रा मे मिलेगी जिसका कोई हिसाब नही। आप खड़े होकर हरियाणा की प्रगति के लिए काम करेा। हरियाणा की जनता प्रगति करने के लिए उत्सूक थी। उसने मेहनत की, उसने कर्जे लेकर के ट्रैक्टर्ज खरीदें, दूसरी मशीनरी खरीदी, खाद और बीज उन्होने ब्लैक मे खरीदी लेकिन नतीजा क्या हुआ कि वह बीज और खाद, जब पानी नही मिला, जमीन के अन्दर सड़ कर रह गए। इण्डस्ट्रीज का फेलाव भी हरियाणा के अन्दर लोगों ने जोर शोर से किया लेकिन स्थिती यह हुई कि जब मजदूर बैठे होते थे तो बिजली गायब होती थी और जिस समय बिजली मौजूद होती

थी तो लेबर की छूटटी हो जाती थी क्योंकि न बिजली के आने का वक्त था और न बिजली के जाने का वक्त था। इसी तरह से चेयरमैन साहब, डौमेस्टिक कंजप्शन के अन्दर भी बिजली की कटौती होती रही। जब स्टूडैन्टस के पढने का वक्त होता था तो शहरो के अन्दर ब्लैक आउट हुआ करता था। तो चेयरमैन साहब, ऐसी स्थिती बिजली की रही है जिसकी वजह से मै तो यह कहूंगा कि सरकार ने तो बड़ा उत्साहजनक कदम उठाया था लेकिन बिजली बोर्ड उस योजना का चलाने मे पूरे तौर पर नाकामयाब रहा है और स्थिती इतनी गम्भी हे कि मै कहूंगा कि –

एक दिन की बात हो तो इसे भूल जाएं हम,

नाजिल हो दिल पे राज बलाए तो क्या करें?

नित्य प्रति की मुसीबरत बिजली की हमारे सामने खड़ी हो गई है। जिसके ऊपर हरियाणा का जीवन निर्भर करता है उसके लिए करना क्या चाहिए था? चेयरमैन साहब, मै बताना चाहता हूं कि जितना रूपया यश प्राप्त करने के लिए, खाली एक मिसाल कायम करने के लिए हरियाणा इलैक्ट्रिसीटी बोर्ड ने देश के अन्दर एक बहुत बड़ा कार्य किया है गांव गावे मे बिजली के खम्बे और तारें फेलाकर, खर्च किया है, उसकी अपेक्षा चाहिए तो यह था कि उससे पहले ये योजना बनाते कि एक एक सैक्टर बनेगा जहां बिजली पैदा होती। उस उत्पादन को देख करके, उस शक्ति को देख करके ही बिजली के खम्बों और तारों का फेलाव

किया जाता। आज मैने रिपोर्ट के अन्दर जब पढा तो उसमे लिखा हुआ है कि फरीदाबाद का थर्मल प्लांट 1974 मे मुकम्मल होने की संम्भावना है। मै नही कह सकता कि उस वक्त तक जरूर की कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि स्वयं ही बिजली बोर्ड की रिपार्ट कह रही है कि मुकम्मल होने की संभावना है। पानीपत थर्मल प्लांट भी अभी जेरे तामीर है। वह कब मुकम्मल होगा हम कह नही सकते। इसका मतलब तो यह हुआ कि हम जो चाहते थें कि हरी क्रान्ति आनी चाहिए, यहां एग्रीकल्चिरस्टस हिम्मत और उत्साह के साथ अधिक से अधिक उपज पैदा करें, किसान खुशहाल हो, इण्डस्ट्रीजलिस्टस खुशहाल हो, वह बात अब नही हो सकेगी। इस बिजली बोर्ड की गलत निति के कारण हमे कई सालों तक बहुत भारी नुक्सान उठाना पड़ेगा और प्रान्त को बहुत भारी धक्का लगेगा।

चेयरमैन साहब, मै अब सदन का ध्यान उन कर्जो की और दिलाना चाहूंगा जो कि इस बोर्ड ने लिए है। मेरे पास यह बड़ी लम्बी चौडी स्टेटमैंट है। इसका शीर्षक है–

Statement showing the loans raised by the Haryana State Electricity Board up to 31st December, 1972 for which the State Government have stood guarantee for repayment thereof under Section 66 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

कितनी निराशाजनक स्थिती है कितनी गम्भी स्थिती है इस बिजली बोर्ड की , मै उनके आंकड़े से ही यह आपको बताने

की कोशिश करूंगा। इसके अन्दर यह बताया गया है कि कहां कहां से और किन किन सोर्सिज से बिजली बोर्ड ने रूपया लिया है। मै सारी स्टेटमैंट न पढ़ करके उसमे से पहले दो चार केसिज ही बताऊंगा क्योकि उनसे ही सारे केसिज की स्थिती आपको मालूम पड़ जाएगी।

यूनाइटिड कमर्शियल बैंक से मीडियम टर्म लोन 50 लाख रूपये लिया गया है। यह लोन 29 अगस्त, 1969 को स्वीकार हुआ। इस स्टेटमैंट के अन्दर चेयरमैन साहब, हमारे से एक बात छुपाई गई है। यह कर्जा किस वक्त हासिल किया गया यह फैक्ट इसके अन्दर नही है। तो इस स्टेटमैंट के अनुसार इरीगेशन एंड पावर डिपार्टमैंट की सैक्शन का जो नम्बर तथा तिथी है उसके लेकर ही मुझे चलना पड़ेगा। यह कर्जा 29 अगस्त, 1969 को स्वीकार हुआ। हो सकात है कि दो चार महीने के बाद यह कर्जा ले लिया गया हो क्योकि इनता ही उसके अन्दर अन्तर पड़ सकता है तो ये पचास लाख रूपये के लोन इन्हे पांच साल के अन्दर वापिस करने चाहिए थे। ये जो स्टैटमैंट हमे दी है इसमे एक कालम है पीरियड आफ री–पैमैंट आफ लोन, उसमे पांच साल का टाईम दिया हुआ है। इसके साथ ही दूसरा कालम है अमाउन्अ पेड बैंक अप–टू 31 दिसम्बर, 1972 बायी दी हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड यानी 31 दिसम्बर, 1972 जो पैसा वापिस किया है वह 7.50 लाख है औ जो बैलेन्स आउटसेटैडिग दिखाया गया है वह 42.50 लाख लिखा है। इसका मतलब यह था कि यह

जो पचास लाख रूपया था यह 10 लाख रूपया प्रति वर्ष के हिसाब से वापिस किया जाना चाहिए था। यदि यह मान लिया जाये कि यह लोन 28 अगस्त, 1969 को सैक्शन हुआ हे और उसी साल के एन्ड मे ले लिया होगा तो सन 1970–71, 1971–72 और सन् 1972–73 तक तीन सालो के अन्दर केवल साढे सात लाख रूपया वापिस हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि दस लाख की बजाए केवल अढाई लाख रूपया साल का दे पाए है। इसी प्रकार से जितने भी लोन केसिज है, इनकी लम्बी चौडी़ लिस्ट है कोई 29 केसिज की लिस्ट हमारे हाथ मे है। मुझे इन 29 केसिज मे से एक केस भी ऐसा नही मिला, ऐसा नही पाया जिसके अन्दर बिजली बोर्ड ने लोन की अदायगी पूर्ण रूप से की हो। एकाध केस तो पाता, लेकिन कोई भी नही मिला। इसके अन्दर चेयरमैन साहब, एक और दिलचस्प बात है वह है रेट आफ इन्ट्रैस्ट के बारे में। जैसा कि मैने पहले केस मे बताया है उसमे रेट आफ इन्ट्रैस्ट सवा आठ परसैन्ट है और साथ ही रिबेट भी दिया हुआ है। इसी तरह से इस स्टेटमैंट मे जितने भी केसिज है सब मे, मोस्टली केसिज मे रेट आफ इन्ट्रैस्ट भी मुकरर्र किया हुआ है और उसके साथ रिबेट का भी प्रोवीजन हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बिजली बोर्ड समय पर कर्जे की अदायगी नही करता है तो उसको वह रिबेट नही मिलेगा। कर्जा देते वक्त लाईफ इन्श्योरेन्स तथा बैंक वगैरह इसीलिए कन्डीशन लगाती है कि उसका लोन सेफ रहे और लौन की अदायगी किश्तवार समय पर मिलती रहे। इसका परिणाम यह निकला कि बिजली बोर्ड ने स्टैट के रेव्न्यू पर, वक्त

पर किश्त न दे कर एक बोझा डाला है जो रिबेट हर केस मे समय पर इन्सटालमैंट देने पर मिलता वह अब नही मिल सकेगा।

चेयरमैन साहब, इसमे एक बात और नही आयी जो कि एग्रीमैंट के अन्दर बिजली बोर्ड ने उन बैंकस से और लाईफ इंशोरैन्स से लाजमी की होगी। अगर बिजली बोर्ड इन्स्टालमैंट टाईम पर नही देता है तो पैनल इन्ट्रैस्ट भी चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि बिजली बोर्ड की कारगर्दगी निराशाजनक हैं। वेसे ये क्रेडिट लेने की गर्ज से, अपनी सराहना करवाने और प्रशंसा करवाने की बाते करलें कि हमने सारे हरियाणा के अन्दर बिजली का फेलाव कर दिया है और कर रहे है। परन्तु उसकी वर्किंग इतनी निराशाजनक है कि जिस कार्य के लिए रूपया मांगा गया था वह समय पर नही दिया जा सका।

चेयरमैन साहब, इसके साथ ही साथ मै यह भी बताना चाहता हूं इस स्टेटमैंट के मुताबिक बिजली बोर्ड के ऊपर कुल कितना कर्जा है। बिजली बोर्ड खाली यश प्राप्त करने के लिए इतना फेलाव कर रहा है। आज जो फिग्र्ज फाईनैशियल स्अेटमैट के मुताबिक है उसके अन्दर पेज चार पर टोटल दिया हुआ है। 3,319.443 लाख रूपया यानी 3,3319 लाख रूपया आज हरियाणा बिजली बोर्ड पर कर्जा है। यह इन्ही की दी हुई स्टेटमैंट के मुताबिक है जो हमे स्पलाई की गई है।

चेयरमैन साहब, इसके साथ–साथ मै यह भी अर्ज कर दूं कि जो एनयूल फाईनैन्शल स्टेटमैंट आया है उसके पेज 17 पे दिया हुआ हे कि 1,476 लाख रूपए का लोन बिजली बोर्ड ने गवर्नमैंट से लिया हुआ है। टोटल लोन जो बिजली बोर्ड ने लिया है वह 4,795 लाख रूपए बनता है। खर्चे को निकाल करके उसमे कुछ भी नही बचा है। चेयरमैन साहब, इतनी लम्बी चौडी स्टेटमैंट इस मोटी फाईल के अन्दर दी है।। इस मोओ रिपोर्ट को जो हमे दी गई हैं, मैने बड़े ध्यान से पढा है। यह रिपोर्ट रात को हमारे पास पहुंची थी। सारी रात इस पर खर्च करके, एक–एक सफे को पढने के बोद मुण्े ऐसी निराशा हुई कि रात यों ही समय नष्ट किया। चेयरमैन साहब, सारी स्टेटमैंट के अन्दर एक सफा बड़ा ही उल्लेखनीय है, उसके अन्दर जो एनुअल फाईनैन्शीयल स्टेटमैंट पेज 17 पर इस मोटी किताब मे दी गई है, उसमे रैवन्यू रिसीट एण्ड रैवेन्यू एक्सपेंडीचर अस्टीमैट्स सन् 1971–72 और सन् 1972–73 इस प्रकार से दिये गये हैः–

बजट एस्टीमैटस सन् 1971–72 का 1806 लाख रूपए और फिर वही सन् 1971–72 का बजट एस्टीमेटस 1973 लाख रूपए दिया हुआ है जो सन् 1972–73 का लेटैस्ट बजट एस्टीमैंटस दिया है वह 2,243 लाख रूपए दिया है यानी यह 1972–73 के रैवैन्यू एस्टीमेट्स के मुताबिक 2,243 लाख रूपया है जो हमे बिजली से रैवैन्यू मे प्राप्त हुआ है। जो वर्किंग एक्सपैन्सिज सन् 1972–73 का लिखा है वह 1,169 लाख है और जो ग्रोस इन्कम

हुई है वह 11074 लाख हुई है लेकिन चेयरमैन साहब, इस 1,074 लाख को उन्होने किस तरह से डिस्ट्रिब्यूट किया है वह भी देखिए–

	1972–73
Depriciation and Ganral Reserve Interest on: -	453
(i) Loan from Institutional Investeros	298
(ii) Government Loan	323

इसी प्रकार से यह टोटल 1,074 लाख बन जाता है। इन्होने यह पूरा करने के लिए अपनी तरफ से फिग्र्ज घढ दी हैं। चेयरमैन साहब, मेरे पास इस समय अकाउटैंट जनरल की आडिट रिपोर्ट तो नही है लेकिन इन्होने यह जो डेप्रिसियेशन लिखा है यह बहुत ही कम लिखा है। मेरा भी वास्ता मशीनरी से पड़ता है इसलिए यह जो 453 लाख डिप्रिसियेशन दिखाया है यह बहुत ही कम है। अब तो मै इसे ही मान कर चलूंगा क्योकि इन्होने अपनी रिपोर्ट मे लिखा हैं। अगर आडिट रिपोर्ट होती तो वाकई ही इससे ज्यादा ही होता। 1,074 लाख रूपये का डेफिसिट न दिखा कर इन्होने अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया है इसे सही मान कर चले तो चेयरमैन साहब, यह कहना पड़ेगा कि हरियाणा बिजली बोर्ड की गलत योजना और गलत नीतियों के कारण ही यह इतने कर्जे के नीचे दबा हुआ है। हरियाणा का मुख्यमंत्री और यह

सरकार और बिजली बोर्ड का चेयरमैन साहब, अपने वक्त मे बेशक यश प्राप्त जाए लेकिन आने वाली कोई सरकार इस कर्जे के निचे दबी ही रहेगी। सालों तक उसके पास इस कर्जे का वापिस करने के साधन नही होगे।

यहां जो यह कहा जा रहा है बिजली का उत्पादन बढेगा जब थर्मल प्लांट चालू हो जाएगा। वह योजना बन जायेगी, यह योजना बनेगी, यह तो सब शेखचिल्ली वाली ही बाते है। उस वक्त उससे कितना रैवैन्यू आएगा, कितना बिजली का उत्पादन बढेगा और सरकार उस बिजली को किस तरह दे सकेगी यह तो उसी समय ही पता लगेगा।

चेयरमैन साहब, आज हरियाणा बिजली बोर्ड पर 4,795 लाख रूपये का कज्र है। फाईनैन्सल स्टेटमैंट के मुताबिक उसके पास देने के लिए कोई भी पैसा नही है। यह हालत है आज इस बिजली बोर्ड की। मैने इस बिजली बोर्ड की सारी कारकरदगी की फिग्र्ज सदन मे रखी हैं जिस पर यह सरकार फख्र करती है इस तरह जो इण्डस्ट्रीज मे काम करने वाले है उनको भी काम नही मिलेगा। इस तरह न इण्डस्ट्रीज को पूरे वक्त बिजली मिल सकेगी और न ही जो जरायत मे तरक्की करना चाहते है बिजली से पानी दे सकेगें। जो हमने लोन ले कर इस बिजली बोर्ड पर खर्च किया है उसको वापिस देने के लिए भी इसके पास कोई प्रोविजन नही हैं। यह है छोटी सी तस्वीर जो मैने हरियाणा बिजली बोर्ड की वर्किंग के मुताल्लिक आपके सामने रखी है। इससे ज्यादा

विश्लेशण मै इसका करना नही चाहता। दो एब बाते और है जिनकी ओर मै सदन का ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि सरकार को किसी भी तरह से यह बात बैठ कर सोचनी चाहिए कि वह इस प्रकार की स्थिती को कब तक चालू रख सकेगी। आज किसान की कमर टूट रही है। किसान को आज खाद ब्लैक के अन्दर मिलती है। किसान को आज मशीनरी बहुत मंहगी मिलती है। आज उसके ट्यूबवैल जो है, वे भी बन्द पड़े है। आज उनको पूरे घन्टे बिजली मिलती नही है और अगर मिल ती भी हे तो कम मिलती है या वक्त पर नही मिलती। इसके लिए सरकार को एमरजैंसी बेसिज पर कोई इस प्रकार की योजना, कार्यक्रम बनाना चाहिये जिससे कि किसान की तकलीफ कम हो सके। इसके साथ ही मेरा कहना यह है कि जितनी बिजली उसको मिलती है उसकी वोल्टेज का कोई पता नही लगता। किसी समय तो इतनी बिजली आती है कि झटका लगता है और मोटर का फ्यूज ही उड़कर कही दूर जाकर गिरता है और किसी समय इतनी कम बिजली आती है कि मोटर धू–धू करके रह जाती है और बन्द हो जाती है। इस लिए इस वोल्टेज को भी किसी एक लेवल पर लगाकर रखना चाहिए ताकि जितनी भी किसान को बिजली मिलती है, उसका वह सही रूप से उपयोग कर सके। चेयरमैन साहब, एक बात जो मैने पिछली बार भी कही थी, अब फिर कहना चाहता हूं। कि बिजली बोर्ड के अन्दर बहुत धांधली है। आज भी हमारे पास इस प्राकार की शिकायतें आती है। हमने इस सदन के द्वारा सरकार से इस बात को अनुरोध भी किया था कि सरकार इस बात

की छानबीन क्यो नही करती कि बेचारा किसान, जो अनपढ है जिसको पूरी समझ नही है उसके पास चाहे उसने पूरा महीना बिली चलाइर्द ही न हों, बिल चला जाता हैं और अन्धा धुन्ध यह सब होता रहता है। जब वह बेचारा बिल लेकर दफ्तर जाने लगता है तो पहले तो उसकी दफ्तर के अन्दर घुसने की जरूरत नही होती, अगर किसी तरह से दफ्तर मे घुस भी जाए तो उसकी कोई सुनवाई नही करता, कोई उसकी बात नही सुनता। उसको कहा जाता है कि पहले जाकर पेसे जमा करवाओ, उसके बाद दरखास्त दे देना, फिर तुम्हारी सुनवाई होगी, फिर देखेगें। इसमे किसकी गलती है? वह बेचारा क्या बता सकता है कि गलती कहा पर है? बिजली के देने वाले भी वे है, बिजली का बिल बनाने वाले भी वे है, गलती को चैक करने वाले भी वे हैं, इसलिए उसकी कोई नही सुनता। हमने पिछली दफा भी यह सलाह दी थी कि पंजाब पैटर्न पर एक लम्प–सम रेट मुकरर्र होना चाहिए और किसान को उस रेट के अनुसार बिजली मिलनी चाहिए।

इसके साथ ही आज किसान ट्यूबवैल के कनैक्शन मांगता है। सरकार द्वारा यह माना गया है, इस सदन के अन्दर कवैश्चन आवर मे कि बहुत सी ऐप्लीकेशन्ज पैंडिंग पड़ी है ओर वह मैटीरियल की कमी के कारण पड़ी है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वह किस प्रकार से उन किसानो को ट्यूबवैल के कनैक्शन देने मे सफल हो सकती है। इसके अलावा आज एक और गम्भीर स्थिती इस बिजली बोर्ड की वर्किंग के

अन्दर है, जिसकी ओर मै सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कोई भी अदायरा, कोई भी इंसटीच्यूशन, कोई भी कारोबार, इस यूग के अन्दर बिना ऐम्पलाईज की सहायता के, ठीक रूप से कामकाज नही कर सकता। आज सरकार ने इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट ऐक्ट बनाए गए हे लेबर डिस्प्यूट के बारे मे और बहुत से कानून बनाये गये हे। यह सब इसलिए बनाए गए है ताकि हमारा जो ऐम्पलाईज का तबका है, हमारा जो मेहनतकश तबका है, हमारे जो फैक्टरी के अन्दर और दूसरे अदायरों या इन्स्ओच्यूशन के अन्दर काम करने वाले मुलाजिम है, उानके साथ अन्याय न हों। उसके साथ ज्यादती न हो। उसकी जो मांग है उसकी जो जायज मेहनत है वह उसको मिले। हरियाणा के अन्दर बिजली बोर्ड के कर्मचारी आज लगातार एक साल से स्ट्राईक कर रहे है, जलूस निकाल रहे है। जलसे कर रहे है, मांगे पेश कर रहे है, मैमोरैन्डम दे रहे है लेकिन हालत यह है कि आज के दिन तक भी , हालाकि वह पिछले साल से लगातार इस बिजली की जान का रो रहे है और चिल्लाते है, दूसरे लोगो के सामने अपनी आवाज बुलन्द करते है लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नही। इनकी मर्जी है भले ही न सुने। मै नही कहता कि इस चलज के अन्दर कितनी सच्चाई है लेकिन यह एक मैम्गोरैंडम बिजली कर्मचारियों की तरफ से सारे विधान सभा के सदस्यों को दिया गया है उसके अन्दर जहां तक मैने पढा है। उनकी मांग एक ही है।(व्यवधान)

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha): Sir, is Mr. Ram Lal adderssing the audience or the Hon'ble Chair?

श्री सभापतिः चौधरी साहब, आप चेयर का ऐड्रैस करें। आप जल्दी से अपनी स्पीच वाईन्ड–अप कीजियें।

चौधरी राम लाल वधवाः बहुत अच्छा जी। मै सिर्फ दो मिनट और लूंगा। मै यह कह रहा था कि बिजली कर्मचारियों ने इस मैमोरैन्डम के अन्दर एक ही बात कही है। वैसे तो यह बहुत लम्बा–चौड़ा है, लेकिन उनकी एक ही बात मुझे जंची है ओर वह यह है कि जुलाई 1972 के अन्दर कोई ऐग्रीमैंट बिजली कर्मचारियों का बिजली बोर्ड के साथ हुआ था। आज उनकी यह शिकायत है कि उास एग्रीमैंट पर पूरी तरह से अमल नही हो रहा। उस पर अमल न होने के कारण, चेयरमैन साहब, जो स्थिति उत्पन्न हुई और आज जिसके कारण बिजली कर्मचारियों को इतनी बेचैनी है, वे इतनी ऐजीटेशन कर रहे है, उसके बदले उनको क्या दिया गया है? बजाये इसके कि सरकार उनकी बात को बैठकर ध्यान से सहानूभूतिपूर्वक सूनती, उसने उनको ऐजीटेशन करने पर मजबूर किया। जैसे प्राईवैट आदयरो के अन्दर काम कने वाले मुलाजिमों और मालिकों के लिये यह व्यवस्था है कि केस इण्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल को भेज सकते है, केस को लेबर–कोर्ट मे भेज सकते हैं वैसे ही क्या सरकार बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिये भी कोई ऐसा कमिशन मुकरर्र नही कर सकती ताकि जो बिजली बोर्ड और बिजली कर्मचारियों के अन्दर

खीचातानी और बेचेनी है, उसका पता लगाया जा सके यह क्यों पैदा हो रही हैं औरप उसको समाप्त किया जा सके। इसके बदले मे होता क्या है? आज उनके ऊपर झूठे केसिज बनाये जा रहे है और उन्हे पकड़–पकड़ कर जेलो के अन्दर फेका जाता है। आज अगर कोई यूनियन का ओहदेदार सामने आने की कोशिश करता है तो उसे नौकरी से बर तरफ किया जाता है। महात्मा गांधी का नाम लेकर सोशलिजम की बात करने वाली यह सरकार बिजली कर्मचारियों को इस प्रकार से तंग करके क्या समझती है कि वह उनकी अवाज को बन्द कर देगी? कम से कम उन्हे इस बारे मे तो ध्यान करके चलना चाहियें कि उनकी जायज डिमान्डे है अगर सरकार यह समझती है कि कर्मचारी गलत है तो उसके लिये कोई आर्बीट्रेटर मुकररे कर सकती है जो यह सामने आनी चाहिए। सदन को कोई भी मैम्बर कर्मचारियो की स्पोर्ट करने के लिये खड़ा नही होगा। इस सब का परिणाम क्या हुआ है? इससे नुक्सान न तो बिजली बोर्ड को होगा, न चेयरमैन साहब, को होगा, न उनकी तनख्वाह कम होगी (बोर्ड के चेयरमैन की)। इससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नही है। ऐसे हथकण्डो से सरकार भले ही कर्मचारियों को दबा हडताल से, स्ट्राईक से, जहा बिजली का संकट पहले ही खड़ा है, अगर उसकी वर्किंग ठीक तरह नही होगी तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी और जो नुक्सान होगा, उसका सारा बोझ जो है वह जनता के ऊपर आकर पड़ेगा। इसलियें, चेयरमैन साहब, मै आपके द्वारा एक ही बात कहना चाहूंगा और वह यह कि सरकार इस मामले को जल्दी से सुलझाा

लें जहां एक और बिजली का संकट है, वहां दूसरी ओर बिजली बोर्ड की वर्किंग इतनी धिनौनी है, इतनी निराशाजनक है कि मेंरा सरकार से निवेदन है कि बिजली बोर्ड और बिजली कर्मचारियों के झगड़े मे जनता को और न फंसाया जाये। इतना ही कह कर मै अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी मेहर चन्द (बडौपल): चेयरमैन साहब, मेरे माहतरिम दोस्त ने एक बात तो यह कही कि ''नाजिल हो रोज बलाये तो क्या करे''। यह उनका नतरिया है? पब्लिक के ऊपर कोई बला नाजिल नही है। क्योद्य मूझे एक बात याद आ गयी, चेयरमैन साहब, । Everything looks pale to the jundiced eye.

खता जू हर भली शै मे बुराई ढूढ लेता है,

चमन मे भी निगाहे जाद पड़ती है गिलाजत पर।

हम करें तो क्या करें? इनकी नजर तो गन्दगी के सिवाय कहीं जाती ही नही। खुशबू लेना चे जानते नही है। बिजली बोर्ड गरीब का कसूर क्या है? चेयरमैन साहब, क्या बिजली बोर्ड का यही कसूर है कि उसने सारे हरियाणा को जगमगा दिया। मेरे मोहतरिम दोस्त ने यह कहा कि बिजली बोर्ड ने इतना पैसा खर्च कर दिया। मै अपने दोस्त से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास कोई जादू की टोकरी है कि बगैर पैसे खर्च किए कोई चीज बन जाती है। उन्होने यह हिसाब तो लगा लिया कि कैपिटल एक्सपैंडीचर बिजली पर इतना हो गया लेकिन उन्होने इस बात को

ऐनेलाईज नही किया कि बिजली बोर्ड ने कितना काम किया है। मेरे दोस्त एक साईड पिक्चर पेंट करते है। वह सिर्फ नुक्ताचीनी करना ही जानते हे यह सिर्फ क्रिटिसीज्म फार दी सैक आफ क्रिटिसीज्म है। मै उनसे यह पूछना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड को सिर्फ यह कसूर है कि उसने मई, 1968 से लेकर जुलाई 1973 तक 90 हजार ट्यूबवैल को अनराइज किया और इन 90 हजार ट्यूबवैल से हरियाणा के अन्दर अब नौ लाखउ एकड़ भूमि की अनरजाइज किया और इन 90 हजार ट्यूबवैल से हरियाणा के अन्दर अब नौ लाख एकड़ भूमि की आबपाशी होती है। क्या कभी उन्होने सोचा है कि इस नौ लाख एक्ड़ भूमि की आबपाशी से हरियाणा के जमींदारे की फाईनैन्शल पोजीशन कितनी सुधरी है। यह जमींदारो के बारे मे तो तब सोंचे जब कि इनको उनसे कोई हमदर्दी हो। चेयरमैन साहब, मै कह रहा था कि नौ लाख एकड़ मे आबपाशी बढ़ी है और खास आदमी जिम्मेवार नही बल्कि मै इस काम के लिए बिजली बोर्ड के सारे कर्मचारियों को दाद देता हूं कि उनकी मेहनत से हरियाणा की स्थिती मे इतनी इम्प्रूवमैंट हो गई। आपने कैपिटल एक्सपैंडीचर तो बता दयिा लेकिन यह नही बताया कि हरियाणा की आमदनी कितनी बढी़ हैं। मै कहना चाहता हूं कि इससे हरियाणा की 250 करोड़ रूपया सालाना की आमदनी क्या सरकार के अच्दे कामों की दाद देने का यही तरीका है? क्या अच्छे कामों को इस तरह से क्रिटिसईज किया जाता है?

इसके अलावा चेयरमैन साहब, हरियाणा के बिजली बोर्ड का एक और भी कसूर है कि पहले जहां बिजली की पर–कैपिटा कंजम्पशन 48 यूनिट थी वह अब बढ़कर 108 यूनिट हो गई है, क्या यह भी बिजली बोर्ड का कसूर है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का कसूर है, कांग्रेस पार्टी का कसूर है जोकि हरियाणा प्रान्त को तरक्की की तरफ ले जा रही है? इसके अलावा चेयरमैन साहब, यहा एक और बात कही गई है कि बिजली के लिए साधन नही किए गए। मै उनसे पूछना चाहता हूं कि कैसे नही किए गए। मेरा ख्याल तो यह है कि जिस आदमी को हाथ सदा जेब मे रहता है उनकों तो सिर्फ पैसा नजर आता है। ठीक बात है हमे पैसे के अलावा और भी बात देखनी है, लोगो की खुशहाली भी देखनी हैं। पहले हरियाणा मे साढे तेतालीस करोड़ यूनिट बिजली की खपत थी ओर आज बिजली की खपत 108 करोड़ यूनिट की है। यह बढोतरी कोई आसमान ने नही हुई। यह सारी बढोतरी बिजली बोर्ड ने की है। मै दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बढोतरी का सारे का सारा क्रेडिट हरियाणा बिजली बोर्ड को जाता है। जितने भी मैने आकड़े दिए है इनका मतलब है कि हरियाणा तरक्की के रास्ते पर जा रहा है, यह तरक्की की निशानी है। मुझे खुशी होगी कि इस बिजली बोर्ड को ओर भी सहूंलियते दी जाए क्योकि जितना काम, जितना बढावा हरियाणा की इकानामी मे बिजली बोर्ड ने किया है, हरियाणा के किसी और शोबे ने नही किया। यह मै दावे के साथ कह सकता हूं ओर इसके लिये मै हर तरह से क्रास एग्जामिनेशन के लिए तैयार हूं। मै यह बात आन दी

फ्लौर आफ दी हाउस और आउट साईड कह सकता हूं। एक बात और अपोजीशन ने कही कि बिजली तो पहले दे दी लेकिन बिजली बोर्ड ने उसकी जनरेशन की तरफ ध्यान नही दिया। यह बात भी सफेद झूठ है। जनता को आप बहुत देर तक नही बहका सकतें। कल भी मैने कहा था कि इनकी अलाएंस ऐसी जगह होती चली जा रही है जहां से आप हरियाणा के दुश्मन बनते जा रहे है आप हरियाणा .. . .।

चौधरी राम लाल वधवाः आन ए प्वांयट आफ आर्डर हरियाणा के दुश्मन एक मैम्बर को बताना, क्या यह ठीक हैं। यह एक्सपंज होना चाहिए।

चौधरी मेहर चन्दः मै किसी मैम्बर को नही बता रहा, मै हरियाणा के जनसंघ को बता रहा हूं हरियाणा का जनसंघ हरियाणा का दुश्मन है . .. . ।

श्री सभापतिः इसमे कोई बात नही है। एक्सपंज की कोई जरूरत नही है। आप बोलिए। बैठ क्यों गए?

चौधरी मेहर चन्दः चेयरमैन साहब, मै कह रहा था कि जनसंघ हरियाणा का दुश्मन है। मै यह बात दावे के साथ कहता हूं। If they want to sue me, They can sue me. (Noise) जब हरियाणा बना उस वक्त हरियाणा को भाखड़ा से हिस्सा आया, इन्द्रप्रस्थ से हिस्सा आया और दूसरी जगहों से मसलन जहां यह सीमेन्ट फैक्टरी है वहां से हिस्सा आया। यह सब 178 मैगावाट

बिजली की जनरेटिंग कैपेसिअी हरियाणा की थी जब हरियाणा बना था लेकिन आज हरियाणा की जनरेटिंग कैपेसिटी 225 मैगावाट हो गई है। क्या यह आसमान से आ गई? क्या यह बिजली बोर्ड ने पैदा नही की? लेकिन यह कहते है कि बिजली की जनरेशन की तरफ कोई ध्यान नही दयिा गया। चेयरमैन साहब, 225 मैगावाट तो अब है ओर इसके अलावा 1974–75 मे 95 मैगावाअ की और एडीशन हो जाएगी और यह लाजमी तौर पर होगी। यह कोई फिक्टीशियस फिगर्ज नही है। यह एडीशन लाजमी तौर पर हो रही है। इस तरह से 1974–75 मे यह 320 मैगावाट हो जाएगी। 1975–76 तक तो जम्प इतना है कि अगर मै इनको सुनाऊं , लेकिन बदकिस्मती यह है कि लोग एक साईउ पिक्चर पेंट करना चाहते हं। यह तस्वीर का एक पहलू देखते है, दूसरा पहलू तो यह देखते ही नही। चेयरमैन साहब, 1975–76 मे बिजली की प्रोडक्शन 629 मैगावाअ हो जाएगी। उाससे नैक्टस ईयर, मै अभी फाईव ईयर प्लान पर आ रहा हूं। मै सिर्फ 1977 तक की बात करता हूं क्योकि मै 1977 तक ही चुनकर आया हूं। चेयरमैन साहब, 1976–77 मे बिजली का प्रोडक्शन 799 मैगावाट हो जाएगा। इसके लिए मै बिजली बोर्ड को दाद देता हूं। बिजली बोर्ड जिन्दाबाद। यह कह देना कि बिजली बोर्ड ने कुछ काम नही किया, फैक्टस और फिगर्ज को टुइसट करने वाली बात है। मै हाउस का ज्यादा टाईम नही ने रहा हूं। मै फैक्टस एण्उ फिगर्ज के साथ बोल रहा हूं। (व्यवधान) चेयरमैन साहब, इनको क्या गिला है, आप इनको कहे कि जरा दिल को थाम कर सुने। इसके अलावा मै आगे

चलकर बिजली बोर्ड के कुद नुक्स भी आप के सामने रखूंगा, मै कोई वन साईड पिक्चर पेन्ट नही कर रहा हूं। पहले तो बिजली बोर्ड को मै एक दाद देता हूं और इसके साथ साथ वहां के सारे कर्मचारियों को भी दाद देता हूं और वह इस बात के लिए कि अगर हिन्दोस्तान मे कोई बिजली बोर्ड है तो वह एक हरियाणा का ही है जिस ने सब से पहले ट्रान्सफार्मर्ज बनाए और बहुत थोड़े से अर्से मे सारे हरियाणा को जगमबा दिया तो यह सारा क्रेडिट हरियाणा बिजली बोर्ड को व उनके सभी कर्मचारियों को ही जाता है। दाद देनी चाहिये इस हरियाणा के बिजली बोर्ड को कि इसने क्या–क्या नही किया। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस के अलावा मै एक और बात कहना चाहता हूं वह है कर्मचारियों की स्ट्राइक के बारे, उनके एजीटेशन के बारे में। मै यह मानता हूं कि एजीटेशन है, स्ट्राइक्स है लेकिन मुझे आप बताइये कि कौन सी जगहे ऐसी है, जहां पर ये एजीटेशन्ज व स्ट्राइक्स नही होती। एक अकेला बिजली बोर्ड को सिंगल आउट कर देना यह बात ठीक नही है। मै तो यहां तक कहने से भी नही हिचकिचाऊंगा कि यह जो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने स्ट्राईक मैमोरैन्डम दिया है यह भी शायद इन जनसंघी भाईयों की हिमायत से दिया गया हो।

चौधरी राम लाल वधवाः और आप शायद शाम को बिजली बोर्ड के चेयरमैन साहब, से चाय पीकर आये होगें। (हंसी)

चौधरी मेहर चन्दः डिप्टी स्पीकर साहब, मै तो चाय पी कर आया हूंगा या नही अगर इन के दल में कोई ख्वाहिश हो तो मै उनके पास से पूरी कचौरी भी खाने को तैयार हूं।(हंसी) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै कर्मचारियों की स्ट्राइक के बारे में बोल रहा था, इन्होने बीच में टोक दिया। बिजली बोर्ड ने हर मुमकिन कोशिश की है कि वह अपने कर्मचारियों को सेटिसफाई कर दे, मै इस बिजली बोर्ड का मैम्बर भी रहा हूं मूझे इसके इनटरनल मामलों का भी पता है कि उस वक्त भी यह सब कुछ किया और अब अगर बिजली बोर्ड वाले यह डिमांड करे कि उनका अगर एक आदमी भी बीमार हो या न हो, उनको तो हर महिनें 400 रूपये वहां से मिल जाने चाहिये, उनकी जेब मे आ जाने चाहिएं, तो ऐसी डिमांड तो उचित नही है। हां कर्मचारियों का रिइम्बर्समैंट की सहूलियते मिली हुई है, अगर वह एकचुअली बीमार होते है तो वे रि–इम्बर्समैंट करवा सकते है।

चौधरी पीर चन्दः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है मेरे दोस्त ने अभी जो रि–इम्बर्समैन्ट के बारे मे कहा कि यह चीज हम पर भी लागू होती हैं? जब हम बीमर होगे तो क्या हमे भी बीमारी के पैसे मिलेंगे?

चौधरी मेहर चन्दः मेरे ख्याल मे डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै इसका जवाब क्या दूं, इसका जवाब अगर और देता तो ठीक था। मेरे दोस्त को यह भी नही मालूम कि वह बोल क्या रहा हैं, जहां तक मैडीकल रि–इम्बर्समैन्ट का सवाल है तो वह पहले ही

हरेक एम.एल.ए. को यह सहूंलियते मिली हुई है। भई, बिजली बोर्ड वाले तो यह कहते है कि बगैर बीमार हुए, उनकी जेब मे महीनें पैसे पहुंच जाए, सो मेरे दोस्त, कुछ ध्यान से सुना तो करो, समझा तो करों, बताओ मै क्या करूं, अगर बाप ही मेरी बात को ध्यान से न सुना. . . . . .

एक आवाजः आप अपना हक निभाते जाओं।

चौधरी मेहर चन्दः भई, मेरा हक सुनना हो तो कभी पब्लिक के जलसों मे चलकर सुन लो।

एक आवाजः यह भी कर लेगें।

चौधरी मेहर चन्दः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै एक दो बाते कहकर वाइंड अप कर रहा हूं क्योकि मेरे बहुत से साथियों ने भी अभी बोलना है। कुछ ऐसी बाते है जिनके बारे में मै बिजली बोर्ड की तव्जजो दिलाना निहायत जरूरी समझता हूं। अरग वे गल्तियों को दूर नही करते तो मेरे ख्याल मे, फिर हम तो उनकी फेवर कर नही सकतें, कम से कम मै तो उनके हक मे नही बोलूंगा। जो अच्छे काम किए हों, उनके लिये हमे दाद जरूर देनी चाहिये लेकिन जो खामियां रह जाए तो उनको भी जरूय बताना चाहियें ताकि वह दूर हो सके। पहली बात तो यह है कि जो बिजली के बिल बनते है, वे बहुत हद तक ठीक नही बनते है, रिडिंग जो है, वह प्रोपर नही ली जाती। अफसर जो है, वे तो शायद एक दो मिनअ बात न सुने लेकिन मीटर रीडर्ज जो है वे

तो घण्टों बात ही नही करते और जब हम अफसरों से इस बात की शिकायत करते है तो वे कह देते है कि मीटर रीडर्ज ने यह लिखा है तो अफसरों को चाहियें कि कभी वहां जाकर स्पोअ पर इन बातों को वैरीफाई करे कि आया पब्लिक ठीक कहती है। क्या मीटर रीडर ही इतना बड़ा आदमी हो गया , जों कर दे वह ठीक है? इससे बहुत से किसान लोग बेचारे दुखी होते है, यूंही दफ्तर मे बैठे बैठे गलत बिल बना दिये जाते है और फिर किसी आदमी की सुनवाठ नही होती। तो बिजली बोर्ड के अफसरों को इस तरफ खास ध्यान देना चाहिये। दूसरी बात यह हैं, स्टेट मिनिस्टर साहब यहा पर बैठे है, मै उनकी तवज्जों इस तरफ दिलाना चाहता हूं क्योंकि मै तो उनको होलसोली इस डिपार्टमैंट का इन्चार्ज समझता हूं, उनकी मेहरबानी होगी अगर वह इस बिजली बोर्ड का सिकन्जा खींच कर रखें और इन्हे यह हिदायत करे कि जो टैस्ट रिपोर्ट होती है, उसकी एकनालिजमैंन्ट दे क्योकि इसके न देने से किसानों को परेशानी होती हैं। अगर बिजली बोर्ड के दफ्तर मे किसी डौमेस्टिक कनैक्शन के लिये ट्यूबवैल के कनैक्शन के लिये जाए तो वे कह देते है कि हमारे पास तो टैस्ट रिपोर्ट ही नही आई, अगर ये टैस्ट रिपोर्ट की एकनालिजमैंट देगे तो फिर यह इस बात से इन्कार नही कर सकेगे और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नही होगी। मुझे अच्छी तरह से याद है, मै दसपे साथ कह सकता हूं कि पिछले सैशन में, आप बेशक प्रोसीडिग्ज निकलवा कर देख लें, जब बिजली बोर्ड की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हुई थी तो उस वक्त यह फैसला किया गया था कि टैस्ट रिपोर्ट

एकनालिजमैंट दी जाएगी, फिर भी ऐसा नही हो रहा है। सरकार की तवज्जों इस तरफ होनी चाहिये और बिजली बोर्ड को इस बारे मे हिदायत देनी चाहियें कि टैस्ट रिपोर्ट लेते समय एकनालिजमैंट दें। तो इस तरह से जमींदारें को, किसानों को, दुकानदारों को जो बिजली का इस्तेमाल करते है उनको इस प्रकार की परेशानी नही होगी। इन शब्दो के साथ, मै आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी पीर चन्द (बरवाला एस.सी.): माननीय डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज हमारे सामने हरियाणा राज्या बिजली बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के ऊपर इस सदन के चर्चा चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने काफी से ज्यादा, बिलजी की तारे, गांव गांव मे फेला कर, हर जगह इस तरह रोशनी करने मे बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है और इससे दूसरे प्रदेशों मे हमारे हरियाणा का नाम भी हो गया है लेकिन जितनी जल्दबाजी मे यह सारा काम किया गया है, इससे बिजली बोर्ड वालों ने इस काम को बड़े गल्त ढंग से चलाया जिसका नतीजा यह हुआ कि थोड़े से अर्से मे काफी से ज्यादा पोल्ज वगैरह टेढे हो गये और कई जगहों पर तो गिर भी गये। ये लोग दावा करते है कि हमने गांव गांव मे बिजली पहुंचा दी है लेकिन आज कई गांवो की ऐसी स्थिती है कि जहासं पर बिजली का नामोनिशान भी नही है और कोई मीटर नही है और न ही वहां पर कोई बिजली घरर मे पहुंचती है। कई जगहे ऐसी है कि जहां पर लोगों

ने बिजली की वजह से ट्यूबवैल भी लगवाये है लेकिन वहा पार अभी तक लोगो को बिजली के कनैक्शन ही नही मिले है जिस से लोगो का नुक्सान हो रहा है। हमारी सरकार ने बिजली का इतना फेलाव तो जरूर यिका है लेकिन बिजली के न आने से बदइन्तजामी हुई पड़ी है। इस कारण से ट्यूबवैल क्या, इण्डस्ट्रीज क्या यहां तक कि हम अपने घरो के अन्दर भी बिजली न आने के कारण परेशान है। पिछले 6 महीनेां से पहले, गांव मे क्या और शहरों मे क्या सारी की सारी इंडस्ट्री बिजली की वजह से बन्द रही। बिजली 24 घंटे आने की बजाए सिर्फ 3 या 4 घंटे आती रही और वह तीन चार घंटे का भी पता नही किसा समय आए। कभी रात को आ जाती थी तो कभी दोपहर को यानी कोई निश्चित समय नही था। बिजली की वोलटेज कम ज्यादा होने की वजह से किसानों के मीटर खराब हो गए और बिजली कर्मचारियों ने उन खराब हुए मीटरों की कीमतें कंज्यूमर से वसूल की जबकि उनाक इसमे कोई कसूर नही था। इस वजह से जमींदारों को और इण्डस्ट्रीज वालों को बहुत भारी नुक्सान हुआ है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इतना भी नही पता कि पब्लिक के साि कैसे सलूक करना है। कोई भी पब्लिक का आदमी उनके पास जाता है तो उसको तसल्लीबख्स जवाब नही मिलता। आज जमींदारो के मीटर डायरैक्ट कनैक्ट कर दियै जाते है जिससे उनके मीटर बन्द हो जाते है और डायरैक्ट करने से उनके ऊपर इतना खर्चा पड़ता है कि एक साल के अन्दर सजा के तौर पर उनके ऊपर 5–6 हजार रूपये डाल दिये जाते है। जबकि आमतौर से एक ट्यूबवैल

के ऊपर 600 या 900 रूपया खर्चा आना चाहिये। दूसरी तरफ गांव मे या शहरों मे जो कनैक्शन लगे हुए है उनकी यह हालत है कि कभी तौ उनकी रीडिंग इस ढंग से होती है कि इसके अन्दर दो फेमिली रहती है इसलिए तुम्हारा खर्च दे गुण आएगा और जिसके अन्दर चार फेमिली रहती है उसका खर्च चार गुणा आएगा। इस बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को यह भी नही पता कि खर्चा यूनिटारें के हिसाब से लेना चाहिये या फेमिलिज के हिसाब से लेना चाहिये। कई मकानों मे चार या पांच कमरे होते है वहा भी यही कहा जाता हैं इसके अन्दर चार या पांच कमरे है इसलिए बिल ज्यादा आया हें ऐसे ऐसे कई मसले हैं। वैस बिजली तो जी सिर्फ तीन यूनिट और बिल आया 11 रूपये। समझ नही आती कि यह बिल किस ढंग से बनाते है। आज हर गरीब आदमी इससे दुखी है। बिजली के भरोसे पर आज हर आदमी ने अपने घर से लालटेन और दीया हटा दिया है लेकिन वह पहले से तंग रहता है क्योकि बिजली के आने कोई टाईम ही नही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपके द्वारा मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वे इन कमियों को दूर करने के लिए जरूर चर्चा करे और हरियाणा सरकार को कहें कि इस नुकसान से पब्लिक को बचाया जाए। आज यह घोटाला चल रहा है एक आदमी को तो एप्लीकेशन देने के बाद दो महीने मे बिजली मिल जाती है और दूसरे को साल साल भर तक नही मिलती। यह सारा इसलियें होता हैं कि यह बिजली वाले हल्के को देख कर मीटर देते है। इसके अलावा जो ट्यूबवैल को कनैक्शन दिये जाते है इसके बारे मे यह निति है कि

ट्रांसफार्मर से लेकर ट्यूबवैल तक जो लाईन खीची जाती है उस पर कोई खर्च नही होगा लेकिन यह होने के बावजूद भी जमींदारों से यह खर्चा वसूल किया जाता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब से निवदेन करूंगा कि वे इस तरफ खास करकें ध्यान दें। इस फसल के लिये अगर जमींदारों को बिजली न मिली तो हो सकता है कि पिछली दफा से भी इस फसल की ज्यादा बुरी हालत हो।। मै एक बार फिर आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वे जमींदारो को हो रही इस परेशानी को दूर करे ताकि लोगो को कुछ फायदा हो सके। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इनता ही कह कर मै आपका धन्यावाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

उपाध्यक्षः अब जैन साहब बोलेगे।

श्री ओम प्रकाश गर्गः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि आपने इनको जैन होने की वजह से पहले बोलने के लिये तो खड़ा नही किया? (हंसी)

12.00 बजें

श्री गुलाब सिंह जैन (हिसार): डिप्टी स्पीकर साहिबा, सदन के सामने बिजली बोर्ड की 1970–71, 1971–72 और 1972–73 के एस्टीमेटस की रिपोर्ट डिसक्स हो रही है। मेरे से पहले इस सदन के काफी दोस्त बोल चुके है। यह बात कि हरियाणा मे बिजली ने तरक्की की है इसके बारे मे मै कोई ज्यादा

नही कहूंगा क्योकि इसके बारे मे सभी भाईयों को अच्छी तरह से मालूम है और इस बारे मे पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है कि किस तरीके से ट्यूबवैल को कनैक्शन दिये हुए थे और 31 जुलाई, 1973 को वे 1 लाख 18 हजार हो गए। किस तरह से इलैक्ट्रिसिटी की कंजम्बपशन बढी़ और किस तरह से हमारा रैवेन्यू बढा़ इन बातों की तरफ मै सदन का ज्यादा समय नही लेना चाहता क्योकि ये बाते किसी से छिपी हुई नही है। आज बिजली जो है वह हमारी जिन्दगी का एक अहम रोल अदा कर रही है। चाहे एग्रीकल्चर को देख लें, इण्डस्ट्रीज को देख ले कामर्स को देख ले और चाहे हाउस होल्ड को देख ले इन सबमें बिजली का ही अहम रोल है। इसलिये आज जो हम डिस्कशन कर रहे है वह ऐसे विषय पर कर रहे है जो हमारी आल–राऊंड लाईफ पर इफैक्ट करता है। मै चाहूंगा कि सदन इस पर शान्ति के साथ गौर करे। हम देखना चाहते है कि अब तक की जो बिजली बोर्ड की परफोर्मेंस है वह संतोषजनक है या नही। कुछ भाईयों ने बिजली को हर गांव मे ले जाने पर ऐतराज किया और कुछ भाईयों ने कहा कि बिजली बोर्ड की तरफ भारी कर्जा हो गया है। लेकिन मै उनको यह बतलाला चाहता हूं कि अगर हम बिजली को बढाना चाहेगेग तो उस पर इनवैसमैंट भी करनी पड़ेगी। हम इसे कमर्शियल बेसिज पर तो चलाते नही है लेकिन कैपिटल की रिटर्न तो जरूरी होती है। आप हरियाणा 68 से 73 देखे इसमे रिटर्न के बारे मे कुछ आंकड़े दिये हुए है। आप अगर हमारे इस बिजली बोर्ड और दूसरे प्रदेशो के बिजली बोर्डो को देखे तो यह पाएगें

कि हरियाणा प्रदेश के बिजली बोर्ड की 1972–73 की रिटर्न 5.3 प्रतिशत है और उसके अगेस्ट कुछ स्टेटस ऐसी है जैससे आसाम 1 प्रतिशत बिहार 2 प्रतिशत, उड़ीसा 2.2 प्रतिशत, यू.पी. 4.5 प्रतिशत राजस्थान और आन्ध्र की रिटर्न ज्यादा है और पंजाब की 5.1 प्रतिशत हैं। इस बात के बावजूद कि हमारे हां ऐक्सपैन्शन बड़ी तेजी के साथ हो रही है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब ऐक्सपैन्शन हो रही हो तो कैपिटल इनवैस्टमैंट ज्यादा होती है और कैपिटल कौस्ट बढ़ जाती है क्योंकि उसक की रिटर्न आने मे कुछ टाईम लगता हैं। लेकिन मै आने बिजली बोर्ड को मुबारिकबाद देता हूं कि इतनी ऐक्सपैन्शन होने के बावजूद भी हमारी पर–कैपिटा रिटर्न 5.3 प्रतिशत है, अगर यह छः प्रतिशत हो तो हब उसको बहुत अच्छा मानते है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै हाउस का ज्यादा समय न लेता हुआ चन्द अहम बाते कहना चाहता हूं। मैने इन्कम और ऐक्सपैंडीचर की फिगर्ज निकाली है, यह बोर्ड को डिटेल्ज देनी चाहिए थी मगर उन्होनें नही दी। तो जो मैने वर्क आउट किया हैं उसकी परसैन्ट मै हाउस के सामने रखना चाहता हूं। बिजली की जनरेटिंग पर जो खर्च आता है वह 19 परसैंट है ऐसटैबलिशमैंट का खर्चा 28 परसैन्ट है, इन्ट्रैस्ट 28 परसैन्ट डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा 6 परसैन्ट और डेप्रीसिएशन 19 परसैन्ट होता है। इन फिगर्ज मे कुछ आधा परसैंट का फर्क हो सकता है वर्ना यह परसैंटैज ठीक हही हे। इसका मतलब यह है कि हमारी इन्कम तभी बढेगी जब हम बिजली और ज्यादा पैदा करेगे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुछ ऐक्सपैंडीचर ऐसे होते है जोकि

स्टेटिक होते है, वह बढते नही। अगर आज हम बिजली की पैदावार को ज्यादा बढा दें तो हमारे जो दूसरे इखराजात है, जैसे स्टाफ का खर्चा है वह उस परसैंटैज से नही बढेगा। इस लिए बिजली पैदा करने के सोर्सिज कौन से सस्ते और अच्छे हो सकतें है इस पर केवल प्रांत मे ही नही सैंटर मे भी विचार किया जाता है ओर इसके लिए आल इंडियां बेसिज पर एक पालिसी बनाई जाती है। शुरू मे हमने कोशिश की कि हम लोगो को बिजली सस्ती दे और सस्ती बिजली सिर्फ हाईडल सिस्टम से ही दी जा सकते है और आज तक हमारें मुल्क मे हाईडल सिस्टम पर ही डिपैंड किया था लेकिन पिछले साल जब ड्राउट आया तो हाईडल सिस्टम फेल हो गया और बिजली की बेहद शार्टेट हो गई जिसको कि पूरा करना संभव नही था। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैने वर्ल्ड लिट्रेचर आन इलैक्ट्रीसिटी पढी है यह जानने के किलए कि वहां पर बिजली के क्या सोर्सिज है। वहां पर thermal is the main generating source and the hydel is subsidiary source. इसलिए मै कहुंगा कि हाईडल पर न जोर दिया जाए, आप भी पहले थर्मल प्लांट लगाए और हाईउल को सबसिडीयरी सोर्स रखें, बल्किी डीजल से भी अगर हम बिजली पैदा करें तो जनरेटिंग पर खर्च आएगा उसकी प्रोपोर्शन से ऐस्टबलिशमैंट के खर्चे मे इजाफा नही होने वाला है। इसलिए हमे हर मुमकिन कोशिश करके बिजली की पैदावार बढानी चाहिए। इस वक्त जो हमारे तमाम सोर्सिज है उनसे 232 मैगावाट बिजली हम को मिल रही है। यह मै सरकारी आंकड़ों से बता रहा हूं। हमारी ऐक्सपैक्टिड

कन्जम्पशन 450 मैगावाट की है। हम जो नए सोर्सिज से बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहें है उस से हमे 275 मैगावाट बिजली और मिलगी। इसके अन्दर जो हमें ब्यास प्रोजैक्ट से बिजली मिलनी है वह इस मे शामिल नही है। मैने जो लिट्रेचर बिजली के बारे मे पढा है उसक के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि हम जो बिजली की मन्जम्पशन के ऐस्टीमेअस बनाते है, अगर आप समझते है कि उसमे 100 फीसदी इन्क्रीज होगी तो आप मान लीजिए कि वह 200 फीसदी इन्क्रीज होगी। उसका कारण यह है कि हमारे देश की डिवैल्पिंग इकानोमी है। जब डिवेल्पमैंट होती है तो बिजली की कन्जम्पशन भी बड़ी तेजी से बढती है। और इस हद तक बढती है जिसका अन्दाजा नही लगाया जा सकता। इसलिए अगर आपका 450 मैगावाट का ऐस्टीमैट है तो मेरी सजैशन है कि आप उसको कम से कम 600 मैगावाट कर दे ताकि आंयदा हमे यह न कहना पड़े कि हमे बिजली की शार्टेज है। आज क्या एग्रीकल्चर क्या इण्डस्ट्रीज औरप जिन्दगी की दूसरी जो एक्टिविटीज है। उन सबका निर्भर बिजली पर ही है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर स्ट्राईक की बात चली। मै जाति तौर पर स्ट्राईक के खिलाफ हूं और कम से कम भारतवर्ष मे जहां कि आज हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे है, ऐसी बाते नही होनी चाहिए। गरीबी कैसे हटेगी? गरीबी तब हटेगी जब प्रोडक्शन बढेगा, प्रोडक्शन कैसे बढेगा—प्रोडक्शन तब बढेगा अगर मजदूर काम करे और जो कैपिटल्सिट है वह ले—आफ या लौक

आऊट न करे। खैर मै ज्यादा इसके बारे मे न कहता हुआ केवल बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के बारे मे ही कहना चाहूंगा, मै उनको यह कहूंगा कि वे ऐजीटेशन के तरीके को न अपनाए। पिछले दिनों आप ने देखा होगा कि हरियाणा मे ट्रेडर्ज की कान्फ्रेंस हुई और उनकी बड़ी डिमाण्डज थी। उन्होने जाए इस के कि हरियाणा मे बंध करके सारा कारोबार बंद करते, डेमोक्रेटिक ढंग को अच्छा समझा और अपने रिप्रेजैन्टेटिवज के थरू अपने ग्रीवैंसिज को गवर्नमैंट रिड्रेस करवाया। आप यह जानते है कि पहले जिस वक्त हड़ताले होती थी वह इसलिए होती थी क्योंकि उस वक्त यह समझा जाता था कि the worker is weak as against the capitalist. इसलिए मजदूरों को मैनेजमैंट पर प्रैशर डालने के लिए हड़ताल करनी पड़ती थी। लेकिन आज डेमाक्रेसी का जमाना है, जनता के चुने हुए रिप्रिजैंटेटिव है। इसलिए मै चाहूंगा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो है वह अपने रिप्रिजैंटेटिव जो यूज करें जैसे कि ट्रैडर्ज अपने रिप्रिजैंटेटिव की मारफत अपने विचार सरकार के नोटिस मे लाए और जनंसघ वालों के पावं तले से जमीन निकल गई, हमारी सरकार ने उनकी जायज मांगो को नही माना जाएगा तो फिर बिजली बोर्ड के ऊपर हम बैठे है हम उनकी जायज मांगो का मनवा सकते है। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै यह बात दावे से कहमास हूं कि आज तक बोर्ड का कोई भी कर्मचारी हमें न मिला है और न ही उनहोने कोई हमें अपनी तकलीफ ही बताई है। दरअसल बात यह है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी गलत चक्कर मे फंसे हुए है। वे उन गलत पोलीटीशन्ज के हाथो मे खेल

रहे है जो मतलब के लिए उनको एक्सप्लायअ कर रहे है। मै चाहूंगा कि मेरी आवाज उन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के कानें तक जाए और ऐजीटेशन के रास्तों को छोड़ कर हमारे देश की बढती हुई इकानोमी मे कोआप्रेशन दे और रूकावट बनने की कोशिश न करे क्योकि उनका भला भी इसी बात मे है। अगर आज हमारी स्टेअ तरक्की करेगी तो उनको भी फायदा पहुंचेगा। आज हमारी स्टेट की डिवैल्पमैंट मे बिजली का एक बहुत अहम रोल है। इसलिए मै उनसे अपील करना चाहता हूं कि वे बजाए स्ट्राईक्स करने के हमें अपनी तकलीफे बताएं, मुझे अभी तक पता नही कि उनक के साटा क्या ज्यादती हो रही हैं, लेकिन अगर उनके साथ कोई ज्यादती पहो रही तो वह हमारे नोटिस मे लाए, हम उनके लिए गवर्नमैंट के साथ बातचीज करने के लिए तैयार है। पिछले दिनों राजस्थान और यू.पी. मे इंजीनियरों ने हड़ताल कर दी थी। तो यह तरीका मै समझता हूं बिल्कूल गजत है। मै अब ज्यादा टाईम नही लूंगा, एक बात कह कर खत्म करूंगा और वह यह कि थोड़ी सी बात अगर मै कड़वी कह दूं तो मै उम्मीद करता हूं कि मेरे जो बिजली बोर्ड के मेरहबान दोस्त बैठे हुए है। वह उसे बुरा महसूस नही करेंगे। मै फील्ड स्टाफ के बारे मे जानता हूं वहा पर इनऐफीशैंसी और कुरप्शन बहुत ज्यादा है। मै इसकी डिटेल मे नही जाता क्योकि पहले बहुत कुछ कहा गया हे। मै खुछ एस.ई. साहिब के पास गया और उन्होने एस.डी.ओ. को टेलिफोन किया, उस के बाद जब वह आदमी एस.डी.ओ. के पास गया तो उस को एस.डी.ओ. ने कहा कि तुम चले जाओ गुलाब

सिंह के पास, जब तक 700 रूपया नही दोग कनैक्शन नही मिलेगा। उस केस मे एफीडैविट भी दिया हुआ है। मुझे पता नही उसका क्या हुआ हैं। लेकिन इस तरह की दुखदायी बाते होती जरूर है और हो रही है। इसके लिये अगर मै यह कहुं कि सरकार जिम्मेदार है या चेयरमैन साहब, जिम्मेदार है तो यह ठीक नही होगा लेकिन इरअसल बात यह है कि ऐक्सपैंशन बहुत ज्यादा हुई है और फील्ड मे जो स्टाफ बैठा है वहां से गड़बड़ होती है। तो मै यह कहूंगा कि इस बात की तरफ से चेयरमैन साहब, ध्यान दे ताकि यह इनऐफीशैंसी दूर हो और लोगो की यह छोटी मोटी तकलीफे खत्म हो। बिलों के बारे मे भी आम तौर पर शिकायत मिलती है। इस बारे मे मै यह कहना चाहता हूं जिस तरह से पटवारी की हुई गिरदावरी अटैस्ट होती है इसी से इन बिलों की भी बाकायदा चैकिंग होनी चाहिए और मीटर रीडर्ज के ऊपर एक ऐसी एजैंसी हो जो इस बात को देखे और अगर बिलों मे गल्ती पाई जाए तो रीडर्ज के खिलाफ ऐक्शन होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मै अर्ज करता हूं कि जो बोर्ड की वर्किंग है, इन्वैस्टमैंट है, उसकी रिटर्न है ऐक्सपैंशन के काम है और बिजली पैदा करने की और स्कीमज है उनकी मै तारीफ करता हूं क्योकि ये बोर्ड के काम सराहनीय है ओर हम उन पर फख्र है। जब हम अपने बोर्ड के बाम को दूसरी स्टेट्स से कम्पेयर करते है तो हमारा सिर फख्र से ऊंचा होता है। इन शब्दों के साथ मै अपना स्थान लेता हूं।

श्री रामधारी गौड़ (गोहाना): डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी मेरे कई साथियों ने बड़े विस्तार रूप से बातया कि हरियाध्णा बिजली बोर्ड ने क्या क्या अच्छे काम कियो है लेकिन एक विरोधी दल के साथी ने कुछ ऐसी बाते कह दी और ऐसे आंकड़े पेश किये कि इतना कर्ज हो गया है औ यह हो गया है और वह हो गया है। मै अर्ज करता हूं कि इस देश मे यह पहला बोर्ड है जिस ने 1970 मे हरेक गांव मे बिजली पहुंचाई। आपको याद होगा कि ऊआकुपंड मे एक कान्फ्रेंस हुई थी और उस मे यह फैसला किया गया था कि सारे भारत मे 1980 तक पचास फीसदी गांव मे बिजली पहुंचाने का अनुरोध किया गया था लेकिन हरियाणा वह स्टेट है जिस ने दस साल पहले ही हरियाणा के सौ फीसदी गांव मे बिजली पहुचा दी है। फिर इस मे देखने वाली बात यह है कि किन हालात मे इनता बड़ा काम किया गया। मै कहना चाहता हूं कि जिस आदमी ने अधेरा नही दिखा उसे रोशनी का पता नीह लगता। इन लोगो ने तो नुक्ताचीनी ही करनी हैं क्योकि यह किसी अच्छी बात को देख नही सकते। मुझे याद है कि 1967 मे जब केबिनेट बनी और उसकी पहली मिंटिंग हुई तो उसमे यह बात सामने आई कि हरियाणा के पास पैसा कितना है कि जिससे मुलाजमों की तनखाहे दी जा सकती है। उस वक्त हमारी माली हालात ऐसे थे। जब यह मौजूदा सराकर पावर मे आई उस वक्त ऐसे हमारे हालात थे लेकिन इसने आते ही ऐसे काम कियो कि तीन साल के अन्दर सौ फिसदी गांवों मे बिजली दे दी और हरियाणा को खुशहाली के रास्ते पर तेजी से चला दिया। उस

वक्त यहां पर सिर्फ 19 हजार ट्यूबवैल होते थे लेकिन आज आप देखे हमारे प्रान्त मे एक लाख 18 हजार ट्यूबवैल है। आखिर यह खुशहाली किन की हुइ? यह खुशहाली जमींदारे और किसानों की हुई हरियाणा की जतना की हुई हैं। इस खुशहाली के लाने मे सब से बड़ा हाथ इस हमारे बिजली बोर्ड का है जिसने इतना शानदार काम किया हैं। अगर ट्यूबवैल को बिजली न दी जाती तो अनाज की पैदावार इतनी नही होनी थी लेकिन यह कहते है कि इतना कर्ज हो गया ओर इतना सूद पड़ गया मगर इनको इस बात की समझ नही आई कि अगर उस वक्त 1970 मे कर्ज लेकर बिजली फेलाने का काम न करते और आज हो रही है आज कर तेा दूगने पैसे खर्च आते और इतनी पैदावार भी न बढती जितनी आज हो रही है जिसकी वजह से आज हरियाणा का नाम सारे देश मे इज्जत के साथ लिया जाता है। हमने बिजली के काम को बढाया जिससे पैदावार बढी और पैसा भी कम खर्चा आया लेकिन इनको यह बाते नजर ही नही आती है क्योंकि यह तो कहते है कि हरियाणा मे इतनी खुशहाली क्यों हो गई और ये ऐजीटेशन होनी क्यो बंद हो गई और अब क्यों नही होती, कभी यह कर्मचारियों की बाते करते है। मै समझता हूं कि यह पहला बिजली बोर्ड है जिसने आज मकान बनाने के लिये अपने कर्मचारियों को कर्जे दिये हैं और वे खत्म नही होती लेकिन वे इन भाईयो के भड़काने मे नही आयेगें क्योकि वे जानते है कि बोर्ड ने उनको कितनी सहूलियतें दी हैं। तो मै बता रहा था कि हमने किन हालात मे यह काम किया है। मुझे याद है कि बोर्ड के कर्मचारियों ने उन

इलाकों मे बिजली पहुंचाई जहां पानी खड़ा था और आने जाने के साधन नही थे। वहा पर पानी मे खड़े होकर खम्बे गाड़े गय और जहां रास्ते इतने खराब थे कि जाना मुश्किल था और सामान जा नही सकता था वहा ऊंटो और छकड़ों की मद्द से खम्बे पहुंचाये गयें। उस वक्त पैसे की कमी थी, मुश्किल रास्ते थे और मुश्किल साधन थे लेकिन बावजूद इन कठिनाइयों के यह सारा काम रिकार्ड टाईम मे किया गया और हरियाणा का नाम तमाम दुनियां में ऊंचा हुआ। यह देख कर हमारा सिर फख्र से ऊंचा होता हैं कि हरियाण पहली स्टेट है जिसने सौ फिसदी गावों मे बिजली पहुचां दी है। लेकिन इन भाईयो को कुछ नजर नही आता है। यूरोप मे भी ऐसे गांव मिलेगें जहां बिजली नही पहुंची है। लेकिन यह फख्र हरियाणा को ही हासिल है कि हरेक गांव मिलेगे जहां बिजली चली गई है। आजादी से पहले जब हमारें प्रचारक देहात मे जाते थे ता वह गाते थे, ''बुढी बैठेगी, चरखा कातेगी और लट्टू जलेगें'' तो उस वक्त लोग कहते थे कि यह बहकाने की बाते है। ऐसी कभी नही हो सकेगा लेकिन हरियाणा की सरकार नहे वह काम कर दिखाया है। 1970 से पहले यह भाई जो नुक्ताचीनी करते हैं जब बैठकों मे बैठते थे तो वहां पर मिट्टी के तेल का दिया जलता था और आंखो मे धुआं और नाक मे बदबू आती थी लेकिन अब ये भाई बिजली के लट्टूओं के नीचे बैठकर बैठके करते है। देहात वालो ने कभी बिजली का पंखा नही देखा था लेकिन अब उनके घरों मे पखें चलते है, हीटर चलते है और फ्रिज लोगो ने ले लिये है। बोर्ड ने ऐसे काम करके देहात और शहर मे

जो फर्क हुआ करता था उसे खतम कर दिया है क्योकि जो सहूंलियते पहले शहरों मे ही मिलती थी और जिसका देहात वाले ख्वाब भी नही ले सकते थे आज देहात मे मिल रही हैं लेकिन इन भाईयों को यह सारी नजर नही आती है जो काम हुये है ओर जिनको सारी दूनियां जानती है उन कामों को इन्हे नजरअन्दाज नही करना और उनकी तारिफ करनी चाहिये। हां कहीं कमी रह गई है उसे सरकार के ध्याान मे लाना चाहियें लेकिन इस बे सिर पैर की नुक्ताचीनी नही करनी चाहियें। आप किसी भी प्रांत मे चले जाये हरियाणा का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है और वे लोग हरियाणा मे जो तरक्की के काम हुये है उनकी तारीफ करते है। अभी बताया गया हैं कि हमने केवल बिजली ही पहुंचाई नही बल्कि और बिजली पैदा करने और उसे पहुंचाने के साधन भी पैदा किये है ताकि इसकी कमी न आये। हमारे पास भाखडा़ की बिजली आती है जिससे अब कात नही चलता है। इसलिये पानीपत 110 मैगावाट के दो यूनिट्स लगा रहे है जो 1977 तक मुकम्मल हो जायेगे। अगले साल 60 मैगावाट का एक यूनिट फरीदाबाद मे मुकम्मल हो जायेगा और 1975 मे 60 मैगावाट का एक और यूनिट लग जायेगा। अंदाजा है कि 1977 तक तकरीबन 350 मैगावाट बिजली हरियाणा में पैदा होने लगा जायेगी। बिजली की जितनी मांग बढती जा रही हैं उतने ही साधन भी उसे पैदा करने के कियो जा रहे है ताकि लोगो की बढती हुई मांग को पूरा किया जाता रहे और इसकी कमी हरियाणा म न रहें।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हाईडल पावर को इस्तेमाल करने का जहां हमे मौका मिलेगा हम उसको इस्तेमाल किये बगैर नही रहेगे। वैस्टर्न जमुना कैनाल मे, ताजे वाला से दादूपुर तक 150–150 फुट के कई फाल आत है। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यह फैसला किया है कि इन फाल्ज का फायदा उठाया जाए और वहा पर 45 मैगावाट के जनरेटर लगायेगे ताकि थोड़ा पैसा लगाकर यहा से जो बिजली पैदा होती है। उसको भी न छोड़ा जाए। थर्मल प्लांट कि लिए डिजल जनरेटर सैटस लगाने की कोशिश की जार रही है। ताकि बिजली की कमी पड़े तो उसे इन से पूरा किया जाए। यह बात नही है कि बोर्ड ने बिजली का फेलाव ही किया है, साधन नही जुटाये है। हमारा ब्यास डेम बन रहा है यह मल्टीपरपज स्कीम है और यहां से बिजली मिलेगी, साउथ की स्अेटों से मिलेगी, राणा प्रताप सागर से मिलेगी। जहां सं भी हमे बिजली का एक भी युनिट मिलता दिखाई देता है हम उसको लेने की कोशिश करते है। जितनी हमारी बिजली की डिमांड बढ रही हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बात को क्रिटिसाईज करना कि बिजली पर खर्चा ज्यादा हुआ है इससे कोई बात नही बनती, मै समझता हूं इस पर ज्यादा खर्चा होना चाहिए क्योकि इससे हमारा हौंसला बढता है। रशिया मे जब सबसे पहली समजावादी हकूमत हुई थी, उन्होने एक ही प्लान रखा था कि देश मे बिजली का विस्तार किया जाए। इसके सिवाये और कोई प्लान नही रखी थी। उसकी पांच साला प्लान सिर्फ बिजली की तरक्की के लिए थी कि बिजली के काम मे इजाफा किया जाए। इसके मुकाबले मे हने

एक ही साल में, हर एक गांव मे बिजली पहुंचा दी है क्योंकि देश की खुशहाली बिजली पर मुनहस्सर है, इसके बिना कोई काम नही चल सकता चाहे इण्डस्ट्री है चाहे खेतीबाड़ी है और चाहे और दूसरे काम–धधें है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर साहब, मजदूरों के बारे मे ये कहते है कि मजदूरों को काम नही मिलता। जब तक बिजली नही पहुंची थी तब तक कैसे मजदूरों को काम मिलता? जिन गावों मे बिजली पहुंची है वहा छोटी छोटी दस्तकारी मिलेगी, छोटे छोअे और कई प्रकार के काम धंधे मिलेगे और काम धधें मिलने से हरियाणा खुशहाल होगा। स्पीकर साहब, मै समझता हूं कि ऐफिशिऐसी के हिसाब से डिवैल्पमैंट के कामों के हिसाब से देखा जाए तो बिजली बोर्ड ने सराहनीय तरक्की हैी है। हमारे यहां दूसरी स्अेटों मे होत है हरियाणा मे उनसे कम है। और रिटर्न ज्यादा है। जहां ऐफिशिएंसी हो लौसिज भी कम हो गए है। मैने ओर स्अेटों मे देखा है। जिनते लोसिज दूसरी स्टेटों मे होते है हरियाणा मे उनसे कम है। और रिटर्न ज्यादा है। जहां ऐफिशिऐसी हो, लौसिज कम हो और रिटर्न ज्यादा हों, हर एक गांव मे बिजली गई हों, इतने बड़े बड़े काम हुए हो वहां मै समझता हूं हरियाणा इलैक्ट्रिसीटी बोर्ड तमाम दुनियां मे बधाई का पात्र है। इसको तमाम दुनियां की सराहना हासिल है। प्रत्येक नागरिक सरहाता है। लेकिन हमारें भाई नट–नटी वाली बात करते है कि ''मै न मानू'' इन्होने सही बात को मानना नही है नुक्ताचीनी करके बड़ा तुफान मचाते है कि यह हो गया, वह हो गया। जो तुफान ये मचाते है। अब जतना

इसकी बात का सुनती ही नही और गवर्नमैंट द्वारा किया गये कामों का सरहाती हैं और कहती है कि कितना बड़ा काम कर के दिखा दिया। ये बाहर नही हाउस मे ही अपने दिल के गुबार निकालते है। जब जनता से बात करते है। तो वह कहती है कि हम मौज में हैं, आपको धोखा लगा होगा, जतना इस तरक्की का सराहती है। मै बिजली बोर्ड और हरियाणा सरकार को मुबारिकबाद देता हूं कि जितना काम हरियाणा मे हुआ है उस मे सब से अहम पार्ट हरियाणा बिजली बोर्ड ने अदा किया है।

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब जवाब देगें, उसके बाद एक रिपोर्ट और है जिस पर डिस्कशन होनी हैं

(इस समय कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मै बोलना चाहता हूं . . . .. . (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सब साहिबान से प्रार्थना है कि तशरीफ रखें। चट्ठा साहब बोलेगे। (व्यवधान)

सिचाई एंव बिजली राज्य मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा): स्पीकर साहब, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड . .. .

श्री जगजीत सिहं टिक्काः आन ए प्वांयट आफ आर्डर। जो मूवर है उनको बोलने का हक पहले होता है इसलियें हमारो बोलने का हक है। . . ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब खड़े हो गये है। इनके बोलने के बाद एक और रिपोर्ट डिस्कस होनी है। आप तशरीफ रखिए। (व्यवधान)

चौधरी चांद रामः आप मुझे इजाजत दे, आप नम्बर के हिसाब से बोलने दे. . . . .

श्री अध्यक्षः आप तशरीफ रखिए। चट्ठा साहब आप बोलिए।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड के एनुवल फाईनैशियल स्टेटमैंट और फोर्थ अनुवल स्टेटमैंट आफ अकाउंटस पर चर्चा चल रही है। कुछ विरोधी भाई इस पर बोले है और इस के साथ ही साथ कुंछ कांग्रेसी भाई भी इस पर बोले है। जिनकी तरफ से हैल्दी और ठीक क्रिटिसीजम भी हुआ है। जिसको मै तसलीम करूंगा। इसके साथ ही साथ कुछ भाईयों ने बहुत सी बाते ऐसी की जो बिल्कुल गलत है और गल्त बाते हाउस मे कहना कोई अच्छी बात नही हैं। श्री राम लाल जी ने कई बातें कही है। इन एक को ही लेकर मै डील करूंगा क्योंकि अपोजीशन की तरफ से मेन–स्पीकर यही रहे है। इन्होने यह बात कही कि एग्रीकल्चरिस्ट को और इण्डस्ट्रीयलिस्टस को पूरी पावर नही मिलती, पूरी बिजली नही मिलती, कनैक्शन ठीक ढंग से नही मिलते जिस की वजह से जमींदार और बिजनैसमैंन तंग है। बड़ी मुश्किल मे हैं। स्पीकर साहब, मै आपकी मारफत इन्हे

अर्ज कर दूं कि जब हरियाणा बना था तो उस वक्त कुछ देर इन की हकुमत आई थी। ''नो महीने से एक महीन कम'' का मतलब क्या होता है, मुझे तो इसका पता नही लेकिन कुछ देर इनकी हकूमत रही (हंसी)

चौधरी रामलाल वधवाः आप जवाब क्या देगें जब आपको इसका पता नही है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः जो आकंड़े मेरे पास है ये उस समय के हे जब इनकी हकूमत भी। उस वक्त 132 के.वी. की 205 किलोमीटर लम्बी लाईने थी और जिस दिन ये कुर्सी छोड़ कर गए उस दिन भी उतनी की उतनी ही थी, एक इंच भी इलैक्ट्रीसिटी की लाईन लम्बी नही की। इलैक्ट्रिसिंटी को स्प्रेड करने की कोशिश बिल्कुल नही की। मै पूछता हूं ये आठ महीने क्या करते रहे?. . .. .

श्री ओम प्रकाश गर्गः आन ए प्वांयट आफ आर्डर। जैसा कि मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि '' कुर्सी छोड़ कर गये थे'' असल मे कुर्सी छोड़ कर नही गये थे, कुर्सी छुडवाई गई थी। (हंसी)

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः आज ये लोग कहते है कि एग्रीकल्चरिस्ट्स को पूरी बिजली नही मिलती, इन्होने कभी खेती नही की है। मै इन्हे बताना चाहता हूं कि मै उन मै से हू जिन्होन अपने हाथ से हल चलाया है, खेती की है और इन से

कई गुणा खेती का तजुर्बा है। इनकी बसे उस रूट पर चलती थी जिस पर मेरा गांव है। ये को–आप्रेटिव यूनियन के सैक्रेटरी थें। जब मुलाजमों को नोकरी दिया करते थे तो पहली बात यह देखते थे कि किसी दूसरे का हक नही था और आज ये मजदूरों के हमदर्द बने बैठे है। ये उनसे कोरे कागज पर दस्तखत करवाते है। . .. .

चौधरी रामलाल वधवाः ये गल्त ब्यानी कर रहे है। इनकी वर्डिंग ऐक्सपंज होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप तशरीफ रखिए। (शोर)

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः इन्होने बिजली बोर्ड के ऐम्पलाईज की स्ट्राइक की बाबत आरगुमैंट दी है और ये मजदूरों के हमदर्द बनते फिरते है। (व्यवधान) जब ये यूनियन के सैक्रेटरी थे तो उनसे कोरे कागज पर दस्तखत करवाते थें।

चौधरी रामलाल वधवाः यह * * ** * * * * ** * * * * * * * *है

श्री जगजीत सिहं टिक्काः यह * * * * * * * ** * * * * * * * ** शब्द पार्लियामैंटरी है या अनपार्लियामैंटरी है। इस पर मै आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः यह अनपार्लियामैंटरी है।

चौधरी रामलाल वधवाः इन्होने कोरे कागज पर दस्तखत करने की बात कही है।(व्यवधान) इन्होने ऐसा क्यों कहा? ये बिल्कुल बेसलैस बात कर रहे है। इस बात का ये कोई प्रमाण पेश करें।(विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौधरी राम लाल जी, हम किस–किस का प्रणाम पेश करें। हम हर एक आदमी से तों प्रणाम नही मांग सकतें(व्यवधान)। मैने मिनिस्टर साहब से कहा है कि वे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड बोले . .. .

चौधरी रामलाल वधवाः ये बिजली बोर्ड पर नही बोल रहे है।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब, आज ये उन मजदूरों के हमदर्द बने फिरते जिन्हे अपने समय मे नौकरी से निकाला था । वे सुप्रीम कोर्ट तक धक्के खाते रहे लेकिन इन्होने नौकरी नही दी। (विघ्न)

स्पीकर साहब, पीछे जैसे हमारे जो स्ट्राईक हुई उसका भी इन्होने जिक्र किया। इसके बारे मे मै सदन को बताना चाहता हूं कि जितनी फेसिलिटीज हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपने ऐम्पलायज को दी है उतनी हिन्दूसतान के किसी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने नही दे रखी है। स्पीकर साहब, मै यह अर्ज करना चाहता हूं कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड मे जो मजदूर काम करते हुए मर जाता है उसको पांच हजार से लेकर दस हजार रूपए तक इमीजिएटली

दिए जाते है। उसकी फेमिली का फ्री मैडिकल एड दी जाती है। उसके बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री ऐजुकेशन दी जाती है। उसकी फेमली का गवर्नमैंट हाउस के बाहर महीने तक और उसके बाद भी रहने दिया जाता है और इन सब चीजों के अलावा उसके एक या एक से अधिक फेमिली मैम्बर्ज को नोकरी भी दी जाती हैं। तो स्पीकर साहब, इस तरह की फेसिलिटीज हिन्दुस्तान के किसी भी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के एम्पलाईज का नही मिली हुई है।

स्पीकर साहब, फिर इन्होने कहा कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऐम्पलाईज इसलिए हड़ताल करते है क्योंकि उनकी जायज मांगो को बिजली बोर्ड नही मानता है। स्पीकर साहब, यह हड़ताल 35 दिन तक रही। हड़ताल कराने वाले, स्पीकर साहब, कौन है यह मै कहना नही चाहता क्योकि इसका इनका पता ही है। स्पीकर साहब, सात मई को हड़ताल खुली यूनियन के मैम्बर्ज ने तसलीम किया कि जो हक हम आपसे मांगते थे वे आप पहले ही दे चुके हे। आज ये बात करते है कि उन्होने पैम्फलेअ निकाला है और इश्तिहार मे जो बाते है वे सही नही है। क्योंकि जैसा मैने कहा आठ तारीख की मीटिंग मे यूनियन के मैम्बर्ज ने खुद माना है कि जो वे मांगते थे वह बोर्ड पहले दे चुका है।

एक बात,स्पीकर साहब, चौधरी मेहरचन्द जी ने कही। उसका जहां तक ताल्लूक है उसके बारे मेरी अर्ज है कि मैडिकल अलाउन्स उसको कैसे दे जो बिल्कूल ठीक ठाक हैं। मैडीकल एड उसको मिलेगी जो बीमार होगा। यह तो नही हो सकता कि ठीक

को भी उतने ही पैसे मिले जितने बीमार को मिले। यह कहां का इन्साफ है? इनकी ऐसी नाजायज मागें हम बिल्कूल मानने के लिए तैयार नही है। पोलिटिकल पार्टीज की इमदाद से की गई मांगे न कोई गवर्नमैंट मानेगी और न बोर्ड उन बातो से सहमत होगा।

स्पीकर साहब, बोर्ड के ऐम्पलाईज की एक मांग है कि सीनियर टेक्निकल ओफिसर्ज के बराबर उनको प्रोमोशन दी जाए। भला यह कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति जो एक लाईनमैन के ऊपर उठ, क्वालिफिकेशन उसकी उतनी न हो, उसको चीफ इंजीनियर तक की प्रमोशन कैसे दी जाए? यह डिमाण्ड कौन सा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड मान लेगा? कौन सी सरकार मांग को ठीक समझेगी? हम ऐसी मांग मानने वाले नही है। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऐम्पलाईज हमारे भाई हैं। उनकी जायज मांगो से हमारी हमदर्दी है लेकिन उनकी गलत मांगे मानने के लिए हम बिल्कूल तैयार नही है।

स्पीकर साहब, चौधरी राम लाल जी ने एग्रीकल्चरिस्टस की बात भी की। पिछली दफा बिजली का संकट था। बिजली कम थी क्योंकि भाखड़ा मे पानी कम था और उसकी वजह से बिजली की जैनरेशन कम हुई। उस वक्त भी दिल्ली पूरी थी, एक ट्यूबवैल रोज 6 घंटे की ऐवरेज से ज्यादा नही चला। पिछलें साल भी हमारी ऐवरोज इससे कम नही हुई। पिछले साल हमने जमींदारो का ऐवरेज पानी 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक दिया। फिर से बात करते है कि हमने जमींदारो का पूरा आराम नही दिया।

स्पीकर साहब, 1947 मे हमारे पास 2,190 ट्यूबवैल थे जबकि अब 31 अक्तुबर, 1973 को 1,21,524 टयूबवैल है। अब भी जैसे मुख्य मंत्री जी, ने परसों बताया, जमींदारो के टयूबवैल को हम ज्यादा से ज्यादा बिजली देने की कोशिश करेगें और देते रहेगें।

इसके साथ ही स्पीकर साहब, एक बात और है। हमारे बिजली बोर्ड ने जहां सारे हरियाणा मे बिजली देकर, सारे गांव मे बिजली देकर हिन्दस्तान मे फर्स्ट स्टैंड किया है। वहां दूसरी तरफ ऐमरजैंसी एग्रीकल्चर प्रोग्राम के अन्दर भी हमारा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हिन्दूस्तान मे फर्स्ट रहा है। इस प्रोग्राम के तहत सारे सूबो को पैसा मिला था कि आपने इतने टयूबवैलज फलां डेट तक लगाने हैं। इसने चार करोड़ रूपया मिथी (फिक्सड) समय के अन्दर अन्दर ट्यूबवैल बनाकर खत्म किया और उनको कुनक्शंज भी दिए। यह भी इसने एक पहल की है।

इसके अतिरिक्त, स्पीकर साहब, हमारा बिजली बोर्ड हिन्दूस्तान मे पहला बिजली बोर्ड है जिसने 45 परसैन्ट लोड एग्रीकल्चरिस्टस को दिया है। कही भी एग्रीकल्चरिटस को इतना लोड नही दिया गया है, इतनी बिजली नही दी गई जितनी हमारे हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने दी है।

चौधरी राम लाल जी ने स्पीकर साहब, इण्डस्ट्रीज की बात भी की थी। जहां तक इण्डस्ट्रीज को बिजली देने का सम्बन्ध है उसकी पोजीशन स्पीकर साहब, यह है कि 1970–71 मे

स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज 15,329 थी जबकि 1972–73 मे 1,904 हो गई है। लार्ज इण्डस्ट्रीज 1970–71 मे 317 थी मगर अब 444 हो गई है। इसके बावजूद भी ये कहते है कि इण्डस्ट्रीज की इलैक्ट्रिसिटी या गवर्नमैंट परवाह नही करती।

स्पीकर साहब, एक दो बाते इन्होने और कही। एक तो यह कहा कि इलैक्ट्रिसिटी की जैनरेशन नही की। यह बात ठीक है। फिर इन्होने कहा कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बहुत सारा कर्जा ले लिया। स्पीकर साहब, हमारा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड एक गांव को बिजली देने के लिए तकरीबन 25,000 से लेकर 30,000 रूपए तक लगाता है। हमने कितने हजार गाव मे बिजली दी है। इसका हर आनरेबल मैम्बर काक पता है। हरा आदमी का पता है क्योंकि हर अखबार मे यह बात आई है। इसी तरह से स्पीकर साहब, एक ट्यूबवैल को बिजली देने मे तीन हजार से लेकर पांच हजार रूपये तक खर्चा आता है। अब ये अन्दाजा लगाए कि कितने करोड़ रूपए बनता है। बिजली बोर्ड के पास मोहरे तो नही है कि वे नोटों पर लगा करके रूपया निकाल लेगें। रूपया तो इसको चाहिए ही। फिर भी, हिन्दूस्तान मे यह पहला बिजली बोर्ड है जिसने जैनरेशन पर खुद खर्च किया है। जितनी जनरेशन हो रही है उस पर इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड खुद अपना पैसा खर्च कर रहा है। स्पीकर साहब, इनके लिए क्रिटिसिज्म मे भी कोई वजन नही था। क्योकि रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए ट्यूबवैल को बिजली देने के लिए इण्डस्ट्रीज को बिजली देने के लिए कई करोड़ रूपया लगेगा ही।

इसमे कोई ऐसी बात नही है। मै तो यहां तक कहता हूं कि बिजली बोर्ड ने जितना कर्जा लिया है हम उसको रि–पे की गारंटी देने के लिए तैयार है। इन्होने स्टेट मे इतनी डिवैल्पमैंट कर दी है जिसका कोई हिसाब नही है। हम तो सूबे मे डिवैल्पमैंट चाहते है पैसा भले ही कितना खर्च हों। फिर इस पैसे को स्पीकर साहब, बैक्स से लेते है और उनके हिसाब किताब के मुताबिक ही देते हैं। जिनता पैसा लिया है वह हम दे रहे है।

स्पीकर साहब, रौंग बिलिंग की भी यहा बात आई। यह बात दूरूस्त है कि कही कही रौंग बिलिंग हो जाती है लेकिन हमारे अफसर उसको ठीक भी करते है। जहां तक मीटर्ज की बात है, उनको टैस्ट करने के लिए लेबोरेटरी का प्रबन्ध किया गया है। अगर जमींदारों से कही ज्यादा पैसे लिए जाए तो उनको वापिस किए जाते है।

एक बात, स्पीकर साहब, बाबू गुलाब सिंह जैन जी ने एक एस.डी.ओ. की बाबत कहा। वह बहुत बुरी बात है। उसकी इंक्वायरी कल ही इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बिजिलैंस विंग को मार्क हो गई है। उसके ऊपर जल्दी से जल्दी ठीक ढंग से ऐक्शन लिया जाएगा। ऐसी बात नही होगी कि गलत बात यदि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के नोटिस मे आ जाए तो वह उस पर कोई ऐक्शन न ले। उस पर एक्शन लेकर के उसे सही किया जाएगा।

स्पीकर साहब, अंत मे मै इलैक्ट्रिसिटी जैरनेशन के बारे मे अर्ज करूंगा। इसके बारे मे कई दफा यहां सवाल आ चुके है ओर उनका जवाब भी दिया गया है। हरियाणा मे बिजली जनरेशन के बारे मे थर्मल प्लांट फरीदाबाद बौर थर्मल प्लांट पानीपत के मुताल्लिक जिक्र आ चुका है। हम वैस्ट्रन हाईड्रो प्रोजैक्ट, ब्यास प्रोजैक्ट, बदरपुर प्रोजैक्ट और राणा प्रताप प्रेाजैक्ट ये और दूसरी जगहो से भी बिजली प्राप्त करेगे। हम ज्यादा से ज्यादा बिजली जरनेट करने की कोशिश कर रहे है लेकिन हमारे पास कोई ऐसा पहाड़ हरियाणा मे नही है जहां पर फाल हो और इनडिपेन्डन्टली बिजली बन सके। इन शब्दों के साथ मै बिजली बन सके। इन शब्दों के साथ मे गुजारिश करूंगा कि हमने जो थर्मल प्लांट फरीदाबाद मे लगाया है। उसके लिए 800 टन कोयला और पानीपत के लिए 1500 टन कोयले को पहले ही प्रबन्ध कर लिया हैं इस चीज का क्रेडिट हमारें बिजली बोर्ड को जाता है।हमारे बिजली बोर्ड की है। इन शब्दो से साथ मै गुजारिश करूंगा कि जो गलत क्रिटिसिजम है वह गलत ही है। हमारे बिजली बोर्ड के बराबर हिन्दूस्तान को किसी बिजली बोर्ड के काम नही किया है।

श्री अध्यक्षः इससे पहले कि मै चौधरी राम लाल जी को कहूं कि वे हरियाणा फाईनैन्शियल कार्पोरेशन की रिपोर्ट के बारे मे अपनी मोशन प्रस्तुत करे मै आदेश देता हूं कि चौधरी राम लाल जी ने हमारे विधान सभा के * * * * * * * * ** * * * * के बारे

मे जो एसपर्शन किया था वे शब्द सदन की कार्यवाही से एक्सपंज कर दिये जाए।

हरियाणा वित–निगम के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखो पर चर्चा

Chaudhri Ram Lal Wadhwa (Karnal): Sir I beg to move—

That the Annual Report and account of the Haryana Financial Corporation for the year 1972-73 be discussed.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा वित निगम के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखों पर चर्चा की जाए।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मैने सारी रिपोर्ट का पढ़ा है। कोई विशेंष बात इसमे नही है। जिस पर खास तौर से जिक्र करने की आवश्यकता हों। पिछली रिपोर्ट भी हरियाणा फाईनैन्शियल कार्पोरेशन की पेश हुई थी। मैने उस रिपोर्ट पर भी बोलते हुए कहा था कि हरियाणा फाईनैन्शियल कार्पोरेशन का काम अप–टू–मार्क तो नही लेकिन उत्साहजनक जरूर है।(विघ्न)

स्पीकर साहब, इस रिपोर्ट पर लम्बी चोड़ी बहस की आवश्यकता नही है लेकिन इसमे कुछ प्वांयट है जिनको मै आपके द्वारा सरकार के नोटिस मे लाना चाहता हूं और कार्पोरेशन भी इस

ओर ध्यान देगी। एक तो यह है कि जो लोन्ज सैक्शनड हुए थें उनकी फिगर्ज इस रिपोर्ट के पेज नम्बर नौ पर हायी लाईट्स आफ आपरेशन के अन्दर दिये गये है। इसमे सन् 1971–72 तथा 1972–73 की फिगर्ज का आपस मे मिलान किया गया है। उसके अनुसार जो लोन सैक्शन्ड हुआ है वह सन् 1971–72 मे 384 यूनिटस का 4,37,49,600 रूपये हुआ है। इसके अगेन्सट सन् 1972–73 मे 303 यूनिटस को सैक्शन्ड हुआ हें इन यूनिटस की तादाद कम हो गयीहै। 303 यूनिटस को कुल अमाउन्ट 4,56,12,200 रूपया सैकशन्ड हुआ है मगर जो नैट अमाउन्ट सन् 1972–73 मे सैक्शन हुआ है वह कम है। मुझे यह समझ नही आता कि यह फिगर्ज का टकराव कैसे हुआ हैं। इसमें जो ग्रौस अमाउन्ट सन् 1972–73 मे 4,56,12,200 रूपये दिया और नैट 3,69,58,300 दिया हुआ है। इसमे डिफ्रैन्स क्यों है? ग्रौस और नैट से क्या मुराद है? इनकी व्याख्या इसमे नही दी गयी हैं लेकिन बात यह है कि इस रिपोर्ट मे जहां सैक्शनड ग्रौस और नैट दिया है। वहा डिस्टर्स्ड भी दिया हुआ है। इस सैक्शन्ड को देने का इस रिपोर्ट मे क्या फायदा है जब पूरी तरह से लोन नही दिया गया तो यहां पर केवल डिस्टर्स्ड ही देना चाहिए था। खाली करकरदगी बढाने का क्या फायदा है? जितना लोन दिया है वही लिखना तो ठीक था।

सन् 1971–72 मे 384 यूनिटस को लौन सैक्शन हुआ लेकिन 124 यूनिटस को कर्जा दिया गया। इसी प्रकार सन्

1972–73 मे 303 यूनिटस को कर्जा सेक्शन्ड हुआ और 185 यूनिटस को दिया गया हे। इससे प्रतीत होता है कि प्रगति की रफ्तार तेज नही है बल्कि कम है। इसी प्रकार से हमारी स्टेट बड़ी है जो दो ही बातो पर निर्भर करती हैं एक खेती पर और दूसरे इण्डस्ट्रीज पर। इण्डस्ट्रीज मे ज्यादा डिवैल्पमैंट करने के लिए फाईनैन्शियल कार्पोरेशन को और ज्यादा तेजी से काम करना चाहिए।

स्पीकर साहब, इसी पेज की जो आईटम नम्बर 6 है उसके अन्दर दिया है–

"Loans dibursed by the erstwhile Punjab Finacial Corporation since its inception upto 31st March, 1967, in the areas now comprising Haryana." इसके आगे दिया गया है सन् 1971–72 मे 190 यूनिटस को 5 करोड़ 33 लाख 13 हजार 150 रूपया सैक्शन्ड हुआ और सन् 1972–73 में 190 यूनिटस को 5 करोड़ 33 लाख 13 हजार 150 रूपया सैक्शन्ड हुआ। Loans Disburesed since inception of Haryana finacial Corporation i.e. 1967-68 to the end of the year. और इसमे आगे दिया गया है सन् 1972–73 मे 416 यूनिटस को 9,26,64,983 रूपया दिया गया। यह ठीक है कि वह पंजाब के वक्त दिया गा होगा लेकिन आज का मुकाबला करने को कोई कारण नही बनता। आज हरियाणा मे जो लोन दिया जाता है वह हरियाणा के एरिया के लिए दिया जाता है उसक वक्त हरियाणा पंजाब का हिस्सा थां। हमारे साथ स्टैप मदरली यानी सौतेली मां जैसा व्यवहार रहा था। इसी लिए

हरियाणा के लोगो ने हरियाणा बनाने की मांग की थी। इसी कारण से हरियाणा बना। इसलिए यहा पर उन फिगर्ज को कोट करने का कोई ताल्लूक नही बनता। लेकिन जहां तक हरियाणा के 6–7 साल का ताल्लूक है। उसके अन्दर जितनी यूनिटस को कज्र दिया गया है उसकी अपेक्षा प्रगति की रफ्तार कम ही लगती है। फाईनन्शियल कार्पोरेशन भी इस ओर ध्यान देगी। इसके साथ ही पेज 11 पर दिया गया है–

"Review of Operations during the year; position of applications" इसके आगे लिखा है–

"During the year under review, the Corporation received 393 applications for grant of loans totaling Rs. 7,22,96,180 as against 515 applications totaling Rs.7,30,30,640 received during the previous year. The applications received covered a variety of industries such as . .. .

पेज 13 पर लिखा है–

"The above mentioned statement reveals that during the year under review there was a slight decrease in the number of application, although the amount of loan applied for was almost the same as during previous". . . . .

इन्होने यह माना है कि लोन लेने के लिये एप्लाकेशन्ज की रफ्तार कम रही है लेकिन इसका कारण नही बताया कि रफ्तार क्यों कम रही जब कि पिछले साल मे एप्लीकेशन्ज ज्यादा आयी

है। जब इण्डस्ट्रीज आगे डिवैल्प कर रही है तब इस फील्ड के अन्दर ऐप्लीकेशन्ज कम क्येा आती है आखिर इसका कोई तो कारण होगा?

श्री हरि सिंहः प्वांयट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, इस रिपोर्ट मे लिखा हुआ है। कि ऐप्लीकेशनज कम क्येां आयी–

"The decline in the inflow of applications was mainly in respect of transport loans and this was owing to the scarce availability of chassis."

The reason has been given here.

श्री अध्यक्षः इसका तो मिनिस्टर साहब जवाब दे देगें।

चौधरी राम दास वधवाः जहां तक इण्डस्ट्री लगाने के बारे मे ऐप्लीकेशन का ताल्लूक है, फाईनैशियल कार्पोरेशन को इसके कारणों की खोज करनी चाहिए कि कमी क्यों हुई है ताकि ज्यादा से ज्यादास फाईनैंशियल कार्पोरेशन से लोन लेकर फायदा उठा सके। इस रिपोर्ट के उसी पेज पर अगले पैरे मे यह लिखा है–

"During the year under review, the response from the small scale units was very encouraging. The Corporation received 217 loans application for Rs. 4,30,51,700 form the small scale units as against 153 for Rs. 6,67,93,790 received during the previous year. There was also an increase in the number of loan applications received form the units other than small scale... ....."

अदरदैन स्माल स्केल के लिये रफ्त ार भले ही बढी हो लेकिन स्माल स्केल यूनिटस के लिए घटी है जोकि इण्डस्ट्रीज का एक आधार है। लार्ज स्केल यूनिटस तो बहुत कम लगते है क्योकि इनके ऊपर लगाने वाले को अपने तरफ से भी बहुत सा रूपया लगाने की जरूरत होती हैं इसलिये मेरी गुजारिश यह है कि स्माल स्केल यूनिटस जो है, वह ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिये और उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये। इसके लिये फाईनैशियल कार्पोरेशन का उन कारणो की खोज करनी चाहिये जिनकी वजह से ऐप्लीकेशन कम आयी है ताकि स्माल स्केल के जो यूनिटस है, उनका ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उटा सके।

श्री अध्यक्षः चौधरी राम लाल जी, समय का ध्यान रखें। कई दूसरे सदस्य भी बोलना चाहेगे।

चौधरी राम लाल वधवाः मै समाप्त ही कर रहा हूं। स्माल स्केल यूनिटस के लिए कर्जा लेने के बारे मे जो एक कारण या एक बात हो सकती है जिससे कि लोगो को प्रोत्साहन नही मिलता हो वह शायद यह हो सकती है कि फाईनैंशियल कार्पोरेशन का जो प्रोसीजर लोन लेने के लियसे बना हो वह इतना सख्त हो कि स्माल स्केल यूनिटस के लिये जो लोग आना चाहते हों, वह पूरा नह कर सकते हों। मै आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि फाईनैंशिचल कार्पोरेशन के रूल्ज बगैरा को देखकर यह पड़ताल करे कि कही यही कारण तो नही है ताकि अगर उनके अन्दर किसी प्रकार की मुश्किल पेश आती हो

तो उस के अन्दर आसानी पैदा की जा सके जिससे कि स्माल स्केल यूनिटस लगाने वाले ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके।

श्री अध्यक्षः चौधरी राम लाल जी, समय का ध्यान रखें। कई दूसरे सदस्य भी बोलना चाहेंगे।

चौधरी राम लाल वधवाः मैं समाप्त ही कर रहा हूं। स्माल स्केल यूनिट्स के लिए कर्जा लेने के बारे में जो एक कारण या एक बात हो सकती है जिससे कि लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता हो वह शायद यह हो सकती है कि फाईनैंशियल कार्पोरेशन का जो प्रोसीजर लोन लेने के लिए बना हो वह इतना सख्त हो कि स्माल स्केल यूनिट्स के लिए जो लोग आना चाहते हों, वह पूरा न कर सकते हो। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि फाइनैंशियल कार्पोरेशन के रूल्ज बगैरा को देखकर यह पड़ताल करें कि कहीं यही कारण तो नहीं है ताकि अगर उनके अन्दर किसी प्रकार की मुश्किल पेश आती हो तो उसके अन्दर आसानी पैदा की जा सके जिससे कि स्माल स्केल यूनिट्स लगाने वाले ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि लोग लोन तो उसी हालत में लेने आयेंगे जबकि किसी इन्डस्ट्री को लगाने के बाद, वह उस इंडस्ट्री में सफल हो सकें। किसी इंडस्ट्री में सफल होने के लिए उसको रा–मैटीरियल की जरूरत होती है। फाइनैंशियल कार्पोरेशन, यह ठीक है कि लोन देती है लेकिन मैं फाइनैंशियल कार्पोरेशन का जो बोर्ड है उससे कहूंगा कि वह एक सैल कायम करें ताकि जो

लार्ज स्केल या स्माल स्केल यूनिट्स के लिए लोन लेने के लिए आते हैं, जिनकी ऐप्लीकेशन्ज आती हैं या जिनका लोन सैंक्शन हो जाता है, अगर उनको किसी चीज की आवश्यकता हो तो वह आवश्यकता पूरी हो सके। इंडस्ट्री जो लगायी जा रही है, उसकी डिटेल में जा करके, डायरैक्टर आफ इंडस्ट्रीज वगैरा, और दूसरी जो उसके साथ लगती हुई संस्थायें हैं, इंस्टीच्यूशन्ज हैं, उनके साथ तालमेल रख करके, उस इंडस्ट्री को कामयाब करा सकें। इस रिपोर्ट के अन्दर पेज 24 पर इर–रैगुलर ऐकाउन्टस के हैडिंग के नीचे जो लिखा हुआ है, उसको इन डिटेल में पढ़ना नहीं चाहता। उसके अन्दर एक बात तो यह है कि 14 केसिज जो 67.81 लाख रूपये के हैं, उनको कोर्ट के अन्दर डिस्पयूट पैंडिग है, चल रहा है। कईयों की डिग्री हुई पड़ी हैं, वसूली नहीं हुई। स्पीकर साहब, इस चीज का कारण यही हो सकता है कि फाईनैंशियल कार्पोरेशन से जिन लोगों ने कर्जा लेकर काम किया है, उन लोगों को कर्जा लेने के बाद प्रैक्टिकल डिफि्कल्टीज आयी है। मैंने डिटेल के साथ इस बारे में ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुए जिकर किया था। मैं उसको अब दोहराना नहीं चाहता। मैं यही चाहता हूं कि फाईनैंशियल कार्पोरेशन लोन देते वक्त इस बात की तसल्ली कर ले कि जो इंडस्ट्री लगनी है, वह पनपेगी और उसका रूपया सेफ है। यह ठीक तरह से वापस आना चाहिए। उन्हें ठीक समय पर रा–मैटीरियल मिलना चाहिए। इतनी ही बात मैं बोर्ड से कहना चाहता था। बाकी मैं फाईनैंशियल कार्पोरेशन ने जो काम किया है, उसकी एक बार फिर प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद।

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, हरियाणा फाईनैशियंल कार्पोरेशन की रिपोर्ट जोकि 1972–73 से सम्बन्धित है, के बारे में मै केवल दो–तीन बाते ही अर्ज करना चाहता हूं। एक तो यह कि फाईनैशियंल कार्पोरेशन की रिपोर्ट के पेज 15 पर लिखाा हैः डिस्ट्रिक्वाईज, क्लासिफिकेशन आफ लोन्ज। इसमे अम्बाला से 17, भिवानी से 9, गुड़गावों से 42, हिसार से 29, जीन्द से 4, करनाल से 14, कुरूक्षेत्र से 17, महेन्द्रगढ़ से 3, रोहतक से 10 और सोनीपत से 6 एप्लीकेशन को लोन सैक्शन किये गये है। 31 मार्च, 1973 तक इनको लोन दिये गये हे। मेरा कहने का तात्पर्य यह ळै कि फाईनैंशियल कार्पोरेशन के पास जो लोगों को लोन देने के लिए पैसा है और जो ऐप्लीकेशन कम आती है, इसका साफ मतलब यह है कि हमारा जो फील्ड स्टाफ है वह इन्सैंटिव नही देता जिसकी बिना पर लोग इण्डस्ट्रीयलाईजेशन की ओर बढ़े इसलिए उनके दिमाग के इण्डस्ट्रीयलाईजेशन की बात नही आती। जब तक हमारे पास जमीन के अलावा रूरल एरियाज मे रोजगार के दूसरे साधन नही होगे तब तक देश से बेराजगारी भी दूर नही होगी और लोगो की शक्ति भी नही बढेगी, जो पैदावार करने की है और उन्हें फिर साधन भी नही मिलेगे। इसलिये मेरी गुजारिश, मिनिस्टर साहब से यह है कि हरियाणा फाईनैंशियल कार्पोरेशन जहां लोन देती हे, उसकी डिस्बर्समैंट भी ठीक हो, स्माल स्केल यूनिटस के लिये ऐप्लीकेशन मे कमी के कारण क्या है, इस के लिये एक स्टडी सरकल या स्टडी ग्रुप बनाया जायें ताकि वे अफसर जो डिस्ट्रिक्ट

हैडक्वाटर्ज पर बैठे हुए हे। वे कम से कम देहातों मे जाकर यह बताये कि यह स्माल स्केल यूनिट लगाकर देखो, इसमे बहुत फायदार हो सकता है। इससे बहुत जल्दी पैसा मिलेगा। जब ऐसा करने से पैदावार बढेगी तो उसके साथ ही लोगो को ऐम्पलायमैंट भी मिलेगी। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर का प्रबन्ध हो और जो फाईनैंशियल कार्पोरेशन के डायरैक्टर साहब यहां बैठे है, वे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से एक क्वार्टरली या मन्थली रिपोर्ट मांग लें। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर जो लोग बैठे हुए है, जो लेाग रूरल एरियाज मे है, वे लोगो को बताये कि फायनैंश्यिल कार्पोरेशन से लोन लेकर छोटे उद्योग धन्धे शुरू करने से फायदा क्या है? लेाग चाहते है कि इस तरह का काम शुरू किया जाये। लेकिन लोगो को पता ही नही लगता कि कोई ऐसी कार्पोरेशन भी है जिससे लोन मिल सकता है और जिससे छोटे उद्योग धन्धों से वे पैदावार के साधन बढ़ा सकते हे। इसलिये मेरी यह गुजारिश है कि यहां फाईनैंशियल कार्पोरेशन से लोन लेने के लिये जो एप्लीकैंटस आते है, उनको लोन मिल जाता हैं वहां निचे के स्तर पर भी इस चीज का इन्तजाम होना चाहियें ताकि लेागों को इसका पता लग सके।

वित्त मंत्री (श्री राम सरन चन्द मित्तल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात हो आज अन–यूजअल है कि गवर्नमैंट की एक अन्डरटेकिंग को हमारे जनसंघ के भाई ने बड़ा एप्रीशियेट किया और उसकी बड़ी प्रशंसा की। (विघ्न) इसका मतलब यह है कि

इसको बड़े गौर से देखा गया मगर इसमे लूप–होल्ज मिलने की कोई गुंजाईश थी नही। हां, उसके बेटेज करना चाहिये था।(विघ्न)

चौधरी राम लाल वधवाः चूंकि मैने प्रंशसा कर दी इसलिए उसको भी ये क्रिटीसाईज करने लगे।(हंसी)

श्री राम सरन चन्द मित्तलः प्रशंसा फेस वैल्यू पर लेता हूं और चूंकि इन्होने इस काम के अन्दर अच्छाई देखी है, ईश्वर इनको शक्ति दे कि ये इसी लाईट मे हमारे और कामों को देखे(व्यवधान)। स्पीकर साहब, यह जो फाईनैंशियल कार्पोरेशन है यह प्योरली स्टेट अन्डर टेकिंग नही है यह सैन्ट्रल एक्ट के तहत के तहत कायम है और इस रिपोर्ट के अन्दर इसकी वर्किंग, कम्पोजीशजन, कांस्टीट्यूशन वगैरह हर चीज मिलेंगी। आप पेज सात पर देखें इसमें रिजर्व बैंक आफ इंडिया, इण्डस्ट्रियल बैंक, शिडयूल्ड बैंक, कार्पोरेटिव बैंक, करीब–करीब सब से रिप्रजेन्टेटिब्ज इसमें है। इसके मतलब यह है कि यह महज हरियाणा की तरफ से ही हो ऐसी बात नही हैं। इसका जो वर्क हैं उसका प्रोजीसर फिक्सड है और वह सेन्ट्रल एक्ट के तहत, सैन्ट्रल गवर्नमैंट की विशिज के मुताबिक काम होता है। इसको गवर्नमैट डिस्करिज नही करती बल्कि अन्करिज करती हैं, सहूलियतें देती है। एक बात और कही गई कि हर जगह इसका सैल होना चाहिए इसके लिए इण्डस्ट्री का डायरेक्टोरेट हर डिस्ट्रिक्ट लैवल पर और दूसरी जगह सैमीनार करता है ओर इसक बात के लिए ऐनकरेज करता है कि इण्डस्ट्रियलिस्ट्स जो सहूलियतें चाहे वह उन्हे दी

जाएगी। जहों तक फाईनेन्सल कार्पोरेशन का ताल्लूक है आप देखेगें कि इसकी कैपिटल शुरू मे एक करोड़ थी, उसमें पचास लाख रूपया और बढाया जिसमें सै पच्चीस लाख रूपया स्टेट गवर्नमैंट ने दिा है और पच्चीस लाख रूपया और मिलना हे। आप पेज 9 के आईटम 7 पर देखें लोन्ज आउडस्टैंडिंग एट द ी एण्ड आफ दी ईयर 9,93,94,983 है। अब आप ही बताईए कि जिसकी कैपीटल डेढ करोड़ की हो और ग्रास इन्कम फार दी ईयर देखे वह है 83,85,992 और नैट प्राफिट सबजैक्ट टू टेक्सैशन 27,22,835 हैं रिजर्वज एट दी एंड आफ दी ईयर 53,17,880 रूपए हैं। इन्ही फिगर से आप इनकी साउन्ड पोजीशन और साउन्ड वर्किंग का अन्दाजा लगा सकते है। अग एक तरफ तो कहा जाता है कि लिटिगंशन न हो, डिफालकेशन न हो और दूसरी तरफ कहा जाता है कि एप्लीकेशंज और इन्वाइट की जानी चाहिए, कम क्यो आती हैं। मै अपने दोस्तो को बताना चाहता हूं कि रूपए पैसे का जो मामला होता है वह काफी सोच विचार कर, एग्जामिन करके निपटाया जाता है, जो पेपर्ज आते है, उनको एग्जामिन किया जाता है। जो कर्जा मांगते है उनकी पोजीशन देखी जाती है कि वह साउन्ड है या नही। इतनी माईनूट चैकिंग होते हुए भी आप यह देखेगे कि कई लोगो ने डिफाल्ट किया है। लिटिगेशन वगैरह का अवाएड करने के लिए पहले ही देखा जाता है कि जो एप्लीकेंटस है उनकी पोजीशन साउंड है या नही है, जो काम वह करना चाहते है वह प्राफिटेबल है या नही, वर्केबल है, या नही। क्योकि पेसा बेकार नही जाना चाहिएण। जो फिगर्ज पेज 9 पर दी

गई है। वह शायद मैम्बर साहब, को समझने मे गल्ती हुई। 1971–72 मे 384 यूनिटस को लोन सैक्शन किया गया और 1972–73 मे 303 यूनिटस को लोन सैक्शन किया गया। मै उनको इन फिगर्ज के बारेम के बाद मे एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर यह कहा गया कि ट्रांसपोर्ट आपरेटर्ज की एप्लीकेशन कम आई। इसके बारे मे मै बताऊ कि ट्रांसपोर्ट ऐसी चीज नही है तो बढती ही चली जाए। जब लोग चह देखते है कि ट्रासपोट की कमी दूर हो गई है तो लोग कम एप्लाई करते है। ट्रांसपोर्ट के लिए तो आप देखेगे कि कार्पोरेशन ने खूब अनकरेज किया हैं इसमे साफ लिखा है कि इण्डस्ट्रीज को स्मालप इण्डस्ट्रीज को इस कार्पोरेशन ने खूब बनकरेज किया है। पेज 9 की पहली आईटम पर आप देखे कि उन यूनिटस को 1971–72 मे और 1972–73 मे जितना लोन सैक्शन किया गया है उसकी कोरसपोडिंग फिगर्ज भी दी हुई है। इसके निचे आईटम दो मे नेट सैक्शन ड्यूरिंग दी ईयर की फिगर्ज दी हुई है। इस रिपोर्ट मे बड़ी माइनूटली इनफरमेशन दी गई है। डिस्ट्रिक्ट वाईज, इण्डस्ट्री वईज, ईयर वाईज पूरी इन्फरमेशन दी गई है। हरेक चीज इसमे दी हुई है। श्री गौरी शंकर जी नक कहा कि काम सुस्ती से होता हैं मै यह बताना चाहता हूं कि चाहे कार्पोरेशन हो, चाहे इण्डस्ट्रीज डिर्पाटमैंट हो, इनकी तो कोशिश होती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग कर्जा लें। लेकिन यह जरूरी है कि पैसे की सेफगार्ड देखी जाए। कर्जा देत वक्ट कई चीजों को पैसा कि मैने पहले बताया है जांच करनी पड़ती है और इसी वजह

से कुछ देरी को सकती है। यह ठीक है कि जो बाते कही गई है उनका ध्यान रखा जाएगा–

चौधरी राम लाल वधवाः मेरी प्रंशसा पर राजी नही है यह अपनी प्रशंसा की मोहर लगायेगे।

श्री रामसरन चन्द मित्तलः इसकी प्रशंसा को आगे रखिए मै अपनी प्रशंसा को पीछे रख लेता हूं।(हंसी)

श्री अध्यक्षः सदन कल प्रातः काल साढे नौ बजे तक के लिए स्थिगित किया जाता है।

12.56 मध्यान्होपरान्त

(तत्पश्चात सभा 9.30 बजे पूर्वान्ह, शुक्रवार , 16 नवम्बर 1973 के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट

(कृपया डिबेट का पृष्ठ (4) 12 देखिए)

Primary Schools

***463. Ch. Dal Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state the District-wise number and names of the villages where new Primary Schools have been opened in the State during the years 1972-73 and 1973-74 separately?

शिक्षा मंत्री (चौधरी माडू सिंह मलिक):

वर्ष 1972–73 में खोले गये प्राइमरी स्कूल = 359

वर्ष 1973–74 में खोले गये प्राइमरी स्कूल = शून्य

जिलावार स्कूलों की संख्या तथा उन गांवों के नामों की सूची जहां वर्ष 1972–73 में नये प्राथमिक स्कूल खोले गये, संलग्न की जाती है।

1972–73 में खोले गये प्राईमरी स्कूलों की सूची

जिला गुड़गांवा	
क्रमांक	गांव का नाम
1	घसोला

2	फरीदपुर
3	चान्द नगर
4	मोहम्मद हेड़ी
5	कुलिया का
6	सकतपुर
7	मोहम्मदपुर
8	खरोंदा
9	टीकली कन्या
10	टठड कन्या
11	वीलाका
12	ब्रिज पुरा
13	हलीमण्डी कन्या
14	धीलावास
15	जटलाशाहपुर
16	मदन पुरी

17	सरोंई
18	चावला कलोनी बल्लभगढ़
19	शाहपुर खुर्द
20	नगला मातुका
21	रिवाज पुर
22	अगवान पुर
23	बादशाह पुर
24	गाजी पुर
25	पाखल
26	सैक्टर 15, फरीदाबाद
27	सैक्टर 9, फरीदाबाद
28	खेड़ी गुजरान
29	इन्दरा नगर
30	प्रतापगढ़ माजरा
31	पेहरक्का

32	बास
33	दोषपुर
34	मनीरगढी
35	डोकरा
36	बधौला कन्या
37	धतीर कन्या
38	चान्द हट कन्या
39	आया नगर
40	हरिजन बस्ती नं. 2 एन0आई0टी0 फरीदाबाद
41	नगला श्री नगर
42	नगला गवालन
43	सनहोली
44	सराय
45	सतवा गढ़ी मुस्ताबाद
46	सुरजन का नगला

47	होडल हरिजन बस्ती
48	धीहडका
49	आन्धका
50	खेडली ब्राहम्ण
51	अलब्राह्मण
52	छापरा
53	काकर खेड़ी
54	मरोड़ा
55	दोवाला
56	दरोन्ची
57	बड़ैलाकी
58	रणीयाका
59	बदोची
60	डालाबास
61	सुबाहेड़ी

62	मण्डकोला कन्या
63	ढाबी मलियाणा
64	पाडा
65	गुजरपुर
66	हमीरपुर
67	बाबन खेड़ी
68	महापुर
69	रणियाली
70	रोहिड़ा
71	मुलाका
72	बन्धहोली
73	बन्चारी कन्या
जिला अम्बाला	
1	भतमाजरा
2	दराजपुर

3	मच्छरपुरा
4	दरियापुर
5	महेशवरी
6	छोटी पावनी
7	नन्द गढ़
8	गढीमाजरा
9	मगरपुरा
10	कंजाला
11	फतेहपुर
12	दूधगढ़
13	दामला
14	चूतान
15	अलीपुर
16	दूधली
17	रतनगढ़

18	नगावां जागीर
19	परवालां
20	गधीलीकलां
21	पीरवाला
22	नवाशहर
23	मलिकपुर खादर
24	माजरी
25	नंगला
26	तेंगलपुर
27	कोटकलासिया (कन्या)
28	मिलक खास
29	ककड़ माजरा (कन्या)
30	भरौली (कन्या)
31	भुर्ड
32	अन्धेरी

33	कलाल माजरा
जिला भिवानी	
1	ढाणी फोगाट
2	हरिजन आश्रम दादरी
3	खेरपुरा
4	हरीपुरा
5	ढाणी नौरंगाबाद
6	ओबरा की ढाणी
7	शेरपुरा
8	खुदाना कन्या
9	नावां कन्या
10	शामपुरा कन्या
11	हरकड़ी कन्या
12	ढाणी गुजरांवा कन्या
जिला नारनौल	

1	मोहल्ला खरकड़ी नारनौल
2	मोहल्ला नहलापुर नारनौल
3	धरसू कन्या
4	गोंद कन्या
5	वाछोद कन्या
6	वकरीजा
7	ढाणी अटाली
8	ढाणी वास कीरा रोड
9	ढाणी कोजिन्दा
10	ढाणी गुजरवास
11	हुडीना कन्या
12	खापुर कन्या
13	डेरोली अहीर कन्या
14	अकबरपुर सिरोही कन्या
15	नांगल नूनिया कन्या

16	सिरोही वाहली कन्या
17	वारडा
18	डालन वास कन्या
19	माधोगढ़ कन्या
20	गागड़ वास कन्या
21	खोतों दंडा कन्या
22	बोरा वाली ढाणी कन्या
23	दुलोट अहीर कन्या
24	सुरजन वास कन्या
25	धनोन्दा कन्या
26	ढाणी भोजावास कन्या
27	नोताना कन्या
28	मुनिया खेड़ा कन्या
29	सिहोर कन्या
30	खेड़ी कन्या

31	खेराना कन्या
32	भटैडा
33	गोवीन्द पुरी
34	बदववानी खेडा
35	जेना बाद (कन्या)
36	ढाणी सन्दरोज (कन्या)
37	गोवीन्दपुर वास
38	ढालिया वास
39	जालीया वास
40	खेडी मोहल्ला
41	जय सिहं पुरखेडा
42	धरचना
43	गाजी गोपाल पुर
44	ढाणी जाटसाना
45	मड हठ रिवाडी

46	शादी पुर
47	सुनारिया
48	धनोडा
49	राजावास
50	चोकी
51	रतगन
52	निगानियावास
जिला हिसार	
1	लोहाखेड़ा
2	कमाल वाला
3	चन्द्र खुर्द
4	सलेम पुरी
5	बढई खेड़ा
6	ठरवी
7	रेलवे कालोनी नवीं बस्ती जाखल

8	कासिम पुर
9	कोडे मोडेवाला
10	शंकरपुर
11	पलुवाला
12	देसु खुर्द
13	लहरी वाला
14	ढाणी सुख चैन
15	ख्योवाली
16	वुडी मेडी
17	मुसली
18	किसान पुरा
19	खेड़ करीवाली
20	ढाणी ठाकरिया
21	मेहूं वाला (कन्या)
22	ढाणी मजरा कन्या

23	चाणक
24	काता खेड़ी
25	गदली
26	दरियापुर
27	ढाणी महताब सिंह
28	मलड
29	डिंगसरा (कन्या)
30	पालसर
31	नाईवाला
32	मिराण
33	टोड
34	खेरपुर
35	रोडन वाली
36	वालन वाली
जिला कुरूक्षेत्र	

1	दौलतपुर
2	सीकन्दरा
3	मसदनगर
4	दाली
5	छोटा बान्स
6	अधोणी
7	माधराव
8	डेरा आबराव
9	वजीदपुर
10	रतन डेरा
11	बाजकी
12	करोलमाजरा
13	मुगलमाजरा
14	सन्दपुरा
15	बकाना

16	यारी
17	वाधम
18	जडौला
19	धिसारपुर
20	अदौली
21	खेडा
22	रामपुर
23	बींड
24	रामनगर
25	सुलतानपुर
26	भालर
27	खिडकी
28	सरीकगढ़
29	नगल
30	सन्धोला

31	लखी बान्स
32	पौअली
33	मन्दुश
34	डाला माजरा
35	कसौर कालोनी
36	प्रभात
37	लैन्डर
38	अन्धली
39	मुगलपुरा
40	सुस्ला
41	डेरा गोबिन्दपुरा
42	गदला (कालू की मण्डी)
43	सुरमी
44	बीबी पर कलां
45	सिहाली

46	किला फारम
47	सोमला
48	गढ़ी लांगरी
49	हिलना
50	घराडसी
51	धडी रोडो
52	पबला
53	खेडी साकरा
54	लूवं लवाज
55	खानपुर
56	निकानपुर
57	सिंहपुरा
58	सिदरपुरा
59	डेरा चान्दी राम
60	झिन्जर पुर

जिला जींद	
1	धाणी राम गढ़
2	माण्डोखेड़ी
3	खुगा कोठी
4	बीबीपुर
5	मोलसरी खेड़ा
6	ललित खेड़ा
7	हथवाला
8	करसोला कन्या
9	वराहखुर्द कन्या
10	निढाणी कन्या
11	पीलूखेड़ा सम
12	निढाणा कन्या
13	दौरडसम
14	सिन्धवी खेड़ा (कन्या)

15	बैरों खेडा कन्या
16	सुन्दरपुर (ब्रहंकला) (कन्या)
17	धर्मगढ (कन्या)
18	मुसलाना
19	कन्डेला
20	रोज खेड़ा
21	उचाना खुर्द कन्या
22	खटकड़ कन्या
23	उदयपुर कन्या
24	दमाडा
25	धसो खुर्द कन्या
26	धसोकलां खुर्द
27	पीपलथा कन्या
28	ढाकल कन्या
29	दनौदा कलां कन्या

30	रतन पुरा कन्या
31	धनौरी कन्या
32	उझाना कन्या
33	डंडोली कन्या
जिला करनाल	
1	टपरियां
2	हन्सु माजरा
3	शेखपुरा
4	कालरां
5	गांधी नगर
6	दातानपुर
7	रामपुर कटाबाग
8	बागपति
9	खासपुर
10	बडनपुर

11	वीडमाजरा
12	वीर राय तिखाना
13	छाजपुर
14	बापोली
15	जटीपुर
16	नूरवाला
17	बिचपड़ी
18	कुराना
19	जारासी
20	माण्डी
21	कहन्सू
22	डेरासाईवाल
23	खण्डा खेड़ी
24	झीण्डा
25	गोमदा वाड़ा

26	खेड़ा (छपरा जागीर)
27	खेड़ा डरा
28	बयाणीं
29	रतन गढ़
30	लाल खेड़ा
31	उपली
32	भैन्सवाल
33	नीजामपुर
34	अजीजउलपुरा
35	भणी कलां
36	नया नाहड़ा
जिला रोहतक	
1	मदाना खुर्द
2	आजाद नगर
3	ढाणी सूनियान

4	तलाव
5	वाजीदपुर
6	हुमायुपुर
7	भगवानपुर
8	मोहल्ला पटवाड़ा (बहादुरगढ़)
9	तितोडिया
10	वोडिया
11	माजरा (वादली)
12	कासनी
13	खरैटी
14	खेड़ी खुमार
15	उखलधना (कन्या)
16	खखराना
17	बस्ती रैनकपुरा
18	दिल्ली गेट झझर

जिला सोनीपत	
1	किशोरा
2	मनीपुर
3	हरसाना खुर्द
4	देवीपुरा
5	मिरजापुर खेडी
6	शामड़ी कन्या